कल्पमेधा

धैर्य शक्ति है। धैर्य क्रियाशीलता का अभाव नहीं है, बल्कि यह उचित कार्य के सही समय पर सही ढंग से किए जाने की प्रतीक्षा मात्र है।
– फुल्टन जे शीन

महंगाई की मार

जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है, जिसकी आय कम होती है और संसाधनों का दायरा भी सीमित होता है। भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यकताओं पर बढ़ता खर्च इन परिवारों के बजट को बिगाड़ देता है। सरकार की ओर से बीते सोमवार को जारी महंगाई के आंकड़ों से साफ है कि आम लोगों को अब रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के लिए अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। खाद्य, ईंधन एवं विनिर्मित वस्तुओं के दाम बढ़ने से अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 9.92 फीसद, जबकि खुदरा महंगाई 4.82 फीसद पर पहुंच गई है। इससे पिछले माह जुलाई में यह क्रमशः 9.78 फीसद और 4.45 फीसद थी। जनवरी से लागू 2024 आधार वर्ष वाली नई श्रृंखला के बाद से अगस्त की खुदरा महंगाई का यह आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक है। यही नहीं, अगले माह से यूपीआइ के जरिए दो हजार रुपए से अधिक की राशि के भुगतान पर भी शुल्क लगेगा। सरकार की ओर से मंगलवार को तय की गईं शुल्क दरों में हालांकि आम लोगों के बीच यूपीआइ से लेन-देन को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन अन्य सरकारी एवं निजी सेवाओं के लिए भुगतान पर शुल्क देना होगा। यानी आम आदमी को अब महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए खुदरा महंगाई की दर अगस्त में क्रमशः 5.23 फीसद और 4.31 फीसद दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं के दाम ज्यादा बढ़े हैं, जहां लोगों की आय सीमित होती है। प्याज की महंगाई दर का जुलाई के 22.54 फीसद की तुलना में अगस्त में उछलकर 48.27 फीसद पर पहुंचना दर्शाता है कि प्याज आम लोगों की रसोई से गायब होने लगा है। यही हाल लहसुन और अदरक का भी है। ऐसे में निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों को अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। आय में वृद्धि अगर महंगाई की गति से कम हो, तो घरेलू बजट को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसमें दोराय नहीं कि अगले माह की शुरुआत में जब भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी, तब नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला करने में महंगाई का यह बढ़ा हुआ स्तर एक प्रमुख कारक साबित हो सकता है।

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि महंगाई का असर केवल घरेलू बजट तक सीमित नहीं रहता। जब लोगों की क्रय शक्ति घटती है, तो बाजार में मांग भी प्रभावित होती है। यानी इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि जब सरकार अक्सर यह दावा करती है कि महंगाई पर उसका नियंत्रण है, तो आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार कैसे बढ़ रहे हैं? जाहिर है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपाय करने चाहिए। खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुचारु रखने, जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा किसानों को उचित उत्पादन और भंडारण सुविधाएं देने की जरूरत है। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाना और आम लोगों की आय में स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करना भी जरूरी है। मगर इसके बजाय सरकार की ओर से यूपीआइ के जरिए दो हजार रुपए से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगाने के फैसले ने पहले से ही महंगाई से जूझ रहे आम लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है।

सुरक्षा का सवाल

दिल्ली-एनसीआर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर गंभीरता और संवेदनशीलता का अभाव साफ नजर आता है। गुरुग्राम में हाल ही में एक मोटरसाइकिल सवार युवती को कार से टक्कर मारकर घायल कर देने की घटना ने सड़क पर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कार चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवती का आरोप है कि कार में सवार लोगों ने पहले उसे रुकने का इशारा किया और बाद में उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हालांकि, आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इससे सुरक्षा एजंसियों की कार्यप्रणाली और सतर्कता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। जब सड़क पर खुलेआम महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हों, तो जाहिर है कि अपराधियों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं है।

दरअसल, पीड़ित युवती ने सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो जारी कर आरोपी के उन दावों पर सवाल उठाए हैं कि मोटरसाइकिल को टक्कर जानबूझकर नहीं मारी गई, बल्कि यह एक हादसा था। यह घटना सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वास्तविकता स्थिति की ओर ध्यान खींचती है। किसी महिला का वाहन चलाते समय पीछा करने, रास्ता रोकने या टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाना आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। अगर आज भी महिलाएं निर्भीक होकर सड़क पर न चल सकें, तो यह शासन-प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। सवाल यह भी है कि आखिर अपराधियों के भीतर कानून का खौफ क्यों नजर नहीं आता है? जाहिर है, इसके लिए निश्चित रूप से कानून प्रवर्तन एजंसियों की लापरवाही जिम्मेदार है। जब तक पुलिस तंत्र में संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाएगा। कहने को सरकार की ओर से सुरक्षा एजंसियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब कोई आपराधिक घटना होती है, तो जमीनी स्तर पर इसके कोई प्रभावी नतीजे सामने नहीं आते हैं।

जन संघर्ष और बदलाव की राह

भारत ने आजादी से लेकर अब तक कई आंदोलन देखे हैं। देश के लोकतंत्र में इनकी खास भूमिका रही है। हर संघर्ष का निष्कर्ष यही रहा कि इससे अवाम की आवाज मजबूत हुई है।

सुभाष चंद्र शर्मा

भारत में आंदोलनों की एक बड़ी पृष्ठभूमि है। आजादी से लेकर अब तक देश ने कई आंदोलनों को देखा है। एक बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण की अगुआई में हुआ। वहीं मंडल आयोग को लेकर हुए छात्र आंदोलन को कौन भूल सकता है। वर्ष 1987 में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन और फिर जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे की अगुआई में हुआ आंदोलन अविस्मरणीय है। इन आंदोलनों से लोग जुड़ते चले गए थे। जय प्रकाश नारायण की अगुआई में हुए आंदोलन का परिणाम यह रहा कि जनता ने सत्ता पलट दी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने वर्ष 1987 को भारतीय किसान यूनियन के झंडे तले किसानों की कर्जामाफी, बिजली के दाम, धान-गेहूं और गन्ने के मूल्य के लिए मेरठ में 25 दिनों तक धरना देकर किसानों को उनकी शक्ति का एहसास कराया। उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की ताकत दी। मगर तब कई लोगों को यह लगता था कि इस आंदोलन से किसानों को कोई खास लाभ नहीं मिला। जबकि ऐसा नहीं था।

किसान आंदोलन पर सवाल उठाने वाले लोग भूल गए कि इससे पूर्व किसानों का अपनी जायज मांगों को लेकर एकजुट होना ही बड़ी बात थी। तब मांग मनवाने के लिए न तो कोई खास संगठन था और न ही अपनी आवाज बुलंद करने की उनमें हिम्मत थी। सरकार ने उनकी फसलों के जो दाम तय कर दिए, तो उसका विरोध जताने की ताकत भी उनमें नहीं थी। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो दरें तय कर दीं, तो किसान उसी दाम में गन्ना बेच देते थे। इतना ही नहीं, तब मिल मालिक अपनी सुविधा अनुसार किसानों को भुगतान करते थे और कहीं कोई विरोध नहीं होता था। उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से आम किसान इसलिए जुड़ा, क्योंकि उनकी भाषा बोलने वाला, उनकी आर्थिक खुशहाली के लिए सरकार की आंखों में आंखें डाल कर उसे ललकारने वाला नेता उन्हीं के बीच से आया था, जो उनकी दुख-तकलीफ को गहराई से समझता था। सच तो यही है कि किसानों को उनकी समस्याओं को हल करने की शक्ति उनमें ही नजर आई। नतीजा यह कि उत्तर प्रदेश में लाखों किसान उनसे जुड़ गए। देखते ही देखते टिकैत प्रभावशाली किसान नेता बन गए। इस संगठन की ताकत के आगे झुकते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली में किसानों की ऐतिहासिक सभा में जाना पड़ा, जहां बड़ी संख्या में किसान जुटे थे।

अधिकारियों के सामने जो किसान कभी गुहार लगाया करते थे। वही अब अपने वाजिब हकों के लिए आगे आने लगे। टिकैत ने संगठन के बल पर किसानों में एक नई जान फूंकी। तब कोई अधिकारी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। कोई करता भी था, तो किसान उसके दफ्तर में किसान यूनियन जिंदाबाद का नारा लगाने लगाते। गन्ने का भुगतान चौदह दिन में नहीं देने पर वे ब्याज सहित भुगतान की मांग को लेकर मिल मालिकों को घेरने लगे। देखते ही देखते सिसौली किसानों का मुख्यालय बन गया। हर

महीने की 17 तारीख को वहां किसानों की समस्याओं पर बैठक होने लगी। अब भी किसान समय-समय पर कर्जामाफी, बिजली की कम दरों, धान, गेहूं और गन्ने के दाम के लिए मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं। इस तरह देश में हर आंदोलन से जन-संघर्ष मजबूत होता गया। सत्ता को हर

> कुछ समय पहले नई पीढ़ी का आंदोलन भी कोई अलग नहीं था। नीट और अन्य परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने पर देश भर के युवाओं में रोष था। नतीजा एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इसमें वे युवक भी जुड़ गए जो बरोजगार थे। इससे यह आंदोलन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, देश के अन्य राज्यों में भी फैल गया। बीस जुलाई को जंतर मंतर पर बैठे युवाओं पर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उसकी देश भर में निंदा की गई। जेन जी में एकजुटता अचानक नहीं हुई। युवाओं में गुस्सा धीरे-धीर बढ़ रहा था। जब उन्हें मंच मिला, तो वे सड़क पर उतर आए। इस आंदोलन की सफलता यह रही कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

बार उनकी बात सुननी पड़ी। लगभग यही स्थिति अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल विधेयक को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में चले आंदोलन में दिखाई दी। देश का आम नागरिक भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त था। मगर लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठा पा रहे थे। जब इस मुद्दे पर उनके बीच उन्हीं की भाषा बोलने और डंके की चोट पर बात रखने वाले अन्ना हजारे उनके सामने आए, तो लोग उनसे जुड़ते चले गए। देखते ही देखते देश भर में उनकी एक आवाज पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। अन्ना हजारे बारह दिन आमरण अनशन पर रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में डेरा डाले रहे। देश के अनेक शहरों में धरने-प्रदर्शन हुए। आखिर सरकार को झुकना पड़ा।

कुछ समय पहले नई पीढ़ी का आंदोलन भी कोई अलग नहीं था। नीट और अन्य परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने पर देश भर के युवाओं में रोष था। नतीजा एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इसमें वे युवक भी जुड़ गए जो रोजी-रोटी के लिए भटक रहे थे। इससे यह आंदोलन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, देश के अन्य राज्यों में भी फैल गया। बीस जुलाई को जंतर मंतर पर बैठे युवाओं पर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उसकी देश भर में निंदा की गई। अनेक हस्तियां उन्हें समर्थन देने वहां पहुंचीं। जेन जी में एकजुटता अचानक नहीं हुई। युवाओं में किस कदर गुस्सा है, यह पिछले दिनों आंदोलन के दौरान सभी ने देखा।

जिस प्रकार भारतीय किसान यूनियन की प्रतीक हरी टोपी लगा कर किसान सरकारी दफ्तरों में जाने लगे थे, उसी प्रकार अन्ना हजारे की पहचान सफेद टोपी पहन कर लोग अपने काम के लिए दफ्तरों में जाने लगे। वहां यदि किसी ने काम के एवज में उनसे पैसे की बात की, तो तुरंत आवाज उठाई जाती। इसके बाद जेन जी की आवाज भी सुनने के लिए सरकार मजबूर हुई। उनकी मांगें मानी गईं। एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी दुर्गा भाभी की एक बात याद आती है। एक बार उन्होंने कहा था कि हमें असली आजादी अभी नहीं मिली है। पंद्रह अगस्त 1947 को केवल सत्ता परिवर्तन हुआ। अंग्रेज चले गए और हमारे लोग सत्ता पर काबिज हो गए। उन्होंने यह भी कहा था कि असली बात तो यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने कुर्बानियां दीं, उस इतिहास से हमारी युवा पीढ़ी को अवगत ही नहीं कराया गया। युवाओं को पता है क आजादी के लिए देश के लोगों ने किस तरह अपना लहू बहाया और कुर्बानियां दीं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगवती चरण वोरा सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम योद्धाओं ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। आज का यथार्थ यही है कि किसान और मजदूरों से लेकर दाल-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक एकजुटता न होने से कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में कोई नेता उनकी मांग उठाने के लिए आह्वान करता है, तो जनता उसके पीछे खड़ी हो जाती है। यह वही जनता थी, जो आजादी की लड़ाई में नेताओं के साथ खड़ी थी। जिन्होंने लाठियां और गोलियां खाईं। अब भविष्य में रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य समस्याओं के समाधान का दावा करने वाला कोई नेता उनके बीच आएगा, तो उसके एक आह्वान पर फिर से नागरिक उसके साथ खड़े दिखेंगे। लोकतंत्र को ताकत आंदोलन से भी मिलती है।

आत्ममूल्य का आकलन

दुनिया मेरे आगे

विजय सिंह अधिकारी

जीवन में अधिक मूल्यवान क्या है- दूसरों की सराहना या बुराई, किसी से की गई तुलना या फिर दूसरों की स्वीकृति? इस प्रश्न को जब भी समझने की कोशिश की जाती है, जीवन और अधिक जटिल महसूस होता है। उम्र बढ़ती रही, अनुभव जुड़ते रहे, परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन एक प्रश्न भीतर कहीं स्थिर रहता है- क्या मनुष्य अपनी असली कीमत पहचानने में कभी सफल हो पाया है? बचपन में हमें बताया जाता है कि अच्छा वही है, जिसे सब पसंद करें। धीरे-धीरे हम यह भूलने लगते हैं कि मनुष्य का मूल्य किसी बाहरी पैमाने से निर्धारित नहीं होता। समाज हमें नाम देता है, पद देता है, पहचान देता है, लेकिन आत्ममूल्य का आकलन हमें स्वयं करना पड़ता है।

एक मूल्यवान वृक्ष अपने होने का प्रमाण किसी से नहीं मांगता। धूप उसे तपाती है, वर्षा भिगोती है, आंधियां उसकी शाखाएं झकझोरती हैं और तूफान उसकी जड़ों की परीक्षा लेते हैं। फिर भी वह मिट्टी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ता। वृक्ष हमें एक और गहरी बात सिखाता है। उसकी जड़ें दिखाई नहीं देतीं, लेकिन वही उसे खड़ा रखती हैं। मनुष्य के जीवन में भी चरित्र, मूल्य, आत्मविश्वास और विवेक ऐसी ही अदृश्य जड़ें हैं। हम अक्सर पद, प्रतिष्ठा, धन और उपलब्धियों को देखकर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, उसकी जड़ों को देखने का प्रयास नहीं करते, लेकिन तूफान आने पर शाखाओं की चमक नहीं, जड़ों की गहराई काम आती है।

> मानव जीवन की कीमत न तालियों से बढ़ती है, न तिरस्कार से घटती है। मूल्य उस मौन में जन्म लेता है, जहां मनुष्य अकेला अंतर्मन के सामने खड़ा होकर पूछ सकता है- क्या मैं अपने जीवन के प्रति ईमानदार हूं? क्या मेरी उपयोगिता केवल मेरे लिए है, या मेरे होने से किसी और का जीवन भी थोड़ा बेहतर होता है?

मनुष्य की स्थिति इसके ठीक उलट है। वह उपयोगी होने से अधिक उपयोगी दिखाई देने की चिंता करने लगता है। सस्ती लोकप्रियता, क्षणिक तालियां, दूसरों की प्रशंसा और सामाजिक स्वीकृति धीरे-धीरे उसकी आत्मा की कसौटी बन जाती है। वह अपने अस्तित्व का मूल्यांकन अपने अंतर्मन से नहीं, दूसरों की आंखों से करने लगता है। यह स्थिति और भयावह तब होती है, जब तुलना जीवन का स्थायी स्वभाव बन जाती है। कोई हमसे अधिक सफल है, किसी के पास अधिक धन है, किसी की लोकप्रियता अधिक है, किसी का पद ऊंचा है और हम अपने जीवन को दूसरों की उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में देखने लगते हैं।

तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह हमें हमारी अपनी यात्रा से बेदखल कर देती है। हम यह भूल जाते हैं कि हरेक जीवन की परिस्थितियां, संघर्ष और मंजिलें अलग होती हैं। भीड़ भी इसी मानसिकता का एक विराट रूप है। दुर्घटना हो, अपराध हो या अचानक कोई संकट सामने आ जाए- अक्सर मनुष्य का पहला स्वभाव अपने को सुरक्षित करना होता है। कई बार कुछ अपराधियों के सामने सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ता। हर व्यक्ति की आंखें किसी दूसरे चेहरे में साहस तलाशती रहती हैं। सब प्रतीक्षा करते हैं कि कोई और पहल करे और इसी प्रतीक्षा में सामूहिक शक्ति निष्प्राण हो जाती है। यहां संख्या और शक्ति के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। भीड़ बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका प्रत्येक सदस्य अगर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल दे, तो वह शक्ति भ्रम मात्र रह जाती है। कभी-कभी एक व्यक्ति का स्पष्ट निर्णय सैकड़ों निष्क्रिय लोगों की सामूहिक उपस्थिति से अधिक प्रभावशाली होता है।

आत्मपहचान की पहली सीढ़ी यह जानना है कि मैं कौन हूं और किस क्षण मुझे भीड़ से अलग खड़ा होना है। आत्मपहचान अहंकार नहीं, वह अपने सामर्थ्य और अपनी सीमाओं दोनों को स्वीकार करने की विनम्र क्षमता है। स्वयं को पहचानने का अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानें, बल्कि यह समझना है कि हमारी अपनी भूमिका, जिम्मेदारी क्या है और हमारे जीवन का अर्थ दूसरों की स्वीकृति से कितना स्वतंत्र है। वास्तविक सुख भी बाहर की प्रशंसा से नहीं, भीतर की शांति से फूटता है। मनुष्य का व्यवहार, उसकी वाणी और उसकी उपस्थिति तभी दूसरों को सुख दे सकती है, जब उसके भीतर लगातार चल रहा संघर्ष कुछ शांत हुआ हो। प्रकृति का सबसे बड़ा सौंदर्य शायद यही है कि वह अपने होने को सिद्ध नहीं करती, वह केवल होती है और जीवन को प्रभावित करती है। मनुष्य के लिए भी शायद यही सबसे बड़ी सीख है।

हर समय स्वयं को सिद्ध करने की बेचैनी आखिर हमारे भीतर को थका देती है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, जिसमें अंतिम रेखा पर पहुंचकर कोई निर्णायक हमें बताए कि हम कितने सफल रहे। कई बार सबसे बड़ी उपलब्धि वह होती है, जब मनुष्य अपने भीतर यह स्वीकार कर पाता है कि उसे हर व्यक्ति से आगे निकलना आवश्यक नहीं है। गौतम बुद्ध ने राजसी वैभव के पार सत्य की तलाश की। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना अपने समय की जड़ताओं को सीधी चुनौती दी। इन सबकी शक्ति केवल उनके विचारों में ही नहीं थी, बल्कि वे अपने विचारों के साथ खड़े रहने का साहस भी रखते थे।

मानव जीवन की असली कीमत न तालियों से बढ़ती है, न तिरस्कार से घटती है। मूल्य उस मौन में जन्म लेता है, जहां मनुष्य अकेला अपने अंतर्मन के सामने खड़ा होकर स्वयं से पूछ सकता है- क्या मैं अपने जीवन के प्रति ईमानदार हूं? क्या मेरी उपयोगिता केवल मेरे लिए है, या मेरे होने से किसी और का जीवन भी थोड़ा बेहतर होता है? सबसे कठिन विजय यह है कि संसार की बदलती राय के बीच भी मनुष्य अपनी ही नजरों में गिरने से बचा रहे। तभी उम्र केवल बढ़ती नहीं, अर्थवान होती है। तभी जीवन केवल बीतता नहीं, बल्कि दूसरों पर अपनी सार्थक छाप छोड़ जाता है।

तकनीक के जोखिम

'तकनीक पर नियंत्रण' (संपादकीय, 14 सितंबर) पढ़ा। कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कृत्रिम मेधा यानी एआइ वैश्विक रोजगार बाजार और मानव अस्तित्व दोनों के लिए जोखिम पैदा करती है। यह नियमित कार्यों, लेखन और कोडिंग को मनुष्यों की तुलना में अधिक तेजी से कर सकती है। कई कंपनियां पैसे बचाने के लिए कर्मचारियों की जगह साफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं। एआइ निर्मित रोबोट सेनाएं ऐसे हथियार बना सकती हैं, जो लक्ष्य चुन कर हमला कर सकते हैं। मगर अब दावा किया जा रहा है कि इससे मानव अस्तित्व के लिए भी संकट पैदा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख की चेतावनी के कुछ दिनों बाद अनुसंधानकर्ता जैकब काक्सन ने कहा कि ये जल्द ही ऐसे 'सुपरह्यूमन सिस्टम' बन जाएंगे, जो कहीं भी सेंध लगा सकते हैं। रातों-रात किसी भी क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं और संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे में एआइ पर मानव का नियंत्रण होना अनिवार्य है, ताकि किसी भी तरह के खतरे की आशंका को समाप्त किया जा सके।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

बहुआयामी समाधान

'नशे के जाल में उलझती युवा पीढ़ी' (आलेख, 11 सितंबर) पढ़ा। नशे को केवल कानून-व्यवस्था या व्यक्तिगत समस्या मानना उचित नहीं होगा। इसके पीछे तनाव, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, निराशा, अकेलापन और भविष्य की अनिश्चितता जैसे कारण भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। नशामुक्ति केंद्रों के साथ योग केंद्र स्थापित किए जाएं, जैसा पुराने समय में अखाड़ों की परंपरा हुआ करती थी। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम इनके संचालन की जिम्मेदारी संभालें। योग, प्राणायाम और ध्यान दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। इससे विद्यालयों और महाविद्यालयों को भी जोड़ा जाए। इससे सरकारी सहायता केवल सहारा न रह कर स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनेगी। नशामुक्ति की लड़ाई में केवल नशा छुड़ाना पर्याप्त नहीं, निराशा को आशा, तनाव को संतुलन और बेरोजगारी को रोजगार में बदलना होगा। यही कारगर उपाय हो सकता है।

– ओपी चौधरी, रतलाम, मप्र

समझ का प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया मंचों के सुरक्षित इस्तेमाल से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में इस बात पर विचार करने की मांग की गई है कि नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया खाते खोलने की अनुमति देने से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति होनी चाहिए। यह पहल इसलिए अहम है, क्योंकि सोशल मीडिया मंचों पर वर्तमान आयु-व्यवस्था और भारत में नाबालिग की कानूनी स्थिति के बीच सवाल खड़ा होता है। कई सोशल मीडिया मंच तेरह वर्ष की आयु में खाते की अनुमति देते हैं, जबकि कानून में अठारह वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नाबालिग माना जाता है। खाता बनाते समय उपयोगकर्ता को नियम और शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि इतनी कम उम्र में बच्चा जिन शर्तों को स्वीकार कर रहा है, उनकी कानूनी और व्यावहारिक समझ उसके पास वास्तव में कितनी है।

– कांतिलाल मांडोत, लखनऊ

सांसों पर संकट

वायु प्रदूषण पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की अधिकांश आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। यह मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के लिए चिंताजनक है। वाहनों से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य, कचरा एवं पराली जलाना वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। प्रदूषित वायु के कारण श्वसन संबंधी रोगों के साथ-साथ हृदय एवं फेफड़ों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार तथा स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करना चाहिए। नागरिकों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर प्रदूषण रोकने में सहयोग करना चाहिए। स्वच्छ वायु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए वायु प्रदूषण की रोकथाम में हर नागरिक की भूमिका अहम है।

– कृष्ण कुमार मौर्य, अंबेडकर नगर, उप्र

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

असम में एक सींग वाले 3,260 गैंडे हैं : हिमंत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में एक सींग वाले 3,260 गैंडे हैं और दुनियाभर में जितने गैंडे हैं, उनमें से 80 फीसद असम में पाए जाते हैं। सरमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य में 2025 में शिकार की कोई भी घटना दर्ज न होने के साथ, नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार गैंडों की संख्या 3,260 पाई गई है। सरमा ने कहा कि दुनिया में एक सींग वाले लगभग 4,075 गैंडे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक दिलचस्प तथ्यः दुनियाभर में एक सींग वाले जितने गैंडे हैं, उनमें से 80 फीसद असम में पाए जाते हैं। हमारा राज्य इस समय लुप्तप्राय प्रजाति के लिए एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षित आश्रय स्थल है, और हम उनकी रक्षा करने तथा उनके आवास का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में 1900 की शुरुआत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 100 के आसपास थी। (ब्यूरो)

स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का तैयार होगा डाटा, चिकित्सा पर्यटन से जुड़ेगा

राकेश शर्मा

आयुष पद्धति से देश में चल रहे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में उपचार करवाने आ रहे विदेशी मेहमानों को डाटा तैयार होगा। इन केंद्रों को आने वाले दिनों में चिकित्सा पर्यटन से जोड़ने की तैयारी चल रही है।

मौजूदा समय में हर साल हजारों की संख्या में विदेशी मेहमान पर्यटक के तौर पर उपचार, पुनर्वास चिकित्सा सहित अन्य की सुविधा लेने आते हैं। लेकिन ऐसे उपचार की जानकारी आयुष मंत्रालय के पास नहीं होती है। इसे देखते हुए इन केंद्रों को छह माह के भीतर विदेशी नागरिकों से जुड़ी जानकारी मंत्रालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे। इसमें यह भी दर्ज किया जाएगा कि विदेशी नागरिकों ने किस तरह की आयुष सेवाएं लीं और उपचार के बाद उन्हें कितना लाभ मिला।

आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव का कहना है कि 150 देशों में आयुष पद्धतियों से उपचार की मांग बढ़ी है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक देश में चल रहे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का रुख कर रहे हैं। इनमें से कई लोग पर्यटन वीजा पर भारत आते हैं। ऐसे में मंत्रालय अब इस बात का व्यवस्थित रिकार्ड तैयार करना चाहता है कि विदेशी नागरिक किन आयुष सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है और इन सेवाओं में किस तरह का सुधार किया जा सकता है। इस डाटा का इस्तेमाल आयुष चिकित्सा को चिकित्सा पर्यटन से जोड़ने की रणनीति तैयार करने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े एक बैठक में 127 देशों के प्रतिनिधियों ने आयुष चिकित्सा से जुड़ी जानकारी, शिक्षा और ज्ञान साझा करने की आवश्यकता जताई थी। भारत अब इस दिशा में एक व्यापक रोडमैप तैयार कर रहा है। आयुष मंत्रालय पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में देशों के बीच शोध, प्रमाण

देश में हर साल आते हैं लाखों विदेशी मेहमान। पर्यटक वीजा पर करवाते हैं आयुष पद्धति से उपचार।

केंद्रों को छह माह के भीतर विदेशी नागरिकों से जुड़ी जानकारी मंत्रालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे।

आधारित अध्ययन, शैक्षणिक आदान-प्रदान और ज्ञान साझा करने पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्रिक्स देशों के बीच हुई चर्चा में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ समूह बनाने और उसे संस्थागत रूप देने की दिशा में भी काम किया गया है। इसके माध्यम से शोध को बढ़ावा देने और चिकित्सा पद्धतियों की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया जाएगा।

मंत्री का दावा है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में पारंपरिक तरीके से उपचार कर रहे वैद्यों और विशेषज्ञों की पहचान पर काम चल रहा है। देश के कई क्षेत्रों में ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उपचार करते हैं और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। मंत्रालय इन पारंपरिक ज्ञान और उपचार पद्धतियों को शोध और वैज्ञानिक प्रमाण के स्तर पर परखकर उनकी गुणवत्ता बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है।

राजस्थान : निकाय चुनाव में भाजपा की बढ़ी ताकत, निर्दलियों ने दिखाया दम

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बेहतर प्रदर्शन से सत्तारूढ़ दल में उत्साह है। हालांकि, परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस ने भी कई महत्त्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की है जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कई स्थानों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पारंपरिक मुकाबले को प्रभावित करने वाली ताकत बनकर उभरे हैं।

राज्य के 309 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव में मतों की गिनती सोमवार को हुई। भाजपा ने कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा जैसे प्रमुख शहरों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने बीकानेर, अजमेर, पाली, झालावाड़ और टोंक में महत्त्वपूर्ण बढ़त बनाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर समेत कई अन्य स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ने का काम किया। दिसंबर 2023 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार के लिए ये निकाय चुनाव पहली बड़ी प्रदेशव्यापी चुनावी परीक्षा थे।

भाजपा राज्यभर में कांग्रेस से आगे रही और 10 नगर निगमों में से चार जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा में सत्तारूढ़ दल को स्पष्ट बहुमत मिला। मुख्यमंत्री शर्मा ने नतीजों को अपनी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछले ढाई वर्षों से अधिक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उस पर राजस्थान की जनता ने नगरीय

हालांकि, परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस ने भी कई महत्त्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की है जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कई स्थानों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पारंपरिक मुकाबले को प्रभावित करने वाली ताकत बनकर उभरे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर समेत कई अन्य स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ने का काम किया।

चुनावों में भाजपा को भारी समर्थन देकर मुहर लगाई है। शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री के विकसित भारत-विकसित राजस्थान के संकल्प को जनता ने स्वीकार किया है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी नतीजों को पार्टी और सरकार के प्रति जनता का समर्थन बताया।

उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा ने लगभग ढाई से तीन गुना बेहतर प्रदर्शन किया। राठौड़ के मुताबिक, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भाजपा को जनता का व्यापक समर्थन मिला। वहीं, कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नतीजों से पता चलता है कि कांग्रेस ने शहरी मतदाताओं के बीच अपना प्रभाव बढ़ाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है और शहरी मतदाताओं के बीच अपना बढ़ता प्रभाव साबित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अजमेर और बीकानेर में भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का निर्वाचन क्षेत्र अजमेर है जबकि बीकानेर से लोकसभा सदस्य अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र भरतपुर के नतीजों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि भाजपा भरतपुर में जीत हासिल नहीं कर सकी, जबकि मुख्यमंत्री ने वहां और अन्य स्थानों पर रोड शो किए थे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भरतपुर, पाली और अन्य क्षेत्रों के नतीजों का हवाला देते हुए भाजपा के शहरी इलाकों में भारी जनादेश के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई है जिन्हें भाजपा अपना गढ़ मानती थी। महापौर और अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों निर्दलीय पार्षदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने बारां नगर परिषद में बहुमत हासिल किया, जबकि माकपा ने बीकानेर जिले की नोखा नगरपालिका में जीत दर्ज की। राजनीतिक विश्लेषक पुनीत शर्मा ने कहा कि नतीजे भाजपा के लिए चेतावनी हैं कि अगर सत्तारूढ़ दल को अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता बनाए रखनी है तो उसे और मेहनत करनी होगी। (ए)

प्रदर्शनी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित अंतरिक्ष और अन्य शोध गतिविधियों की प्रदर्शनी का दौरा किया।

युवाओं को साइबर जोखिमों में फंसा रहा है स्मार्ट फोन

पंकज रोहिला

देशभर में 74 से 75 करोड़ फोन का इस्तेमाल हो रहा है। इन फोन की पहुंच छोटे-छोटे बच्चों तक भी बढ़ी है और बच्चों में इस फोन के जोखिम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चे तरह- तरह में मोबाइल एप्लीकेशन और खेलों के आदि हो रहे है। फोन की मदद से ही बच्चों का पीछा भी हो रहा है। यह चिंता संसद की एक संसदीय समिति ने जाहिर की है। युवाओं व युवतियों को ऐसे जोखिम से बचाने के लिए समिति ने केंद्र सरकार से एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार करने की सिफारिश की है ताकि बच्चों साइबर अपराध शिकार होने से बचाया जा सकेगा।

इन अपराधों के प्रति सचेत करने के लिए विद्यालयों में आयु उपयुक्त साइबर स्वच्छता और साइबर अधिकारों से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। समिति ने संपूर्ण प्रक्रिया को एक जैविक स्वरूप में इस प्रकार तैयार करने के आदेश दिए कि वह साइबर क्षेत्र के तेजी से फैलते दायरे के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की ओर से बच्चों और किशोरों को प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभावों से बचाने के लिए सोशल मीडिया में भी आयु - उपयुक्त नियमों और तय सीमा तक प्रयोग की सीमाएं तय करें। युवा उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वस्थ्य की सुरक्षा के लिए सेफ्टी बाय डिजाइन मानकों को लागू करें।

केंद्र सरकार जल्द शुरू करेगी बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम। संसदीय समिति ने की है सिफारिश।

वर्ष 2017 से 2022 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों में 239 फीसद और बच्चों के मामलों में कई गुना तक बढ़ोतरी हुई है।

समिति ने बहुस्तीय हस्तक्षेपों से भारत की साइबर सुरक्षा संरचन को मजबूत किए जाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले आशा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की सहभागिता जरूरी है। इन्हें सरकार साइबर सुरक्षा के दूत के तौर पर प्रशिक्षित करें। समिति ने चिंता जताई है कि स्मार्ट फोन व सोशल मीडिया के अधिक उपयोग की वजह से साइबर स्टाकिंग, सेक्सटार्शन, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, बाल यौन शोषण और बिना सहमति के अंतरंग चित्र - वीडियो साझा करने जैसे अपराधों में स्मार्ट फोन आने के बाद बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2017 से 2022 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा किया गया है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों में 239 फीसद और बच्चों के मामलों में कई गुना तक बढ़ोतरी हुई है।

समिति ने कहा है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज शिकायतों की बढ़ती संख्या इस मामले में एक जागरूकता की ओर इशारा करती है लेकिन वहीं दूसरी ओर विशेषकर किशोरियों, ग्रामीण महिलाओं और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भय, सामाजिक कलंक और समिति डिजिटल साक्षरता, कम रिपोर्टिंग होने का कारण बना हुआ है। दावा किया गया है कि जेनरेटिव एआइ, मशीन प्रशिक्षण और 5 जी जैसी नई तकनीक ने जीवन को सरल बनाने के साथ शोषण के नए रास्ते खोल दिए हैं। इस वजह से जिम्मेदारी तय कर पाना भी कठिन हो रहा है। ये सिफारिश महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति की ओर से दी गई है। समिति को साइबर अपराध और महिलाओं की साइबर सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित किया गया था।

यूरिया से हवा में बढ़ रहे महीन कण

एक अध्ययन के मुताबिक, उर्वरकों से होने वाला प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर ज्यादा

सुशील राघव

वायु प्रदूषण की चर्चा होते ही आमतौर पर वाहनों के धुएं, ईंट भट्ठों, औद्योगिक इकाइयों और पराली जलाने को इसके प्रमुख कारणों के तौर पर देखा जाता है। लेकिन खेती में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक भी हवा में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। भारत-गंगा के मैदानी इलाके और हिमालय की तलहटी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला यूरिया मिट्टी से अमोनिया गैस के उत्सर्जन का कारण बनता है। यह गैस वातावरण में मौजूद दूसरी प्रदूषक गैसों के साथ प्रतिक्रिया करके पीएम 2.5 के बेहद महीन कणों को जन्म देती है।

एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आइसीआइ एमओडी) के एक अध्ययन के मुताबिक उर्वरकों से होने वाला यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर बड़े क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। खासकर उन इलाकों में जहां पहले से ही वाहनों, उद्योगों, बिजली संयंत्रों और कृषि अवशेष जलाने से निकलने वाले प्रदूषक मौजूद हैं। अध्ययन में देश के उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में नाइट्रोजन के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई है। इन राज्यों में किसान कई बार

एक अध्ययन के मुताबिक मिट्टी से निकलने वाली अमोनिया बना रही पीएम 2.5 कण। अध्ययन में देश के उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में नाइट्रोजन के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई है।

वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीति में सिर्फ वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन के संतुलित इस्तेमाल, उर्वरक की सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल तथा नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने पर भी ध्यान देना जरूरी।

राष्ट्रीय स्तर पर सुझाए गए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम के अनुपात की तुलना में करीब दोगुना नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं।

वायुमंडलीय माडलिंग के एक आकलन के मुताबिक नाइट्रोजन उर्वरकों से जुड़े उत्सर्जन के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्र के अलग-अलग राज्यों में पीएम 2.5 का सालाना औसत प्रभाव करीब 1.4 से 3.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक हो सकता है। फसल चक्र में जब उर्वरकों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तब इसका मौसमी प्रभाव 7.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषज्ञों की चिंता सिर्फ मौजूदा प्रदूषण तक सीमित नहीं है। अनुमान है कि 2035 तक अगर पराली जलाने में कमी आती है और फसल अवशेष प्रबंधन की बेहतर तकनीकें अपनाई जाती हैं, तब भी नाइट्रोजन उर्वरकों से होने वाला पीएम 2.5 प्रदूषण वायु गुणवत्ता में होने वाले संभावित सुधार को कुछ हद तक कम कर सकता है। इसलिए वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीति में सिर्फ वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा।

कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन के संतुलित इस्तेमाल, उर्वरक की सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल तथा नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। मिट्टी की सेहत सुधारने के साथ यह कदम हवा की गुणवत्ता बेहतर करने में भी मददगार हो सकता है।

अध्ययन के मुताबिक खेत में यूरिया डालने के बाद मिट्टी में मौजूद एंजाइम हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया के जरिए यूरिया को अमोनियम और कार्बन डाइआक्साइड में बदलते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है। क्षारीय वातावरण और गर्म मौसम में मिट्टी में मौजूद अमोनियम का एक हिस्सा अमोनिया गैस में बदलकर वातावरण में चला जाता है।

केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर 5,100 करोड़ रुपए कमाए

जनसत्ता ब्यूरो

सरकारी कार्यालयों में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत पांच वर्षों में कबाड़ बेचकर 5,100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त किया गया है। केंद्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन अभियानों का उद्देश्य सभी सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना है।

कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2021 से इस अभियान के पांच सालाना संस्करणों और सचिवालय में सुधारों की मासिक निगरानी (जुलाई 2026 तक) के जरिए 24.20 लाख से अधिक स्थलों पर अभियान चलाया गया, 180.48 लाख से अधिक फाइलों को हटाया या बंद किया गया है और कबाड़ बेचकर 5,102.91 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि अकेले 'अभियान-5' में 11.6 लाख स्थलों से कुल 29.52 लाख फाइलों को हटाया गया, 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल खाली कराया गया और कबाड़ बेचकर लगभग 833.92 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया।

कार्मिक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बुधवार को 'अभियान 6' की प्रगति की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। यह अभियान दो अक्तूबर से 31 अक्तूबर के बीच चलाया जाएगा। इससे पहले 16 सितंबर से 30 सितंबर तक तैयारी का चरण होगा। तैयारी के चरण के दौरान, मंत्रालय और विभाग चुनिंदा श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करेंगे, जमीनी स्तर के कर्मचारियों को एकत्र करेंगे, अभियान की जगहों

पांच वर्षों में सरकारी कार्यालयों में चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान। 180 .48 लाख से अधिक फाइलों को हटाया या बंद किया गया।

को अंतिम रूप देंगे, रिकार्ड की समीक्षा करेंगे और जगह के प्रबंधन की योजना बनाने के साथ-साथ चिह्नित कबाड़ का निस्तारण करेंगे। बयान के मुताबिक 19 से 25 दिसंबर तक चलने वाले 'सुशासन सप्ताह' के दौरान बेहतरीन तौर-तरीके पेश किए जाएंगे। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को होने वाले कार्यक्रम के दौरान, केंद्र के सभी 84 मंत्रालयों और विभागों में 'अभियान 6' के नोडल अधिकारियों, जन शिकायतों से जुड़े नोडल अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों की एक बैठक होगी। बैठक को प्रशासनिक सुधार , डाक, कोयला, खान और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संबोधित करेंगे।

चिंतन

धरती के लिए खतरा बढ़ा रही अंतरिक्ष में हथियारों की आहट

अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात कर रखे हैं। अमेरिकी वायुसेना के सचिव ट्रॉय मिंक का यह खुलासा ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका, रूस और चीन के बीच अंतरिक्ष में रणनीतिक बढ़त हासिल करने की होड़ लगातार तेज हो रही है। सवाल इसलिए केवल यह नहीं है कि अमेरिका ने अंतरिक्ष में कौन से हथियार तैनात किए हैं, बल्कि यह भी है कि इस खुलासे का समय क्या संकेत देता है? क्या यह ईरान और पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश है या फिर अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के एक नए दौर का सार्वजनिक ऐलान? अमेरिकी अधिकारी ने यह तो कहा कि ऑर्बिट में मौजूद हथियार जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैनिकों और अंतरिक्ष प्रणालियों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि ये हथियार किस प्रकार के हैं, कितने हैं और इन्हें कब अंतरिक्ष में भेजा गया। यही गोपनीयता इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बनाती है। आज के युद्ध में सैटेलाइट किसी देश की आंख, कान और संचार व्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। सेना इनके जरिए संपर्क बनाए रखती है, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखती है, मिसाइलों की चेतावनी हासिल करती है और अपने सैनिकों तथा हथियारों की स्थिति का पता लगाती है। इसलिए अंतरिक्ष पर नियंत्रण का अर्थ धीरे-धीरे युद्ध के मैदान पर बढ़त हासिल करने से जुड़ता जा रहा है। अमेरिका लंबे समय से रूस और चीन की अंतरिक्ष सैन्य क्षमताओं को लेकर चिंता जताता रहा है। रूस के अंतरिक्ष में परमाणु क्षमता विकसित करने की आशंकाओं को लेकर भी अमेरिका चिंता जाहिर करता रहा है, हालांकि मॉस्को इन आरोपों से इनकार करता है। दूसरी ओर, चीन भी अपनी सैन्य आधुनिकीकरण नीति के तहत अंतरिक्ष और एंटी-सैटेलाइट तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका का यह कहना कि उसके पास भी ऑर्बिट में हथियार मौजूद हैं, सुरक्षा की मजबूरी के रूप में पेश किया जा सकता है। समस्या यह है कि एक देश की सुरक्षा दूसरे देश के लिए खतरा बन सकती है। परिणाम वही होगा जो दुनिया ने परमाणु हथियारों की होड़ में देखा। सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे असुरक्षा को बढ़ाती चली गई। इस घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, संचार और मानव प्रगति का क्षेत्र नहीं रह गया है। वह तेजी से सैन्य रणनीति का नया मोर्चा बन रहा है। यदि किसी बड़े संघर्ष में सैटेलाइटों को निशाना बनाया गया तो उसका असर केवल सैनिक अभियानों तक सीमित नहीं रहेगा। नेविगेशन, विमानन, समुद्री परिवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं तक पर असर पड़ सकता है। अंतरिक्ष में मुठभेड़ हुई तो उसकी कीमत धरती पर आम आदमी चुका सकता है। यहीं 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी की प्रासंगिकता सामने आती है। इस संधि ने पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों की तैनाती पर रोक लगाई थी। लेकिन इसमें पारंपरिक हथियारों के अंतरिक्ष में इस्तेमाल पर वैसी स्पष्ट और व्यापक रोक नहीं है। अमेरिका का ताजा खुलासा इसलिए दुनिया के लिए चेतावनी है कि अंतरिक्ष को युद्ध का नया मैदान बनने से रोकने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय नियम पर्याप्त नहीं हैं। दुनिया को अब यह तय करना होगा कि अंतरिक्ष में कौन-सी सैन्य गतिविधियां स्वीकार्य होंगी और कौन-सी नहीं।

पश्चिम एशिया संकट
अखिलेश आर्येन्दु

ऊर्जा जरूरत और अर्थव्यवस्था पर असर

तेल की कीमत 100 डालर के पार पहुंच गई है, जिसका असर दुनियाभर में साफ-साफ दिखाई दे रहा है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए इसका अर्थ है-ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती, रुपये पर दबाव, महंगाई का जोखिम और आयात बिल में वृद्धि। जैसे-जैसे सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे तमाम तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा सुरक्षा इतनी अधिक आयातित तेल पर निर्भर रह सकती है? पश्चिम एशिया में संघर्ष और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर व्यवधान ने तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए यह चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि देश अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है।

पश्चिम एशिया संकट सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है और न ईरान ही। ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध रूस-यूक्रेन जैसा लम्बा खिंचेगा। तेल की कीमत 100 डालर के पार पहुंच गई है, जिसका असर दुनियाभर में साफ-साफ दिखाई दे रहा है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए इसका अर्थ है-ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती, रुपये पर दबाव, महंगाई का जोखिम और आयात बिल में वृद्धि। जैसे-जैसे सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे तमाम तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं।

सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा सुरक्षा इतनी अधिक आयातित तेल पर निर्भर रह सकती है? पश्चिम एशिया में संघर्ष और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर व्यवधान ने तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए यह चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि देश अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में हर उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती लेकर आता है। तेल केवल पेट्रोल पंप पर बिकने वाला ईंधन नहीं है, इसका संबंध अर्थव्यवस्था के तकरीबन हर क्षेत्र से है। परिवहन, कृषि, विमानन, पेट्रोकेमिकल उद्योग में कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक, रसायन, सिंथेटिक फाइबर और अनेक औद्योगिक वस्तुओं की लागत भी ऊर्जा कीमतों से जुड़ी होती है। इसलिए कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर धीरे-धीरे ही सही, हर क्षेत्र में दिखाई देता है। सबसे पहले आयात बिल बढ़ता है। इसके बाद डालर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव बढ़ जाता है। रुपया लगातार प्रतिदिन गिर रहा है। रुपया कमजोर होने पर भारत में आयातित तेल और महंगा हो जाता है। यानी भारत के सामने दोहरा दबाव पैदा हो जाता है- अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा और डालर के मुकाबले रुपया कमजोर। रुपया कमजोर होने का मतलब डालर की मांग बढ़ना और आयात की हुई हर वस्तु की कीमत अधिक चुकता करना। महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह रुपये का लगातार कमजोर होते जाना है। इसलिए एशिया संकट जितनी जल्दी खत्म होगा, भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। पश्चिम एशिया में तेल की कीमतों का लगातार बढ़ते जाने के बावजूद भारत में उस तरह की महंगाई का दौर नहीं आया, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में देखने में आया और अभी भी बना हुआ है। सवाल यह है कि तेल के दाम बढ़ते जाने के असर से भारत में वस्तुओं के दाम स्थिर बनाए रखना क्या हर स्थिति में संभव होगा? अर्थशास्त्रियों के अनुसार दुनिया में तेल संकट के बाद भी भारत में महंगाई उस दर से नहीं बढ़ी, जैसे भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ी। इसकी वजह है भारत के पास दुनिया की बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला सुरक्षा कवच का होना। इस सुरक्षा कवच के कारण कच्चा तेल आयात करके उसे पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद में बदल सकता है। दूसरी बात, भारत ने रूस सहित अलग-अलग देशों से तेल खरीदकर पिछले वर्षों में अपने आयात स्रोतों को भी विधिवत बनाया है, लेकिन यह सुरक्षा कवच बहुत लम्बे समय तक सुरक्षा नहीं दे सकता है। यदि तेल आयात पूरी तरह ठप हो जाए तो भारत के सामने ऊर्जा के दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए

अभी से ही विकल्पों को दुरुस्त करना होगा। सवाल यह है कि क्या रूस पर निर्भरता ऊर्जा समस्या का समाधान है या असली समाधान के लिए वैकल्पिक ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना समाधान है? पश्चिम एशिया संकट के बीच अक्सर कहा जाता है कि भारत को अपने सबसे विश्वसनीय मित्र रूस से अधिक तेल खरीदना चाहिए बजाय मध्य-पूर्व देशों से। जानकारों के अनुसार रूस पर निर्भरता कुछ हद तक ही ठीक है।

एक देश पर निर्भरता के बजाय भारत को चाहिए कि वह अनेक स्रोतों और अनेक तकनीकों के संतुलित मिश्रण को अपनाए। यानी स्थायी समाधान भारत को मुकम्मल रूप से खुद तैयार करना होगा। हर तेल संकट भारत को एक ही संदेश देता है-तेल आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार वैकल्पिक ऊर्जा का विस्तार कर रही है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में लगातार विस्तार कर रही है। गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है। केवल सौर पैनल लगा देने से तेल समस्या खत्म नहीं होगी। अभी गैर-जीवाश्म ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की संख्या बहुत कम है। गैर जीवाश्म ऊर्जा से चलने वाले दो और चार पहिया वाहनों की खरीदारी बढ़ी तो है, लेकिन उतनी नहीं, जिससे तेल संकट के वक्त काम आ सकें। इसी तरह सार्वजनिक परिवहनों, रेलवे का विद्युतीकरण, ऊर्जा-कुशल माल ढुलाई जैसे विकल्प बढ़े हैं, लेकिन यह बहुत कम हैं। इसके लिए बैटरी भंडारण और ग्रिड क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। ठंडक के दिनों में कोहरा छाए रहने, बरसात में कई दिनों तक बादल छाए रहने पर सौर ऊर्जा कम प्राप्त हो पाती है। हालिया ऊर्जा समस्या के समाधान में केंद्र सरकार ने कोयले और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए परमाणु, सौर, पवन, जलविद्युत, बैटरी भंडारण और हरित हाइड्रोजन जैसे विविध स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने का कार्य किया है। इससे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर होने वाली चिंताओं में राहत दिखाई दी है। हाल में यह बताया गया कि तेल संकट के साथ देश में बिजली संकट भी बढ़ सकता है, क्योंकि मांग की अपेक्षा आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आज की तारीख में देश के 59 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार बेहद कम है। आज की रिपोर्ट के अनुसार इन संयंत्रों के पास या तो निर्धारित स्टाक का 25 प्रतिशत से कम था या तीन दिन से कम उत्पादन जितना कोयला उपलब्ध था। बिजली की मांग करीब 267 गेगा वाट पहुंची और रिकार्ड 270 गेगा वाट के आसपास बनी हुई है। अब जब कि तेल, कोयला दोनों का संकट बढ़ रहा है, देश को ऊर्जा सुरक्षा मिशन की जरूरत बढ़ गई है। अब केंद्र सरकार को ऐसी ऊर्जा नीति बनानी होगी, जो किसी भी संकट के वक्त सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद रहे। पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि तेल आयात पर धीरे-धीरे निर्भरता कम की जाए। दूसरी नीति रणनीतिक रूप से पेट्रोलियम भंडार को बढ़ाया जाए। तीसरी सुरक्षा यह होनी चाहिए कि एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाएं। चौथी सुरक्षा इलेक्ट्रोलिकल सार्वजनिक परिवहन को तेज गति से बढ़ाया जाए जैसे दिल्ली सरकार ने किया है। पांचवीं सुरक्षा बैटरी स्टोरेज और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को मजबूत किया जाए। छठे सुरक्षा के रूप में परमाणु ऊर्जाऔर नवीकरणीय ऊर्जा के संतुलित विस्तार को बढ़ाया जाए और ऊर्जा आयात के लिए एक ही क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता धीरे-धीरे कम की जाए। बढ़ते ऊर्जा संकट में केंद्र सरकार बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तेल और गैस संकट से भारत अपने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का बेहतर इस्तेमाल कर उबर जाएगा और ऐसा संकट नहीं आएगा कि जनता त्राहि-त्राहि करने लगेगी।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

विश्व ओजोन दिवस
रोहित कौशिक

नया शोध, नई जानकारी लेकिन खतरा टला नहीं

विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि विश्व के ज्यादातर देश किसी न किसी रूप से विकास कर रहे हैं। जीवन स्तर सुधारने के लिए विकास की यह प्रक्रिया सुखद है, लेकिन क्या इस विकास से सच्चे अर्थों में हमारा जीवन स्तर सुधर पाया है? भौतिक रूप से देखें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन स्तर सुधरा है, लेकिन विकास की इस प्रक्रिया ने हमारे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई है। इसका असर न केवल प्रकृति के स्वास्थ्य बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा जीवन स्तर सुधरा नहीं है, अपितु खराब ही हुआ है। विकास की इस प्रक्रिया ने प्रकृति को कई जख्म दिए है। प्रकृति के इन जख्मों ने इंसान के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। विभिन्न तरह से हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत का क्षरण भी विकास की अंधाधुंध प्रक्रियाओं का ही नतीता है। समय-समय पर ओजान परत को लेकर कई अध्ययन प्रकाशित होते रहते हैं। दरअसल, ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण की एक महत्वपूर्ण है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारण पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों को पता चला था कि यह परत तेजी से पतली हो रही है। मुख्य रूप से अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन छेद बन रहा था। वैज्ञानिकों ने बताया था कि इसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन हैं जो फ्रिज, एयरकंडीशनर और स्प्रे उत्पादों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक नए अध्ययन में बताया गया है कि ओजोन परत का क्षरण 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) ने अपने नए अध्ययन में दावा किया है कि अगर आज जैसी उन्नत निगरानी तकनीकें पहले उपलब्ध होतीं तो वैज्ञानिक ओजोन क्षरण के संकेत 1957 में ही पकड़ सकते थे। इसका अर्थ यह है कि ओजोन छिद्र की खोज से लगभग तीन दशक पहले ही इस सुरक्षात्मक परत को नुकसान होना शुरू हो चुका था।

अब तक मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही ओजोन परत के शुरुआती क्षरण के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा है, लेकिन बताया गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बल्कि कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम का एक औद्यागिक रयासन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार था। दरअसल, लगातार हो रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों का सबसे बड़ा लाभ यही है कि नई-नई जानकारियां सामने आती रहती है। ऐसे अध्ययनों में कई बार पिछले अध्ययनों को नकार भी दिया जाता है। यही विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। विज्ञान की इसी ताकत के बल पर नए आविष्कार होते हैं और नया शोध प्रमाण के साथ सामने आता है। ओजोन परत पर हुए इस नए अध्ययन के नतीजे प्रतिष्ठित जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएएस) में प्रकाशित हुए हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड 1930 के दशक से ही ड्राईक्लीनिंग और मशीनों की सफाई में चिकनाई हटाने वाले सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। बर्फ की गहराइयों से निकाले गए आइस कोर नमूनों में भी इसके निशान मिले। यही रसायन ओजोन परत का शुरुआती क्षरण कर रहा था। हालांकि, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल दुनिया के कई हिस्सों में बंद किया जा चुका है। अब कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि ओजोन परत का क्षरण कम हुआ है। इस दौर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। विभिन्न देशों की सरकारें भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। हालांकि पर्यावरण के मुद्दे पर अभी भी कई देशों का व्यवहार खोखले आदर्शवाद की परिधि में आता है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस दौर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इस दिशा में कुछ काम भी हो रहा है। यही कारण है कि आज ओजोन परत की स्थिति में सुधार हुआ है। ओजोन परत की दशा सुधारने के लिए कई तरीके के उपाय किए गए। यह भी कटु सत्य है कि पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर होने वाली वैश्विक संगोष्ठियों में कई बार अपेक्षित निर्णय नही लिए जाते। अनेक बार कई तरह के विरोधाभास भी उभर आते हैं, लेकिन इन सब विसंगतियों के बावजूद जब बार-बार ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है तो कुछ सार्थक परिणाम भी सामने आते ही हैं। इन परिणामों का ही यह नतीजा है कि आज ओजोन परत की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि इस सुधार के आधार पर यह मान लेना कि खतरा पूरी तरह टल गया है, उचित नहीं है। हमें इस दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। अगर इन प्रयासों में कहीं भी कमी हुई तो ओजोन परत के क्षरण का खतरा पुनः पैदा हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि ओजोन परत को संरक्षित करना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मनुष्य इंद्रिय विषयों में करता है आनंद अनुभव

संकलित
दर्शन

भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। पहला है श्रद्धा। लोग मंदिरों और पवित्र स्थानों के प्रति श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं, क्योंकि वहां भगवान की पूजा होती है, ऐसे स्थानों में उनकी सत्ता अधिक अनुभूति होती है। प्रत्येक देश में लोग धर्माचार्यों के प्रति श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं, क्योंकि ये आचार्य उन्हीं भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं। इस श्रद्धा का मूल है प्रेम। हम जिससे प्रेम नहीं करते, उसके प्रति कभी श्रद्धालु नहीं हो सकते। इसके बाद है प्रीति अर्थात ईश्वर चिंतन में आनंद। मनुष्य इंद्रिय विषयों में तीव्र आनंद अनुभव करता है। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजों के लिए वह भटकता फिरता है और बड़ा से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। इसके उपरांत आता है विरह। विरह प्रेमास्पद के अभाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख। यह दुख संसार के समस्त दुखों में सबसे मधुर है। जब मनुष्य भगवान को न पा सकने के कारण, संसार में एकमात्र जानने योग वस्तु को न जान सकने के कारण तीव्र वेदना अनुभव करने लगता है और अत्यंत व्याकुल हो पागल-सा हो जाता है, उस दशा को विरह कहते हैं। मन की ऐसी दशा में प्रेमास्पद को छोड़ उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुधा यह विरह सांसारिक प्रणय में देखा जाता है। जब पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है तो अन्य अप्रिय विषयों की उपस्थिति हमें खटकने लगती है, यहां तक कि प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बातचीत तक कहना हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है।

मैं भी मेला देखने जाऊंगी

संकलित
प्रेरणा

एक गांव में मां-बेटी रहती थीं। एक दिन वह अपनी मां से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। मां ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने मां की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। मां ने जाने से पहले बेटी को दो लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। मां ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांववाले वापिस आ गए लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते-कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैने यह एक लड्डू और पानी नहीं पीया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया फिर वह कहने लगे कि मांगों तुम क्या मांगती हो? वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो मां ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया।

अंतर्मन

आज की पाती

युवाओं के हौसले का विजयघोष

आज का भारत उस दौर से गुजर रहा है, जहां प्रतिभा किसी बड़े शहर, संपन्न परिवार या महंगे संसाधनों की मोहताज नहीं रह गई है। देश के छोटे कस्बों, गांवों और सामान्य परिवारों से निकलकर युवा अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा की विश्व कप फाइनल में स्वर्णिम सफलता इसी बदलते भारत और उसके युवाओं के बढ़ते हौसले का जीवंत उदाहरण है। यह केवल एक खिलाड़ी की जीत नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के सपनों की जीत है, जो सीमित साधनों के बावजूद बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैक्सिको के साल्टिलो में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल के पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में धीरज ने जापान के जुन्या नाकानिशी को रोमांचक मुकाबले में शूट ऑफ के जरिए हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। -कांतिलाल मांडोत, सूरत

ट्रेंड

डिफेंस स्टार्टअप्स

भारत में डिफेंस स्टार्टअप्स की एक नई लहर उठ रही है। ये स्टार्टअप्स ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में आधुनिक डिफेंस सेक्टर को एक नई दिशा दे रहे हैं। आज का इनोवेशन ही कल की मिलिट्री क्षमता है। - राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

सेवा संकल्प अभियान

'सेवा संकल्प अभियान' इस साल इसलिए भी खास है क्योंकि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और तब से वे लगातार 25 सालों से जनसेवा में समर्पित है।
- जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री

शिक्षा सिस्टम

भारत का शिक्षा सिस्टम उसी पीढ़ी को निराश कर रहा है जिसे उसे ऊपर उठाना था। पेपर लीक होना। बहुत ज्यादा फ़ीस। खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर। लाखों युवा भारतीय ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी सिस्टम उन्हें निराश करता है।
- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

लोकतंत्र दिवस

लोकतंत्र के इस अंतरराष्ट्रीय दिवस पर, हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि 'हम, भारत के लोग' ही लोकतंत्र की असली नींव और आत्मा हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस तरह काम करे जिससे लोगों का कल्याण हो। जो लोकतंत्र अपने लोगों की बात नहीं सुनता, वह लोकतंत्र नही है।
-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

बांग्लादेश व चीन ने प्रस्तावित आर्थिक गलियारे पर की चर्चा

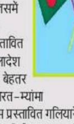

चीन के राजदूत याओ वेन ने बांग्लादेश की कनिष्ठ विदेश मंत्री शमा ओबैद इस्लाम से मुलाकात की तथा उन्होंने ढाका को म्यांमा और चीन से जोड़ने वाले प्रस्तावित आर्थिक गलियारे के संबंध में सहयोग पर चर्चा की। स्थानीय मीडिया की खबर में यह जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय का हवाला देते हुए बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी 'बीएसएस' ने बताया कि सोमवार को मंत्री के कार्यालय में यह बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, मानव संसाधन विकास और आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा की। प्रस्तावित आर्थिक गलियारा का मकसद म्यांमा के रास्ते बांग्लादेश और दक्षिण-पश्चिमी चीन के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। यह पूर्व में प्रस्तावित बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमा (बीसीआईएम) आर्थिक गलियारा से अलग है। इस प्रस्तावित गलियारे से बीजिंग को बंगाल की खाड़ी तक व्यापार और कनेक्टिविटी का एक अतिरिक्त रास्ता मिल सकता है। खबर के अनुसार, दोनों पक्षों ने रंगपुर में 1,000 बिस्तरों वाले प्रस्तावित अस्पताल, शिक्षा और मानव-संसाधन विकास, दोनों देशों की जनता के स्तर पर संपर्क, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और महिला सशक्तीकरण पर भी चर्चा की।

ऑफ बीट

एआई से बढ़ी वित्तीय धोखाधड़ी सावधानी बरतने की जरूरत

फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ आपके पोते की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वह बताता है कि उसके साथ दुर्घटना हो गई है और उसे तत्काल पैसों की जरूरत है। आवाज पोते की आवाज जैसी ही होती है लेकिन पोते की आवाज नहीं होती। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से तैयार की गई आवाज होती है, जिसे इंटरनेट पर उपलब्ध किसी वीडियो या ऑडियो क्लिप से तैयार किया गया है। कई वर्षों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनियों का केंद्र कॉरपोरेट नेटवर्क और सरकारी प्रणालियां रही हैं। हालांकि, ये खतरे वास्तविक हैं, लेकिन अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के धोखाधड़ी संबंधी आंकड़ों से एक अलग तस्वीर सामने आती है–घरेलू खातों से बड़ी मात्रा में धन निकल रहा है। एफबीआई की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उसकी इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर (आईसी3) इकाई ने पहली बार एआई से जुड़े मामलों को अलग से दर्ज करना शुरू किया। अमेरिकियों ने ऐसे 22,000 से अधिक मामले दर्ज कराए और करीब 89.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नुकसान की सूचना दी। इनमें से 63.2 करोड़ डॉलर का नुकसान निवेश संबंधी धोखाधड़ी में हुआ जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 35.2 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

यूपीआई पर फीस

जिस समय महंगाई दर के आंकड़े मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, उसी समय 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' यानी यूपीआई लेन-देन से संबंधित अधिसूचना से देश के करोड़ों उपयोगकर्ताओं व छोटे कारोबारियों का चिंतित होना स्वाभाविक है। अभी तक किसी भी यूपीआई लेन-देन पर कोई फीस नहीं लगती थी। ऐसे में, उनकी चिंता निराधार नहीं कही जा सकती। हालांकि, सरकार ने 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेन-देन पर किसी तरह की फीस-वसूली को प्रतिबंधित करके आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों के हितों को संरक्षित करने का काम किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बैंक या पेटीएम, फोनपे, गूगलपे जैसी सेवा प्रदाता कंपनियां घोषित सीमा तक के लेन-देन पर कोई चार्ज नहीं लगा सकेंगी। अलबत्ता, यह सवाल ज्यादा मौजूं हो गया था कि 2,000 रुपये से अधिक के लेन-देन पर सरकार कितनी फीस वसूल करेगी? नेशनल पेमेंट्स कौंसिल ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने देर शाम यह स्पष्ट कर दिया कि 15 अक्तूबर से कुछ कारोबारी लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाया जाएगा।

डिजिटल भारत की कामयाबी की मुनादी में यूपीआई सिस्टम सबसे अग्रणी रहा है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना 66 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन-देन हो रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में इसकी सफलता को देखते हुए ही कई देशों ने इसे अपने यहां अपनाया है। ऐसे में, इसकी शुरुआत के एक दशक बाद अब सरकार ने इससे कुछ आमदनी कमाने के बारे में सोचा हो, तो आश्चर्य की बात नहीं। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में संकेत किया भी था कि अगर भविष्य में एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) सिस्टम लागू हुआ, तो वह सिर्फ बड़े लेन-देन पर आंशिक रूप में लागू होगा, इससे आम लोगों के आपसी लेन-देन प्रभावित नहीं होंगे। सरकार ने देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए इन बदलावों की उपयोगिता बताई है। निस्संदेह, सरकार अपनी जगह सही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों को अचूक बनाने की जरूरत है। जिस बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होने लगा है, साइबर जालसाजी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। इसलिए इसकी सुरक्षा में निवेश की दरकार है।

सियासत अपनी जगह, मगर देश के वित्तीय ढांचे में अगर किसी दीर्घकालिक बदलाव की शुरुआत होती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, विपक्ष इसे अमेरिकी दबाव की परिणति बताने में जुट गया है। देश की अनेक विपक्षी पार्टियों और लोकसभा में नेता, प्रतिपक्ष ने इसे राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के इरादे से उठाया गया कदम बताया है। यूपीआई की सफलता से अमेरिकी भुगतान नेटवर्क की ईर्ष्या जगजाहिर है। ऐसे में, कोई दोराय नहीं कि आने वाले दिनों में इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ेगी। सरकार के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ, उसे विपक्ष के राजनीतिक हमलों का जवाब देना होगा, तो दूसरी ओर इस बात की भी निगरानी रखनी होगी कि एमडीआर का भार आम यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर न पड़े। हमारे देश में कारोबारी घरानों की जो स्थिति है, उसमें कोई भोला ही यकीन करेगा कि कारोबारी इसका भार अपने ऊपर लेंगे। किसी भी किस्म के आर्थिक बोझ को वे जनता के कंधों पर डालने में सिद्धहस्त हैं। अब जब सरकार ने एमडीआर लागू करने की घोषणा कर दी है, तो उसे जनता को संतुष्ट करना होगा कि उसकी जेब सुरक्षित है। सियासत अपनी जगह, मगर देश के वित्तीय ढांचे में अगर किसी दीर्घकालिक बदलाव की शुरुआत होती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 16 सितंबर, 1951

नेहरू-टंडन विवाद

नेहरू-टंडन विवाद के नाम से कांग्रेस तथा देश के सामने जो एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था, वह कांग्रेस महासमिति के प्रायः सर्वसम्मत निर्णय से हल हो गया। जहां देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था ने राष्ट्र-नेता नेहरू का दृढ़ समर्थन किया, वहां टंडनजी की कांग्रेस-सेवाओं की सराहना भी की। महासमिति के गुप्त अधिवेशन में दो प्रस्ताव स्वीकृत हुए। प्रथम प्रस्ताव में टंडनजी की सराहना करते हुए उनका त्यागपत्र स्वीकार किया गया और दूसरे प्रस्ताव में नेहरूजी से अध्यक्ष का भार संभालने का अनुरोध किया गया। ... इस प्रकार महासमिति ने एक कठिन समस्या को सुलझाने में बड़ी शांति व समझदारी से काम लिया।

नेहरूजी ने कांग्रेस महासमिति के अनुरोध पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया। अधिवेशन में यह भी तय हुआ कि 17 से 19 अक्तूबर तक दिल्ली में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाये। स्मरण रहे कि नेहरूजी ने यह इच्छा प्रकट की थी कि कांग्रेस को गतिशील बनाने के लिए पुनः कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता है। उनकी इच्छानुसार ही इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कांग्रेस के इस संकट के निवारण में श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपने स्वभावानुसार जिस शालीनता का परिचय दिया, वह कांग्रेस के इतिहास में अमर रहेगी। स्वयं अपने पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने कांग्रेस महासमिति के लिए मार्ग निकाल दिया, नहीं तो समिति एक बड़ी दुविधा में पड़ जाती। इस प्रकार जहां टंडनजी ने कांग्रेस कार्यसमिति के पुनर्निर्माण के प्रश्न पर अपने सिद्धांतों का पूर्ण निर्वाह किया, वहां अपने "छोटे भाई" जवाहरलाल नेहरू के हाथों में अध्यक्ष की बागडोर थमाकर दूरदर्शिता का परिचय दिया। कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में उन्होंने कहा : ''मैं नेहरूजी का त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय वह हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। साथ ही वैधानिक सत्ता के विचार से मैं उनकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। इस पेशोपेश में मेरे सामने पदत्याग के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं।''

नेहरूजी ने अपने भाषण में कहा कि टंडनजी से गत 39 वर्षों से मेरा संबंध है और उनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। लेकिन जब मैंने देखा कि कांग्रेस आम जनता से दूर होती जा रही है, तो मैंने त्यागपत्र देना ही ठीक समझा।

महंगाई पर हर मुमकिन वार जरूरी

अरुण कुमार | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

थोक और खुदरा महंगाई दरें कम हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए लागत घटाना जरूरी है, क्योंकि जब उत्पादन सस्ता होगा, तभी लोगों को उत्पाद भी सस्ता मिलेगा।

भारत में थोक और खुदरा, दोनों महंगाई दरों में इजाफा हुआ है। नए आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में जहां खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई, वहीं थोक महंगाई दर भी 9.92 फीसदी तक पहुंच गई है। इससे आम लोगों की जेब अधिक ढीली होने लगी है।

महंगाई बढ़ने के कुछ कारक बाहरी हैं, तो कुछ घरेलू, पर कुछ प्रयासों से हम इसके असर को कम कर सकते हैं। यह सच है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, जिसकी बड़ी वजह वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आई रुकावट है। युद्ध के कारण ईंधन के दाम फिर से बढ़ने के कारण भी महंगाई बढ़ी है। रही-सही कसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने पूरी कर दी है। पिछले साल तो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया ही था, इस वर्ष ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 को हथियार बनाकर करीब 60 देशों पर 10 से 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया है। टैरिफ बढ़ने से कारोबार में रुकावटें बढ़ती हैं और आपूर्ति प्रभावित होती है। यह महंगाई बढ़ाती है।

घरेलू कारकों में सबसे पहला है, कॉरपोरेट सेक्टर की मनमानी। मई में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने एक कार्यक्रम में बताया था कि बीएसई 500 या एनएसई 500 की कंपनियों का मुनाफा कोरोना के बाद सालाना करीब 31 फीसदी बढ़ा है, लेकिन निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण की हमारी दरें अब भी निराशाजनक हैं, यानी वे जरूरी निवेश नहीं कर रहीं। चूंकि बड़ी कंपनियों के पास बाजार नियंत्रित करने की ताकत होती है, इसलिए उनकी नीतियों का असर महंगाई पर पड़ता है। अच्छा होगा कि सरकार चंद कंपनियों का एकाधिकार खत्म करे। अब तो कमोबेश हर क्षेत्र में दो-तीन बड़े खिलाड़ियों का ही दबदबा है। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए।

सुधार प्रबंधन के स्तर पर भी करना होगा। मसलन, खाद की किल्लत ने भी महंगाई बढ़ाई है, क्योंकि इस कमी ने खेती-बाड़ी को काफी प्रभावित किया है। इनका

प्रबंधन इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ऐसी किल्लत आमतौर पर कालाबाजारी बढ़ाती है। इसे चीनी के उदाहरण से समझिए। यह पिछले साल ही पता था कि अल नीनो की वजह से गन्ने की उपज कम होने वाली है, फिर भी हमने 2025-26 के लिए करीब 20 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी दे दी। इससे इस साल हमारे शुरुआती भंडार कम हो गए, जबकि गन्ने की पैदावार कम होने से चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ। इसने बाजार में कमी की आशंका पैदा कर दी और कालाबाजारियों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। नतीजतन, खुदरा बाजार में चीनी के दाम 70 रुपये किलो तक पहुंच गए।

निस्संदेह, बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जिस तरह बफर स्टॉक से सस्ती दर पर प्याज बाजार में उतारना शुरू किया, उसी तरह से चीनी के बढ़ते दाम को कम करने के लिए भंडारण की सीमा घटाने, आयात को मंजूरी देने और कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए गए। हालांकि, अवधारणा के स्तर पर काम नहीं हुआ और बाजार में यह अफवाह बनी रही कि देश में चीनी की किल्लत है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए पहले से ही काम करने की जरूरत है।

चूक यह भी हुई कि अल नीनो के प्रतिकूल असर के जैसे पूर्वानुमान लगाए गए थे, हालात उतने खराब नहीं हुए। बेशक, मानसूनी बारिश कुछ कम हुई, लेकिन यदि कृषि का उचित प्रबंधन किया जाता, तो महंगाई को कुछ हद तक थामा जा सकता था। वैसे, यह काम अब भी किया जा सकता है। खेती-बाड़ी को लेकर जमीनी अध्ययन अनिवार्य है और उसी आधार पर कृषि नीतियां भी बननी चाहिए।

इसी तरह, खाद्यान्न की कीमतों को भी नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि यह विशेषकर गरीबों को काफी प्रभावित करता है। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि हम सार्वजनिक जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी को अनाज देने की व्यवस्था करें। फिलहाल एक बड़ी आबादी को सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, पर कभी उसकी गुणवत्ता सवालों में रहती है, तो कभी आपूर्तिकर्ता डीलर की मंशा, नतीजतन कई लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सबको अनाज मुहैया कराने से यह धांधलीबाजी नहीं हो सकेगी। मुमकिन हो, तो सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून को मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जहां यह अधिकार ठीक-ठीक काम करता है, वहां व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहती है।

महंगाई थामने के लिए अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार अनिवार्य है। जितना अधिक अप्रत्यक्ष कर लगता है, कीमतें उतनी अधिक बढ़ती हैं। जैसे- गेहूं पूरी तरह से जीएसटी मुक्त है, लेकिन उसकी जब ढुलाई होती है, तो ट्रक पर, उसके कल-पुर्जों पर, डीजल जैसे उत्पादों पर विक्रेताओं को जीएसटी देना पड़ता है। ऐसे में, अगर जीएसटी दरें बढ़ेंगी, तो गेहूं पर कोई टैक्स न होने के बावजूद आम लोगों के लिए इसके दाम बढ़ते जाएंगे। अभी अप्रत्यक्ष कर का जीडीपी अनुपात लगभग 11 फीसदी है, जबकि प्रत्यक्ष कर का करीब 6.5 प्रतिशत। हमें यह समझना होगा कि प्रत्यक्ष कर यदि सरकार ज्यादा वसूलती है, तो महंगाई में शायद ही इजाफा होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी सीधे उत्पादों की कीमतें बढ़ा देती हैं।

कुछ ऐसा ही संतुलन शोध और विकास (आरऐंडडी) के क्षेत्र में भी बनाने की जरूरत है। दरअसल, अपने देश में नई प्रौद्योगिकी पर उस तरह से काम नहीं हो रहा, जिस तरह से चीन, अमेरिका या रूस जैसे देश कर रहे हैं। इसी कारण, हमारी उन पर निर्भरता बनी हुई है, जिसका एक नुकसान बढ़ती महंगाई भी है। मसलन, सौर ऊर्जा में पर्याप्त संभावनाएं होने के बावजूद हमारे पास इस ऊर्जा के संग्रहण की पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके लिए हम चीन का मुंह ताकते हैं, पर बीजिंग बैटरी बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल महंगा बेचता है, जबकि बनी-बनाई बैटरी सस्ता। इसका हमें दोतरफा नुकसान हो रहा है। लिहाजा, शिक्षा पर निवेश बढ़ाकर हमें शोध व विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता घटे। मुमकिन है, शुरुआत में हमें असफलता हाथ लगेगी, लेकिन सफलता की राह भी यहीं से निकलेगी।

साफ है, हमें अब अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। लागत घटाना जरूरी है, क्योंकि जब उत्पादन सस्ता होगा, तभी लोगों को उत्पाद भी सस्ता मिलेगा। इसके लिए शिक्षा में निवेश बढ़ाना अनिवार्य है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अब हर अल नीनो पहले से अधिक कीमत वसूल रहा

पंकज चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

जलवायु परिवर्तन ने अल नीनो को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया है और यह केवल आशंका नहीं है, बल्कि अब वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध हो चुका है। प्रतिष्ठित जर्नल *साइंस* में प्रकाशित एक नए शोध का यह निष्कर्ष है। इस शोध का नेतृत्व मिशिगन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जूलिया कोल ने किया और जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक डॉ किम कॉब सहित अनेक जलवायु विज्ञानी इसमें शामिल रहे।

शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष गैलापागोस द्वीपसमूह के जीवित व जीवाश्म प्रवाल भित्तियों, यानी कोरल रीफ के रासायनिक अभिलेखों (टाइम कैप्सूल) के विश्लेषण से निकाले, क्योंकि यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के उस अहम हिस्से में स्थित है, जहां अल नीनो की उत्पत्ति और तीव्रता तय होती है। इस अध्ययन के अनुसार, अल नीनो घटनाएं औद्योगिक युग से पहले, यानी 19वीं सदी के मध्य से पहले की तुलना में आज 36 प्रतिशत से ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि पिछले चालीस वर्षों में इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो संकेत है कि यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

अल नीनो घटनाएं औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 36 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बीते चार दशकों में ये 16 प्रतिशत तक बढ़ी हैं।

वैज्ञानिकों के लिए यह अनुसंधान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यक्ष समुद्री तापमान के अवलोकन पर आधारित रिकॉर्ड मात्र 75 वर्ष पुराने हैं, जिस कारण अब तक इस बढ़ोतरी की पुष्टि करना कठिन था। कोरल की परतों में सुरक्षित रासायनिक संरचना ने शोधकर्ताओं को सैकड़ों वर्ष पीछे जाकर समुद्री तापमान के इतिहास को पढ़ने का अवसर दिया, जिससे 1877 की भीषण अल नीनो घटना जैसी अन्य पुरानी घटनाओं को पहचाना जा सका।

यह अध्ययन ऐसे समय पर सामने आया है, जब प्रशांत महासागर में एक और अत्यंत प्रबल, तथाकथित 'सुपर अल नीनो' आकार ले रहा है। इसके इस वर्ष के अंत तक रिकॉर्ड तोड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में तापमान औसत से लगभग तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। ध्यान देने की बात यह है कि आधुनिक अभिलेखों में 1982 के बाद से केवल तीन सुपर अल नीनो घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें से सबसे हालिया 2015-16 की घटना ने पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में 3.6 करोड़ से अधिक लोगों को भुखमरी के मुहाने पर पहुंचा दिया था। ऐसे में, जब अल नीनो की बारंबारता और तीव्रता अधिक अप्रत्याशित होती जा रही हैं, तब इसका असर सबसे अधिक उन देशों पर पड़ने वाला है, जो कृषि और मानसून पर निर्भर हैं। जाहिर है, भारत इसमें सबसे आगे है।

भारत में लगभग 70 प्रतिशत वार्षिक वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है और लगभग आधी खेती योग्य भूमि सीधे इसी वर्षा पर निर्भर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस वर्ष मानसून का दीर्घकालिक औसत 90-92 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है। यह बीते एक दशक से अधिक समय में सबसे कमजोर मानसूनों में गिना जा रहा है। इतिहास इस पैटर्न की पुष्टि करता है। 2002 और 2009 जैसे प्रबल अल नीनो वर्षों में वर्षा औसत के 80 प्रतिशत से भी नीचे चली गई थी, जबकि 2015 के सुपर अल नीनो में यह 86 प्रतिशत रही थी। इसका सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ता है, जिनमें धान, दलहन, तिलहन, कपास और गन्ना जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं। कृषि देश के जीडीपी में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान भले करती हो, पर यह लगभग आधे श्रम-बल को रोजगार देती है। ऐसे में, मानसून में कमी का असर करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय पर पड़ता है। इसके अलावा, कमजोर मानसून का प्रभाव जलाशयों के जल-स्तर और जल-विद्युत उत्पादन पर भी पड़ता है।

साफ है, नया शोध केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, एक चेतावनी है। अल नीनो अब उतना प्राकृतिक नहीं रहा, जितना पहले समझा जाता था; मानव गतिविधियों से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन इसे अधिक विनाशकारी बना रहा है। भारत जैसे देश को, जिसकी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा आज भी मानसून की एक धुरी पर टिकी हुई है, यह निष्कर्ष आगाह कर रहा है कि जलवायु अनुकूलन को अब दीर्घकालिक योजना का केंद्रीय हिस्सा बनाना होगा, अन्यथा हर आने वाला सुपर अल नीनो पहले से अधिक भारी कीमत वसूल करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

युद्ध की जड़ ईर्ष्या

आपमें तथा आपके चारों ओर होने वाले क्लेश और भ्रांति में क्या संबंध है? जाहिर है, ये भ्रांति, कष्ट अपने आप नहीं आ गए। आप और मैं, यानी हम ही इनको लेकर आए हैं। आप जो भीतर से हैं, वही बाहर, विश्व पर प्रक्षेपित हुआ है। आप जो हैं, जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में जो कार्य करते हैं, उसी का बाहर प्रक्षेपण होता है और उसी से संसार बनता है।

यदि हम अंदर से कंजूस, भ्रमित, अशांत और क्षुब्ध हैं, तो प्रक्षेपण द्वारा हमसे वैसा ही संसार, समाज निर्मित होता है, क्योंकि आपके और मेरे बीच का संबंध ही समाज है। और, यदि हमारे संबंध गड्ड-मड्ड, अहं-केंद्रित, संकीर्ण, संकुचित हैं, तो हम उसी को प्रतिबिंबित करेंगे और संसार में अव्यवस्था लाएंगे।

आप जैसे हैं, वैसा ही संसार है, अतः आपकी समस्या संसार की समस्या है। क्या यह सीधा-सा और मूलभूत तथ्य नहीं है? अपने संबंधों में इस तथ्य की हम सदा अनदेखी कर देते हैं। हम किसी विधि या विचार या मूल्यों में विधि-जनित क्रांति के जरिये बदलाव लाना चाहते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम ही हैं, जो अपनी जीवन पद्धति से अस्त-व्यस्तता या व्यवस्था लाते हैं। इसलिए शुरुआत हमें अपने निकट से करनी होगी, यानी हमारा जो दैनिक जीवन है, उसी से हमारा सीधा सरोकार होना चाहिए। जीविका कमाते वक्त, धारणाओं व विश्वासों के साथ अपने संबंध आदि में किस प्रकार हमारे विचार, हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, उन सबसे हमारा सीधा संबंध होना चाहिए।

जीविका, नौकरी, पैसा कमाना, हम इन्हीं सब में तो लगे हुए हैं; धारणा, विश्वास, परिवार और पड़ोसियों से हमारे रिश्ते, यही हैं हमारी दिलचस्पी के विषय। अब यदि हम अपने व्यवसाय की बारीकी से परीक्षा करें, तो पाएंगे कि यह मूलतः ईर्ष्या पर आधारित है। यह मात्र जीविकोपार्जन का मामला नहीं है। समाज इस प्रकार से रचा गया है कि वह एक अंतहीन द्वंद्व, निरंतर कुछ बनने की कोशिश भर रह गया है। वह लोभ, ईर्ष्या, जलन पर आधारित है। एक क्लर्क मैनेजर बनना चाहता है, यानी उसका वास्ता सिर्फ जीविका कमाने या निबाह के साधन

यदि हम अंदर से कंजूस, भ्रमित, अशांत और क्षुब्ध हैं, तो प्रक्षेपण द्वारा हमसे वैसा ही संसार, समाज निर्मित होता है, क्योंकि आपके और मेरे बीच का संबंध ही समाज है।

जुटाने से ही नहीं है, पद और प्रतिष्ठा पाने से है। यह दृष्टिकोण समाज में, संबंध में तबाही लाता है, लेकिन यदि आपका और मेरा सरोकार सिर्फ जीविकोपार्जन से होता, तो हम उसके लिए उचित साधन ढूंढ़ ही लेते। ऐसा साधन, जो ईर्ष्या पर आधारित नहीं होता।

संबंधों में ईर्ष्या सर्वाधिक विनाशकारी तत्वों में से एक है, क्योंकि यह इस बात की सूचक है कि सत्ता और पद की लालसा बनी हुई है, जो आखिरकार राजनीति की ओर ले जाती है।

जे कृष्णमूर्ति

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

अपनी भाषा में बात करना आत्मविश्वास है, कोई सीमा नहीं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदी को नई पीढ़ी, नई तकनीक एवं नए अवसरों से जोड़ते हुए इसे ज्ञान, नवाचार और वैश्विक संवाद की अधिक सशक्त भाषा बनाएं।

मेहमाननवाजी पर भी संकीर्ण राजनीति

ब्रिक्स की मेज पर दुनिया बैठी थी, लेकिन विपक्ष की नजर थाली पर थी। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आधिकारिक रात्रिभोज में विदेशी मेहमानों को शाकाहारी भारतीय व्यंजन परोसे गए। खांडवी, मशरूम गलौटी, पनीर लबाबदार, गुच्छी मार्मिक, बाजरे का पुलाव, बीटरूट रायता और पारंपरिक भारतीय मिठाइयों से सजा यह मेन्यू भारत की समृद्ध शाकाहारी पाक-परंपरा का प्रदर्शन था, लेकिन मेहमानों की मेज से उठकर यह मेन्यू सीधे भारतीय राजनीति की मेज पर पहुंच गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब भारत में अधिकांश लोग मांसाहारी हैं, तो विदेशी मेहमानों के सामने केवल शाकाहारी व्यंजन क्यों परोसे गए?

जाहिर है, न तो ब्रिक्स कोई पारिवारिक डिनर का मंच है और न ही राजकीय भोज का उद्देश्य यह साबित करना होता है कि देश के कितने प्रतिशत लोग क्या खाते हैं। यदि भारत किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में अपने श्रेष्ठ शाकाहारी व्यंजनों को दुनिया के सामने रखता है, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? क्या किसी देश का सांस्कृतिक परिचय सिर्फ उसके मेन्यू कार्ड से तय होगा? दुर्भागपूर्ण है कि विपक्ष की नजर में ब्रिक्स के मुद्दों से अधिक महत्वपूर्ण खाने का मेन्यू है। विपक्ष यह पूछ सकता था कि भारत ब्रिक्स के माध्यम से अपने आर्थिक हितों को किस तरह आगे बढ़ा रहा है? चीन के साथ व्यापार असंतुलन को लेकर नई दिल्ली की रणनीति क्या है? ब्रिक्स के विस्तार से भारत की सामरिक स्थिति कितनी मजबूत होगी आदि? इन सवालों पर सरकार को असहज किया जा सकता था, लेकिन विपक्ष ने चुना 'मेन्यू'!

यहीं से यह विवाद केवल भोजन का विवाद नहीं रह जाता, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकता का सवाल बन जाता है और विपक्ष की राजनीतिक प्रतिबद्धता सवालों में आ जाती है। उसका तर्क है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी हैं, तो क्या राजकीय भोज का मेन्यू जनगणना के आंकड़ों के अनुपात में तय होगा? यदि देश में 70 प्रतिशत लोग किसी विशेष भोजन को पसंद करते हैं, तो क्या मेन्यू में 70 प्रतिशत वही भोजन होना चाहिए? यदि किसी राज्य में मांसाहार प्रमुख भोजन है, तो क्या हर अंतरराष्ट्रीय भोज में मांसाहार अनिवार्य होना चाहिए? विडंबना है कि आज देश की राजनीति ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां विपक्ष भूल गया है कि राजकीय भोज संसद की सीटों का वितरण नहीं है, मेन्यू कार्ड वोट-बैंक नहीं है और प्लेट कोई जनगणना-तालिका नहीं है। काश, विपक्ष यह समझ पाता कि वह सरकार से मेन्यू का हिसाब मांग रहा है, जबकि देश उससे राजनीतिक विकल्प का मेन्यू मांग रहा है।

नीलम महेंद्र, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

ब्रिक्स-मेन्यू

भारतीय व्यंजनों के वैविध्य की अनदेखी

नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन में परोसे गए शाकाहारी भोजन ने कूटनीति से अधिक घरेलू राजनीति को चर्चा में ला दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि भारत की लगभग 80 फीसदी आबादी मांसाहार करती है, इसलिए विदेशी मेहमानों के सामने केवल शाकाहारी भोजन पेश करना भारत की वास्तविक खाद्य-विविधता का अधूरा प्रदर्शन है।

विपक्ष की आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि शाकाहार अच्छा है या मांसाहार? बल्कि, यह है कि क्या किसी एक खाद्य संस्कृति को पूरे भारत का प्रतिनिधि बनाया जा सकता है? भारत की पहचान विविधता है। इसकी सांस्कृतिक पहचान बहुलता में निहित है। कश्मीर का रोगन जोश, बंगाल का माछ-भात, केरल का मीन करी, नगालैंड के पारंपरिक व्यंजन और हैदराबाद की बिरयानी- ये सभी भारतीय खान-पान की विरासत हैं। इसी तरह गुजरात की खांडवी, राजस्थान की दाल-बाटी और दक्षिण भारत के अनेक शाकाहारी व्यंजन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में, ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच पर यदि केवल एक पक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो यही संदेश जा सकता है कि भारत की आधिकारिक पहचान केवल शाकाहार तक सीमित है। विपक्ष इसीलिए मुखर है। आंकड़े भी उसके दावों को पुष्ट करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 15 से 49 वर्ष आयु-वर्ग में अधिकांश भारतीय पुरुष और बड़ी संख्या में महिलाएं कभी-न-कभी मांसाहार करती हैं। इसलिए विपक्ष का पक्ष सही है कि यदि सम्मेलन का उद्देश्य 'भारत का स्वाद' दुनिया के सामने रखना था, तो उसमें भारत की दोनों प्रमुख खाद्य परंपराओं का स्थान होना चाहिए था।

किसी भी देश के लिए भोजन केवल आतिथ्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संदेश भी होता है। फ्रांस अपने चीज और वाइन, जापान सुशी, जबकि तुर्किये अपने मिश्रित व्यंजनों के माध्यम से अपनी पहचान प्रस्तुत करता है। भारत यदि 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की बात करता है, तो उसका भोज भी उसी समावेशी दृष्टि का प्रतीक होना चाहिए। निस्संदेह, ब्रिक्स सम्मेलन में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन परोसना गलत नहीं, पर जब अवसर पूरे भारत का सांस्कृतिक परिचय देने का हो, तब विविधता का सम्मान अधिक प्रभावशाली कूटनीति बन सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनेकता है; इसलिए वैश्विक मंचों पर भी उसी अनेकता का स्वाद दुनिया तक पहुंचना चाहिए था। आगामी सम्मेलनों में भारतीय खान-पान की विविधता का ख्याल रखा ही जाना चाहिए।

अंकुरी मिश्र, टिप्पणीकार

किराना कारोबार में बढ़ती सजगता

भारत के किराना क्षेत्र में वाकई क्रांति की जरूरत है। यहां प्रीमियम या उच्चस्तरीय किराना विक्रेताओं की संख्या बढ़ रही है। गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और इसके लाभ आम किराना उपभोक्ताओं तक पहुंचने चाहिए। सेहत के प्रति सजगता बढ़ी है, तो ऐसे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ रही है, जो अच्छे सामान के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। पेश है राधिका पी नायर की एक खास रिपोर्ट...

किराना स्टोर की बढ़ती संख्या और बदलती खरीदारी

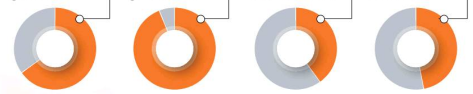

65% हिस्सेदारी है भारत में किराना दुकानों की कुल खुदरा बाजार में

94% किराना खरीद के लिए लोग आज भी पारंपरिक दुकानों पर निर्भर हैं

40% घरेलू बजट भारतीय शहरों में लोग किराना उत्पादों पर खर्च करते हैं

47% घरेलू बजट भारतीय गांवों में केवल किराना उत्पादों पर खर्च होता है

1.40 करोड़ छोटे और बड़े किराना स्टोर अभी भारत में चल रहे हैं।

2.80 करोड़ से ज्यादा लोग आजीविका के लिए किराना स्टोर पर निर्भर।

8000 से ज्यादा कंपनियां भारत में खाद्य निर्माण व आपूर्ति में लगी हैं।

खरीदते समय क्या देखते हैं ग्राहक

कीमत : बदलता रुख

1 तमाम सर्वे बताते हैं कि लोग खरीदारी करते समय सबसे पहले कीमत देखते हैं। कम से कम कीमत पर सामान खरीदने का मानव स्वभाव पुराना है, पर इधर एक धारणा यह मजबूत हुई है कि अच्छे सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कई लोग पूछने लगे हैं कि सबसे महंगा सामान कौन सा है?

गुणवत्ता : समझौता नहीं

2 विश्व में तमाम व्यावसायिक सर्वे इशारा करते हैं कि ग्राहक कीमत जितनी ही तरजीह गुणवत्ता को देते हैं। भारतीय बाजारों में भी ज्यादातर ग्राहक कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के सामान खोजते देखे जाते हैं। यहां जागरूक ग्राहकों को पता है कि ज्यादा कीमती सामान की गुणवत्ता भी सुनिश्चित नहीं होती है।

वैधता : असली और मौलिक की बढ़ती मांग

3 एक दौर था, जब लोग उत्पाद के स्रोत पर ध्यान नहीं देते थे। अब दुकान पर हर उत्पाद की वैधता परखते ग्राहक दिख जाते हैं। ग्राहक एक्सपायरी डेट से लेकर उत्पाद में शामिल तत्वों के आकार-प्रकार को भी परखने लगे हैं। उत्पाद की वैधता को कीमत और गुणवत्ता की तरह ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ग्राहकों की परेशानी

कीमतों को लेकर असंतोष और असमानता

कीमतों को लेकर असंतोष का भाव लगातार बना रहता है। एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग कीमत चुकाने की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन खरीद के लिए सेवा शुल्क के साथ ही, आपूर्ति शुल्क भी चुकाना पड़ता है। किराना उद्योग में कीमतों को लेकर मनमानी है। गुणवत्ता में भी बहुत ज्यादा अंतर है। दूध 48 रुपये लीटर में भी उपलब्ध है, तो कहीं उसकी कीमत 130 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा है। अनेक विक्रेता झूठे प्रचार से ठगते हैं।

गुणवत्ता पर भरोसा करना अभी भी मुश्किल

यह एक सच्चाई है कि किराना व्यवसाय में करीब 4 प्रतिशत उत्पाद रखरखाव के अभाव या प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाता है, लेकिन खराब उत्पाद को किसी तरह से बाजार में बेचने वाले कम नहीं हैं। डेयरी उत्पाद, फल और सब्जियों में सवार्धिक कमी देखी जाती है। ऑनलाइन उत्पादों में भी बहुत कमी देखी जाती है और शिकायतों के बावजूद ग्राहकों को धोखा देने वाले कम नहीं हो रहे हैं।

उत्पाद के लिए इंतजार और सुनवाई में लापरवाही

किराना क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग में भारत पीछे है। शहरों में अब 10 मिनट में आपूर्ति की सुविधा है, पर उत्पाद खराब होने पर सुनवाई बहुत मुश्किल है। सुपर मार्केट में बीलिंग काउंटर पर जरूरत से ज्यादा इंतजार आम बात है। ध्यान रहे, अनेक ब्रांड कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पैसे मांगते हैं, पर कई ब्रांड पहले ही पैसे मांगने लगते हैं। छह लाख मामले विभिन्न उपभोक्ता फोरम में लंबित हैं।

कृष्णा कुमार की सुबह की दिनचर्या 5:30 बजे योग और ध्यान से शुरू होती है, जिसके बाद वह बिना चीनी वाले ग्रैनोला के साथ उच्च प्रोटीन वाला दही, ब्लू टोकाई कॉफी और कटे हुए फलों या ताजे जूस के साथ हल्का नाश्ता करते हैं। लगभग सारा खाना फर्स्टक्लब से मंगाया जाता है, जो बेंगलुरु स्थित एक प्रीमियम ऑनलाइन किराना स्टार्टअप है, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था।

52 वर्षीय वरिष्ठ बैंक अधिकारी कृष्णा कुमार ने पिछले एक दशक में चीनी का सेवन कम कर दिया है, योग करना शुरू कर दिया है और शाकाहारी बन गए हैं। बढ़ती जागरूकता और ज्यादा धन खर्च करने की उनकी क्षमता ने उन्हें क्लीन-लेबल, कम प्रिजर्वेटिव वाले, ऑर्गेनिक और बेहतर गुणवत्ता वाले भोजन की ओर प्रेरित किया है।

कुमार यह नहीं चाहते थे कि किराने का सामान खरीदते समय हर उत्पाद का बार लेबल चेक करना पड़े और यहीं पर प्रीमियम किराना दुकानों की भूमिका सामने आती है। प्रीमियम किराना कंपनियों का कहना है कि वह अपने हर उत्पाद की गहन जांच करती हैं और कृत्रिम रंगों, शुगर, बेंजोएट (प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होने वाले) और आटा गूंथने वाले पदार्थों सहित 200 से अधिक सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। कुमार बताते हैं कि उत्पादों के मिश्रण से लेकर डिलीवरी और पैकेजिंग तक, पूरा अनुभव प्रीमियम एहसास कराता है। अब वह प्रीमियम किराना स्टोर से हफ्ते में कम से कम तीन बार खरीदारी करते हैं और हर सप्ताह कम से कम 1,000 रुपये खर्च करते हैं। कुमार ऐसे प्रीमियम किराना उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आयातित या महंगे उत्पादों से परे स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक, ताजा और आधिकारिक भारत निर्मित खाद्य पदार्थों की तलाश में रहते हैं। ऐसे उपभोक्ता किराना उत्पादों की गुणवत्ता को देखते हुए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं।

फर्स्टक्लब उन नए प्रीमियम किराना खुदरा विक्रेताओं में से एक है, जिन्होंने साल 2023 और 2025 के बीच अपना कारोबार शुरू किया है। कोरोना के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग हुए हैं और जो लोग खर्च करने में सक्षम हैं, वह गुणवत्ता से समझौता करना नहीं चाहते हैं। हालांकि, प्रीमियम किराना खुदरा बिक्री की इस चकाचौंध के पीछे कई बातें छिपी हुई हैं।

क्या यह नई बात है?

वैसे, प्रीमियम ग्रोसरी श्रेणी कोई नई बात नहीं है। दशकों से, धनी उपभोक्ता आयातित खाद्य पदार्थों और पनीर इत्यादि के लिए शहर की कुछ विशेष दुकानों व बाजारों की ओर रुख करते रहे हैं। दिल्ली में मॉडर्न बाजार और आईएनए मार्केट थे, मुंबई में वी के स्टोर्स और चेन्नई में अम्मा नाना।

फिर प्रीमियम किराना के लिए नेचर बास्केट और फूडहॉल जैसे संगठित प्रारूप सामने आए, लेकिन किराना की यह श्रेणी अपने विस्तार के लिए बहुत संघर्ष करती रही। फूडहॉल 2023 में बंद हो गया, जबकि 2005 में लॉन्च हुआ नेचर बास्केट राष्ट्रीय स्तर पर केवल 35 दुकानों तक सिमट गया। वित्त वर्ष 2024 में इसकी बिक्री 296 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 272 करोड़ रुपये रह गई है। मॉडर्न बाजार ने अपनी दुकानों की संख्या में भारी कमी की है, लगभग एक साल पहले तक 27 दुकानें थीं, जो अब घटकर 12 रह गई हैं।

कंसल्टिंग फर्म द नॉलेज कंपनी के वरिष्ठ पार्टनर अंकुर बिसन बताते हैं, ऊपरी तौर पर यह बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें और हिसाब लगाएं, तो कहानी कहीं अधिक जटिल है। प्रीमियम खाद्य खुदरा क्षेत्र में हमेशा से दो समस्याएं रही हैं। पहली है मांग का बिखराव। दूसरी है क्रियान्वयन। ध्यान रहे, प्रीमियम खाद्य पदार्थों के मामले में भारतीय खुदरा विक्रेता उत्कृष्ट उत्पाद बेचने में हमेशा सफल नहीं रहते हैं।

ग्राहक करने लगे सवाल

सवाल है, नए प्रीमियम किराना विक्रेता ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, जिससे सफल हो रहे हैं? सबसे पहले, भारत में उपभोक्ताओं की आय बढ़ी है और प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। यह अच्छी बात है कि पहले की तुलना में अब ज्यादा भारतीय अपने खान-पान को लेकर सतर्क हुए हैं।

अक्षयकालपा ऑर्गेनिक डेयरी कंपनी के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक शशि कुमार बताते हैं कि अब ग्राहक बहुत मुश्किल सवाल पूछने लगे हैं। ग्राहक जानना चाहते हैं कि मेरा भोजन कहां से आ रहा है? क्या यह मेरे लिए अच्छा है? इन दो सवालों से ही किराना की नई श्रेणी को ताकत मिल रही है।

पहले ग्राहक ऐसे सवाल नहीं करते थे, लेकिन इन सवालों से ही भारतीय किराना क्षेत्र में बेहतर बदलावों की बयार चलने लगी है।

बाजार अनुसंधान कंपनी आईएमएआरसी ग्रुप के अनुसार, भारत का प्रीमियम खाद्य बाजार महज एक साल में 22 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करेगा। 2025 में 5.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2026 में 6.6 अरब डॉलर हो जाएगा। साल 2034 तक यह 24.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

फूड स्क्वायर के सह-संस्थापक मयंक गुप्ता कहते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति में सैकड़ों नए ब्रांडों के लॉन्च के साथ जबरदस्त उछाल आ रहा है और हमें लगता है कि यह वृद्धि और भी तेज होगी। गौर कीजिए, 2023 में लॉन्च हुआ फूड स्क्वायर तीन स्टोर संचालित करता है और 150 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व या लाभ कमा रहा है।

बदल रही किराना रणनीति

पहले की तुलना में एक बदलाव यह है कि नए खुदरा विक्रेता इस बात पर जोर देते हैं कि अधिक कीमत का मतलब यह नहीं है कि उत्पाद प्रीमियम ही हैं। वास्तव में, फर्स्टक्लब खुद को प्रीमियम खुदरा विक्रेता कहना पसंद नहीं करता है। प्रीमियम का अक्सर मतलब होता है कि कोई चीज ज्यादा महंगी, खास है, एक तरह से पहुंच से बाहर। प्रीमियम उत्पाद बेचने वाली नई कंपनियां यह नहीं चाहतीं कि उनके उत्पादों को पहुंच से बाहर माना जाए।

यहां कीमत उतनी ही अहम है, जितनी गुणवत्ता। एक प्रीमियम स्टोर के मालिक अरविंद मेदिरात्ता कहते हैं, 'जब मैं गुणवत्ता की बात करता हूं, तब मेरा मतलब तीन चीजों से है : उत्पाद ताजा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और कीमत ऐसी होनी चाहिए, जिसे आम ग्राहक वहन कर सके। गुणवत्ता के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी चाहिए।'

नतीजा यह कि दिल्ली और उत्तर भारत में ज्यादातर ए2 घी गुजरात से और खपली गेहूं महाराष्ट्र से आ रहा है। ए2 गाय के गिर घी की कीमत 1,799 रुपये प्रति लीटर है, वैसे, बाजार में प्रीमियम के नाम पर प्रति लीटर 3000 रुपये तक घी उपलब्ध है। वहीं, खपली गेहूं 165 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है, कुछ स्टोर तो इसके लिए और भी ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। कुल मिलाकर, यह कोशिश हो रही है कि हर उत्पाद असली या मौलिक हो।

सावधानी से हो विस्तार

अब नए खुदरा विक्रेता पिछली नाकामियों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी खुदरा या किराना विक्रेता के लिए यह जरूरी है कि वह ग्राहकों को आकर्षित करे। किराना का नया विस्तार तभी सफल होगा, जब व्यवसाय में ग्राहकों की भागीदारी बढ़ेगी। पारंपरिक किराना विक्रेता भी अब प्रीमियम उत्पाद बेचने लगे हैं। अच्छे उत्पादों की मांग और उन्हें खेतों से ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिशें बढ़ रही हैं।

विकसित होते भारत में अच्छे उत्पादों का भविष्य उज्ज्वल दिखने लगा है। सेहत और कारोबार का तालमेल बिठाते हुए पूरे किराना क्षेत्र को प्रेरित होने की जरूरत है।

mint

कैसे बढ़ रहा किराना क्षेत्र?

- साल 2020 में भारत में किराना कारोबार 545 अरब डॉलर (45,780 अरब रुपये) तक पहुंच गया था।
- चालू वर्ष 2026 में किराना कारोबार 658 अरब डॉलर (55,272 अरब रुपये) तक पहुंच गया है।
- अनुमान है, साल 2030 तक यह कारोबार 992 अरब डॉलर (83,328 अरब रुपये) का हो जाएगा।

सुधार के लिए अभियान : चर्चा में तुकाराम मुंढे

लोगों को अच्छे उत्पाद चाहिए। लोग शुद्ध के लिए युद्ध चाहते हैं और ऐसे में, महाराष्ट्र के खाद्य आयुक्त तुकाराम मुंढे की चर्चा स्वाभाविक है। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य भर के रेस्तरां, कैफे और अन्य खाद्य व्यवसायों में निरीक्षण अभियान छेड़ रखा है। भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या गंभीर है और जुलाई में संसद में प्रस्तुत आंकड़े संकेत करते हैं कि यह समस्या कितनी व्यापक है। 2025 और 2026 में पूरे भारत में जांचे गए 2,23,808 खाद्य नमूनों में से लगभग पांच में से एक नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। खाद्य व किराना क्षेत्र में शिकायतों की भरमार है और ऐसे में, हर जगह तुकाराम मुंढे जैसे ईमानदार अधिकारियों की जरूरत बढ़ गई है।

दूध : सबसे ज्यादा उपयोग लेकिन 70% अशुद्ध

भारत में बुनियादी खाद्य पदार्थ दूध को लेकर सर्वाधिक शिकायत रही है। शहरों में ही नहीं, गांवों में भी शुद्ध दूध की उपलब्धता मुश्किल है। यहां बिकने वाले दूध का लगभग 70% हिस्सा भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं है। जब दूध मानक पर खरा नहीं है, तो पनीर और मिठाइयों का बहुत बुरा हाल है। शुद्ध दूध की मांग और उपलब्धता बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही है।

तेल : जरूरत से ज्यादा खपत, लेकिन 27% तक अशुद्ध

भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुताबिक, उसके द्वारा परीक्षण किए गए 4,461 खाद्य तेल के नमूनों में से 2.42% किसी न किसी तरह से सुरक्षा मानकों के मुताबिक नहीं थे, जबकि 24.2% नमूने गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह से नाकाम रहे। तेल और उसमें भी दूषित तेल के उपभोग की वजह से भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। कला व संगीत में रुचि बढ़ेगी। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

वृष : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। कारोबार के लिए पिता से धन मिल सकता है।

मिथुन : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। सेहत का ध्यान रखें।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में परिवर्तन के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, परंतु धैर्यशीलता भी बनाए रखें। कारोबार के लिए माता से धन मिल सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखें। लेखन आदि कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। धन की प्राप्ति भी होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

तुला : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं, परंतु किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। भागदौड़ भी बढ़ेगी।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। आय वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

मकर : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। सेहत का ध्यान रखें। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें। वाहन के रख-रखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

16 सितंबर, बुधवार, **शक संवत्**: 25, भाद्रपद, (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग**: 31, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम**: 04, रबि-उल्सानी, 1448 **विक्रमी संवत्**: भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि प्रातः 09 बजे तक पश्चात षष्ठी तिथि, विशाखा नक्षत्र सायं 05.23 मिनट तक, वैधृति योग दोपहर 12.23 मिनट तक, पश्चात विष्कुम्भ योग। चन्द्रमा तुला राशि में प्रातः 10.49 मिनट तक उपरांत वृश्चिक राशि।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। शरद ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

गणपति की सूंड़ को लेकर बड़ा भ्रम रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें।

- गणेश जी की सूंड़ का निर्धारण उनके शरीर के अनुसार माना जाता है। यदि गणेश जी की सूंड़ बायीं ओर मुड़ी हो, तो इसे वाम मुखी कहा जाता है। इसे सुख-शांति, सौभाग्य, समृद्धि से जोड़ा जाता है। इन्हें सामान्य जीवन में पूजा करने के लिए सरल माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भी कर सकते हैं। उनकी सूंड़ उनके दायीं ओर मुड़ी है, तो वह दक्षिण सूंड़ के गणपति हुए।
- इनकी पूजा में नियम, विधि विधान एवं शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- इन्हें कुछ विशिष्ट साधनाओं से जोड़ा जाता है।

वर्ग पहेली : 8453

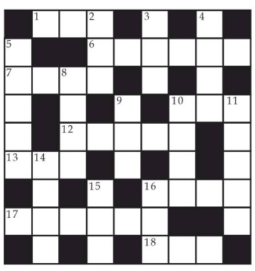

बाएं से दाएं
1. भावपूर्ण; मधुर; मीठा; रसीला (3)
6. रक्षा करना; छिपाना; दूर रखना; बचा कर चलना (3,3)
7. बारीक सूत से बुना पतला कपड़ा (4)
10. सोलह संस्कारों में से एक संस्कार; गृहस्थाश्रम प्रवेश; शादी (3)
12. कर चोरी करने वाला; कर न देने वाला (5)
13. पैमाइश करना; मापना; हिसाब लगाना; थाह लेना (3)
16. चप्पू; सुकर्ण; नाव चलाने की डांड (4)
17. उगाहा जाना; प्राप्त होना; वसूला जाना (4,2)
18. यज्ञ; होम (3)

ऊपर से नीचे
2. जिसके साथ सेना हो; बल सहित (3)
3. बयार; मरुत; वायु; हवा (3)
4. किसी धार्मिक काम की सेवा; निःशुल्क किया जाने वाला काम; श्रमदान (4)
5. धुआं खींचना; चिलम का कश लेना (2,3)
8. गंध होना; महक देना; बास छोड़ना (4)
9. लौंग का वृक्ष; लौंग (3)
10. उन्नत; खिला हुआ; जिसका विकास हुआ हो; प्रस्फुटित; सभ्य (4)
11. मौत के घाट उतारना; खून करना (2,3)
14. पत्थर, पत्थरों व ढेलों की वर्षा (4)
15. कुमक; सहायता (3)
16. शरण; आश्रय; त्राण; रक्षा स्थल (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8452

1 फ	ट	2 का	र	3 ना		4 ना		5 त
ड़		न		6 ना	का	म	या	ब
7 क	ला	का	र			ही		ल
ना		मै		8 ड	9 र	ना		ची
	10 श	ल	11 भ		12 स	म	य	
13 ज		14 नि	य	म		र		15 क
ल		का			16 रा	ह	गी	र
17 पा	ता	ल	वा	18 सी		जा		त
न		ना		19 ना	मु	ना	सि	ब

सुडोकू : 8407

*आसान

	1					8		
	7		6				4	5
3				2	9			
		9	4		1		3	
		1		8		2		
	3		2		5	1		
			9	6				2
7	2				3		8	
		5					1	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8406

6	4	7	8	2	5	3	1	9
5	3	9	6	1	4	7	2	8
1	2	8	9	7	3	5	4	6
4	7	2	5	9	1	6	8	3
3	5	6	7	4	8	2	9	1
8	9	1	2	3	6	4	5	7
7	6	4	1	5	9	8	3	2
2	1	3	4	8	7	9	6	5
9	8	5	3	6	2	1	7	4

दैनिक जागरण

क्षमादान से व्यक्ति स्वयं को ही एक बोझ से मुक्त करता है

आगे बढ़ी अटकी परियोजना

यह स्वागतयोग्य है कि लंबी प्रतीक्षा के बाद केंद्र सरकार की पहल पर छह राज्य महत्वाकांक्षी किशाऊ बांध परियोजना पर सहमत हुए। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने इस परियोजना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को लेकर हिमाचल की सहमति इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह विपक्ष शासित राज्य है। उसकी सहमति इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस हर मामले में विरोध के लिए विरोध की राजनीति का परिचय देती चली आ रही है। उसके नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार की सहमति यह बताती है कि लोक कल्याण के विषयों पर दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। यह अच्छा हुआ कि हिमाचल सरकार ने इस परियोजना के लिए सहमति दी। अभी तक वित्तीय अंशदान के अतिरिक्त इस परियोजना पर सहमति न बन पाने का एक कारण दलगत राजनीति भी रहा। यह जहां संतोषजनक है कि आखिरकार इस परियोजना का रास्ता साफ हो गया, वहीं इसकी अनदेखी भी न की जाए कि इसका प्रस्ताव स्वतंत्रता के पहले किया गया था। किसी परियोजना का आठ दशक से अधिक की देरी से शुरू हो पाना यही बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में किस तरह कुछ आवश्यक काम भी अटक जाते हैं। ऐसा लोकतंत्र की अति के चलते होता है। इस अति के चलते ही आम तौर पर हर योजना-परियोजना का विरोध होता है और इसके चलते विकास के अनेक कार्यक्रम देर से शुरू हो पाते हैं।

आम तौर पर पहले राजनीतिक दल किसी परियोजना के विरोध में उतरते हैं, फिर सामाजिक या पर्यावरण समूह। इसके साथ ही उन्हें अदालतों में भी चुनौती दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं की गिनती करना कठिन है, जिनके अमल में दशकों की देरी हुई। कुछ तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकीं। जो आगे बढ़ीं, उनकी लागत बढ़ी। किशाऊ बांध परियोजना पर हुआ समझौता उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में पेयजल और सिंचाई के संकट को दूर करने में सहायक बनेगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भी सुनिश्चित हो सकेगा। यह उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर जिले की सीमा पर टोंस नदी पर निर्मित की जाने वाली एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। चूंकि टोंस यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, इसलिए उसमें प्रवाह बनाए रखना आसान होगा और उसे साफ करने में भी मदद मिल सकती है। किशाऊ बांध परियोजना पर छह राज्यों के बीच हुआ समझौता यह बता रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह विभिन्न राज्यों के बीच समझौते कराने को लेकर सक्रिय है। पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार की सक्रियता के चलते कई राज्यों में नदी जल बंटवारे संबंधी समझौते हुए हैं। यह सिलसिला कायम रहना चाहिए।

बनी रहे सतर्कता

बिहार में बाढ़ की विभीषिका अब धीरे-धीरे सामान्य होती जाएगी। राहत शिविरों और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए लोग बाढ़ का पानी उतरते ही अपने घरों को जाएंगे। यह समय काफी कठिन होता है। जो घर बाढ़ में बच गए उन्हें रहने लायक बनाने में काफी मेहनत की जरूरत होती है। जबकि फूस और मिट्टी के घरों को दोबारा खड़ा करना होता है। दूसरी ओर घरों में गाद-कीचड़ छोड़ गई बाढ़ बीमारियों का भी कारण बनती है। यहां प्रशासन को काफी गंभीरता से काम लेना होगा। संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए रसायनों का छिड़काव सुनिश्चित करने की जरूरत है। साथ ही चिकित्सा की सुविधा को सक्रिय करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि संक्रामक बीमारियों के साथ कीड़ों या सर्पदंश की घटना पर त्वरित उपचार मिल सके। दूसरी ओर, नदियों का जलस्तर कम होने से कटाव की तीव्रता बढ़ रही है। सुपौल की मौजहा हो या समस्तीपुर की खरसंड पंचायत, यहां नदियों का कटाव तेज हो गया है। सुपौल में कोसी के कटाव के कारण मौजहा पंचायत के आधा दर्जन परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। रविवार को राधा-कृष्ण मंदिर कोसी में समा गया। यहां बचाव कार्य को गति देने की जरूरत है। समस्तीपुर में खरसंड पंचायत के लोगों की शिकायत है कि बागमती के कटाव से बचाव के प्रति गंभीरता नहीं बरती जा रही। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इस शिकायत का संज्ञान लेना चाहिए। पशुओं के लिए चारे की भी चिंता करनी होगी।

> बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारियों से बचाव एवं नदियों के कटाव के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है

सामने आए संस्कृति का सही स्वरूप

विकास सारस्वत

धार्मिक उत्सवों-आयोजनों में सुधार की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती और न ही यह आशा की जा सकती हैं कि अपने आप कोई नई संस्कृति जन्म लेगी

लंबे समय के बाद पिछले कुछ दशकों में हिंदू अपने उत्सवों को बिना बाधा, हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों के लिए ये उत्सव हुल्लड़ और शोर-शराबे का बहाना बन गए हैं। कुछ उत्सवों के दौरान ऐसे दृश्य आम हैं, जहां घंटों रास्ता रोकने वाली शोभायात्राएं, तेज आवाज में बजता संगीत, अश्लील गाने और नृत्य, राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार न केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न बनते हैं, बल्कि इन उत्सवों की शुचिता एवं पवित्रता का मानभंग भी करते हैं। इन आयोजनों में कलात्मकता का अभाव भी दिखाई देता है। एक बड़े क्षेत्र में हिंदू जनजीवन एक उच्च संस्कृति के उत्थान की बाट जोह रहा है। इस क्रम में आवश्यकता इसकी है कि सार्वजनिक उत्सवों में भी यह नई उच्च संस्कृति परिलक्षित हो। उच्च संस्कृति का अर्थ ऐसी संस्कृति से नहीं है, जो केवल संग्रहालयों, सभागारों या समाज के छोटे वर्ग तक सीमित हो। उच्च संस्कृति वह है, जिसकी अभिव्यक्ति पौराणिक कथाओं, सभ्यतागत प्रतीकों और दर्शन सार को सौंदर्यबोध के साथ मर्यादित रूप में प्रकट करे। ऐसी संस्कृति जो अर्थपूर्ण और सभ्य हो, जो रुचियों को परिष्कृत करे, भावनाओं का उत्सर्ग करे, ध्यान और संवेदनशीलता विकसित करे और समाज को स्वयं के बारे में एक गरिमापूर्ण दृष्टि दे। ऐसा नहीं है कि लोकप्रिय संस्कृति अपने आप में अशिष्ट होती है और केवल कुलीन संस्कृति ही श्रेष्ठ होती हो। उत्तरी हरियाणा की रागिनी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का कजरी या चैती गायन या फिर मिथिला की कोहबर और बुंदेली फाग, ये सभी भावपूर्ण और मर्यादित कलाएं रही हैं। ऐसा ही बृज के चरकुला, हरियाणा के घूमर और मिथिला की झिझिया नृत्य परंपराओं के बारे में कहा जा सकता है, पर यह सत्य है कि तमाम लोक नृत्य और संगीत या तो लुप्त हो रहे हैं या उनमें अश्लीलता का पुट बढ़ने के कारण उनका मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है। यह स्थिति दुखद है, क्योंकि उच्च संस्कृति इंद्रियों को उत्तेजित मात्र नहीं करती, बल्कि उनको अनुशासित और उर्ध्वगामी बनाती है। हिंदू सभ्यता के संदर्भ में तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू सौंदर्यबोध केवल वस्तुओं को सुंदर बनाने तक सीमित नहीं रहा।

हिंदू चिंतन में रस की अवधारणा है, जो सामान्य भावनाओं को कलात्मक अनुभूति में बदल देती है। भारतीय कला की इसी विशेषता पर बल देते हुए संस्कृति और कला के पुरोधा आनंद कैंटिश कुमारस्वामी ने लिखा है कि भारतीय कला का उद्देश्य केवल मूर्त वस्तुओं की अच्छी नकल करना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से उच्च आदर्शों और गहरे सत्य को प्रकट करना है। उनके मतानुसार कलाकार के लिए दृश्य सुंदरता शाश्वत को प्रकट करने का अनुशासित माध्यम है। श्री अरविंद ने कला के पतन के विषय में चेतावनी देते हुए कहा था कि अनुशासन खो देने पर कला 'तुच्छ, भड़कीली, इंद्रियप्रधान, सस्ती और अशिष्ट' बन सकती है। उनके लिए श्रेष्ठ कला बुद्धि, भावना और चरित्र को ऊपर उठाने वाली शक्ति थी। बकौल श्री अरविंद किसी समाज का सौंदर्यबोध केवल स्वाद का विषय नहीं होता, बल्कि वह धीरे-धीरे उस समाज का चरित्र बन जाता है। कुछ धार्मिक उत्सवों में अश्लील नाच-गाने की घटनाएं श्री अरविंद की चेतावनी को ही चरितार्थ करती हैं।

अवधेश राजपूत

उत्सवों का स्वरूप कितना सुंदर हो सकता है, उसका एक सुंदर उदाहरण बीते दिनों गुरुवायूर में होने वाले जन्माष्टमी उत्सव के दौरान दिखा। केरलम में इस उत्सव में पुष्परचनाओं, दीप प्रज्वलन, कृष्ण गोपिका नृत्य, उरियाडी यानि मटकी फोड़ने की रस्म, शोभायात्रा, भक्ति-संगीत और पारंपरिक वाद्यवृंद ने मिलकर ऐसा जादू रचा, जिसमें उत्सव, भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण था। ऐसा नहीं है कि गुरुवायूर ने कोई आधुनिक उपाय खोजा। वहां पारंपरिक तौर-तरीकों को ही अपनाया गया। इन्हीं पारंपरिक तत्वों के समायोजन से गणपति शोभायात्रा में अभंग, शास्त्रीय और लोक संगीत, सुव्यवस्थित वाद्यवृंद, ध्वज-पताकाएं एवं प्रामाणिक हिंदू प्रतीकों पर आधारित सज्जा और पौराणिक कथाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां संभव हैं। जन्माष्टमी में नृत्य, कीर्तन, कविता, नाटक, चित्रकला, कथा-वाचन और कलात्मक प्रकाश-सज्जा हो सकती है। नवरात्रि भी केवल कानफोड़ संगीत के बजाय कर्णप्रिय संगीत, नृत्य, साहित्य, वेशभूषा और देवी-परंपरा के अर्थ को समझने वाला नौ दिनों का सांस्कृतिक पर्व बन सकता है।

प्रश्न यह है कि इस परिवर्तन का नेतृत्व कौन करे? इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती और न ही यह आशा की जा सकती है कि अपने आप कोई नई संस्कृति जन्म लेगी। इसके लिए मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, कलाकारों और जागरूक सामाजिक नेतृत्व को आगे आना होगा। बड़े मंदिर न्यास और धार्मिक संगठन विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन और प्रभाव, दोनों हैं। वे संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, उत्सव-सज्जा और शोभायात्रा में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सरकार और नगरपालिकाएं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं, किंतु रचनात्मक नेतृत्व समाज के भीतर से आना होगा। संपन्न भक्त और सांस्कृतिक न्यास भी अपना धन केवल विशाल पंडालों और कानफोड़ संगीत पर न लगाकर कलाकारों और नई सांस्कृतिक रचनाओं को संरक्षण देने में लगा सकते हैं। उद्देश्य यह नहीं कि हिंदू उत्सवों को गंभीर शास्त्रीय संगीत समारोह बना दिया जाए या फिर उन्हें हास्य, रंग, खेल और सरल-सहज भक्ति से विहीन किया जाए। उद्देश्य उन्हें अधिक सुंदर, कल्पनाशील और सौम्य बनाना होना चाहिए। किसी सभ्यता की गंभीरता तब दिखाई देती है, जब वह उन रूपों को गंभीरता से लेने लगती है, जिनके माध्यम से वह स्वयं को व्यक्त करती है। हिंदू उच्च संस्कृति के पुनर्निर्माण में लोक-जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास होना चाहिए।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

अपना एजेंडा थोपने वाला इकोसिस्टम

राजीव सचान

वह इकोसिस्टम हावी हैं, जो किसी मुद्दे को तूल देकर या उसकी अनदेखी कर लोगों के सोचने के तरीके को प्रभावित करता हैं

किसी प्रकरण को अपने एजेंडे के हिसाब से तूल देकर अथवा उसकी अनदेखी कर समाज की चिंतनधारा को प्रभावित करने का काम किस तरह होता है और उसके लिए नैरेटिव गढ़ने वाला इकोसिस्टम कैसे काम करता है या नहीं करता, इसका ताजा उदाहरण है कि केरलम के उस मौलाना के प्रति नरम रवैया, जिसने कहा था कि महिलाएं घर से बाहर निकलीं तो तबाही होगी। तालिबानी सोच वाले ये मौलाना हैं शेख अबूबकर अहमद। उन्हें केरल का ग्रैंड मुफ्ती कहा जाता है। उनकी हैसियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनके समर्थकों के दबाव के चलते केरलम के उस बिग टीवी को माफी मांगनी पड़ी, जिसने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। दबाव इतना था कि टीवी चैनल ने माफी मांगने के साथ ही इस बहस का वीडियो भी हटा दिया। इतना ही नहीं, उक्त बहस को संचालित करने वाली चैनल की पत्रकार अपर्णा के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज कर दी गई-इस आरोप में कि उन्होंने माहौल बिगाड़ने और दंगे भड़काने का काम किया। यह तब हुआ, जब अपर्णा ने भी माफी मांग ली थी। यह सब कांग्रेस के शासन वाले केरलम में हुआ। गौर करें कि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए पितृसत्ता से लड़ने और उसे ध्वस्त करने की जरूरत जताई थी, लेकिन अबूबकर के बयान पर उन्हें सांप सा सूंघ गया। सनद रहे कि केरलम की कांग्रेस सरकार मुस्लिम लीग के समर्थन से चल रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा उस वायनाड से सांसद हैं, जो लीग का गढ़ है।

हालांकि केरलम के मुख्यमंत्री ने मौलाना अबूबकर के बयान से असहमति जताई, लेकिन राहुल गांधी के मौन रहने के चलते कांग्रेस के किसी केंद्रीय नेता ने मौलाना के खिलाफ मुंह खोलने का साहस नहीं दिखाया। जो केरलम प्रगतिशीलता के लिए जाना जाता है और जहां की तमाम महिलाएं कामकाजी हैं, उसके ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की तुलना सोने के गहनों से की थी, जिन्हें डिब्बे में सुरक्षित रखा जाता है। वैसे यह वह केरलम भी है, जहां इजरायल पर भीषण हमला करने वाले हमास के नेता का भाषण प्रसारित हुआ और जहां के अनेक युवा इस्लामिक स्टेट और अलकायदा में शामिल होने जा चुके हैं। अबूबकर के घनघोर पितृसत्तावादी सोच और अपर्णा के खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वे पैरोकार भी करीब-करीब मौन ही रहे, जिन्होंने किसी अन्य पंथ के धर्मगुरु के ऐसे ही बयान पर आसमान सिर पर उठा लिया होता। मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी इस मामले को महत्व देना जरूरी नहीं समझा। कोई भी समझ सकता है कि इसीलिए कि यह प्रकरण उनके नैरेटिव के मनमाफिक नहीं था। उन्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने केरलम दौरे पर अबूबकर से भेंट करना आवश्यक समझा। उनके अबूबकर से मिलने पर हैरानी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिहादी सोच वाले जाकिर नाइक को अपने यहां शरण दे रखी है।

मध्ययुगीन सोच वाले मौलाना को लेकर छाया मौन। फाइल

जिस इकोसिस्टम को मौलाना अबूबकर के महिलाओं को पर्दे और घर में रखने वाले बयान पर कोई खास परेशानी नहीं हुई, वह जेएनयू के उन प्रोफेसर को लेकर भी नरम है, जिन पर विश्वविद्यालय की 11 छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये आरोप करीब चार महीने पहले लगाए गए थे, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तो शायद इसलिए कि प्रोफेसर मणिपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और जेएनयू में वामपंथियों का बोलबाला है। कांग्रेस और वामपंथियों की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं। आरोपित प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई न होते देखकर दिल्ली महिला आयोग ने जेएनयू कुलपति को नोटिस देकर विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की ओर से की गई कार्रवाई के सिलसिले में तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने आरोपों का स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले में जेएनयू की आंतरिक शिकायत समिति क्यों मौन धारण किए रही, यह एक रहस्य है। यह मामला उसके एजेंडे को सूट नहीं कर रहा है। इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर से काकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में हिंसा के लिए जिम्मेदार तत्वों पर दर्ज की गई सभी एफआइआर वापस लिए जाने का भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अतीत वालों को छोड़कर शेष सबको माफी दे दी। सबने इस फैसले पर संतोष जताया। किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जाना कि हिंसा केवल आपराधिक अतीत वालों ने की? यह क्या दिखाता है? यह नैरेटिव बनाने वाले इकोसिस्टम की ताकत दिखाता है। देश में वह इकोसिस्टम हावी है, जो अपनी पसंद के किसी मुद्दे को खास दिशा देने या किसी विशेष विचारधारा को स्थापित करने के लिए एक उद्योग की तरह काम करता है और इस तरह लोगों के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

स्थिरता की शक्ति

मनुष्य की सामर्थ्य का आकलन प्रायः उसकी गति, उपलब्धियों और संघर्ष करने की क्षमता से किया जाता है, किंतु जीवन के गहनतम स्तर पर देखा जाए तो वास्तविक शक्ति उसकी स्थिरता में निहित होती है। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर संतुलित रहना नितांत सरल है, परंतु प्रतिकूलताओं के प्रचंड प्रवाह के मध्य स्वयं को अडिग बनाए रखना ही व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा है। स्थिरता का अर्थ ठहर जाना कदापि नहीं है। यह जड़ता नहीं, अपितु गति के भीतर संतुलन है। वृक्ष आंधी में अपनी शाखाओं को झुकाता है, किंतु अपनी जड़ों का परित्याग नहीं करता। यही स्थिरता है। परिस्थितियों के साथ आवश्यकतानुसार झुकना, किंतु अपने मूल्यों और विवेक से विचलित न होना ही स्थिरता का वास्तविक अर्थ है।

आज का जीवन निरंतर परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा और त्वरित परिणामों की आपाधापी में फंसा हुआ है। उपलब्धि हेतु अधीरता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में स्थिर रह पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वृक्ष वर्षों तक धरती के भीतर जड़ें फैलाते रहते हैं, तदुपरांत ही आकाश की ओर उठने की सामर्थ्य अर्जित कर पाते हैं। मन की स्थिरता भी ऐसी ही अदृश्य साधना है। आलोचना में विचलित न होना, प्रशंसा में उन्मत्त न होना, सफलता में अहंकार से बचना और असफलता में आत्मविश्वास न खोना-यही आंतरिक स्थैर्य है। जो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को अपने अंतर्मन का स्वामी नहीं बनने देता, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जीवन में तूफान समाप्त होने की प्रतीक्षा करना स्थिरता नहीं, तूफान के बीच अपनी जड़ों को पहचान लेना स्थिरता है। गति हमें आगे ले जाती है, किंतु स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जीवन की वास्तविक शक्ति कोलाहल में नहीं, अपितु उस मौन धैर्य में छिपी होती है।

प्रेरणा अवस्थी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता पर्यावरणीय प्रभाव

डा. सुधीर कुमार

पानी, खनिज एवं ऊर्जा का बेतहाशा उपयोग एवं इलेक्ट्रानिक कचरे का बढ़ना एआइ के प्रमुख दुष्प्रभाव हैं

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ का उपयोग डिजिटल युग की अनिवार्यता बनता जा रहा है। मानव चिंतन की नकल करने वाली यह तकनीक अपनी विविध महत्ता के लिए सभी आयु वर्ग के बीच लोकप्रिय होती जा रही है। हालांकि इस तकनीक के संचालन के पीछे बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग शक्ति का प्रयोग होता है, जिससे पर्यावरण को व्यापक हानि होती है। पानी, खनिज एवं ऊर्जा का बेतहाशा उपयोग एवं इलेक्ट्रानिक कचरे का बढ़ना एआइ के प्रमुख दुष्प्रभाव हैं। इस तकनीक का सीमित इस्तेमाल करके इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।

एआइ के संचालन के लिए दुनियाभर में डाटा सेंटर धड़ल्ले से खोले जा रहे हैं। इन डाटा सेंटरों में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरणों से उत्पन्न ई-कचरे में पारा और सीसा जैसे खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं, जो भूमि और जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। एक अनुमान के अनुसार, एआइ अवसंरचना से 2030 तक सालाना 25 लाख टन तक ई-कचरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं एआइ डाटा सेंटर पानी के बड़े उपभोक्ता होते हैं। इन सेंटरों पर विद्युत घटकों को ठंडा रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, एआइ से संबंधित जल की खपत इस दशक के अंत तक 1.3 अरब लोगों की बुनियादी वार्षिक घरेलू जरूरतों के बराबर हो सकती है। आज स्वच्छ जल की समस्या पूरे विश्व में गहरा चुकी है। ऐसे में एआइ का बढ़ता इस्तेमाल तकनीकी रूप से मददगार हो सकता है, किंतु यह जल संकट को भी बढ़ावा दे सकता है। दूसरी तरफ, एआइ से जुड़े डाटा सेंटरों के कंप्यूटिंग उपकरणों को संचालित करने के निमित्त बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, जो अमूमन जीवाश्म ईंधन जलाने से प्राप्त होती है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, एआइ-आधारित वर्चुअल असिस्टेंट चैटजीपीटी के माध्यम से किया जाने वाले प्रत्येक चैट से बिजली की खपत होती है। जाहिर है, व्यापक विद्युत खपत का दबाव विद्युत ग्रिडों और अंततः जीवाश्म ईंधन के दोहन पर पड़ता है। जीवाश्म ईंधनों से बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक तरफ, एआइ का इस्तेमाल तकनीकी रूप से समृद्ध कर रहा है तो यह पर्यावरण निम्नीकरण के लिए भी जिम्मेदार है।

बहरहाल, मानवता को भी समझना होगा कि प्रौद्योगिकी के विकास में हम इतने आगे न बढ़ जाएं कि इससे हमारा ग्रह ही संकट में पड़ जाए। एआइ डाटा सेंटरों के बढ़ते पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कानून की दरकार तो है ही, इसके इस्तेमाल की निरंतरता को बरकरार रखने के लिए अनावश्यक उपयोग कम करने, ऊर्जा-कुशल माडल को अपनाने और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देना होगा।

(पर्यावरण मामलों के जानकार)

पाकिस्तान को बेनकाब करे भारत

'पाकिस्तान का छलावा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान के छद्म वेश को तथ्यों के साथ उजागर किया गया है। आतंकी मसूद मजहर पर इनाम की राशि बढ़ाकर पाकिस्तान यह साबित करना चाहता है कि वह उसके यहां वांछित है, जबकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसके पाकिस्तान में ही छुपे होने के पुख्ता सुबूत दिए है। पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई आतंकियों की सूची में आतंकियों के फोटो और उनकी संबद्धता की अधूरी जानकारी भ्रम, अविश्वास और चिंता उत्पन्न करती है। पाकिस्तान की आतंकवादियों को पोषित करने की नीति को भारत से बेहतर कोई नहीं जानता है। अतः भारत का मानवता के समर्थन में आतंकवाद के विरुद्ध यह दायित्व है कि वह पाकिस्तान की इस चाल का माकूल जवाब दे और एफएटीएफ जैसे वैश्विक मंच पर उसकी करतूतों को बेनकाब करे।

डा. मोहित सोनी, कुक्षी (मप्र)

महिला बाइक राइडर की आजादी

गुरुग्राम के पाश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर महिला स्पोर्ट्स बाइकर सिया के साथ कथित हिट एंड रन की घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह महज सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सड़क पर कानून और इंसानी जिम्मेदारी के प्रति बढ़ती बेपरवाही है। वहीं किसी महिला का सड़क पर अकेले सफर करना उसके लिए डर का कारण बनना समाज और प्रशासन के तौर पर भी चिंताजनक है। गुरुग्राम देश के आधुनिक और विकसित शहरों में गिना जाता है। चमचमाती सड़कें, ऊंची इमारतें और कारपोरेट दफ्तर विकास की तस्वीर जरूर दिखाते हैं, लेकिन असल मे महिलाओं को तेज रफ्तार कार, संदिग्ध द्वारा पीछा और खतरनाक ड्राइविंग के बीच अपनी सुरक्षा के बारे में हर रोज सोचना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ समस्या सिर्फ सड़कों पर नहीं, उस पुरुष मानसिकता में भी है जो महिला की आजादी और असहमति को चुनौती समझते हैं। महिला का खुली सड़क पर बाइक चलाना उसकी स्वतंत्रता है, कोई अपराध नहीं। जब ताकत, अहंकार और दबंगई को मर्दानगी समझा जाएगा तक बेटियों की सुरक्षा का सवाल बना रहेगा। किसी महिला का आत्मविश्वास, उसकी स्वतंत्रता या उसका सड़क पर होना किसी पुरुष के अहंकार को चुनौती लगता है तो समस्या सिर्फ ट्रैफिक नियमों की नहीं, बल्कि कथित पुरुष मानसिकता वाले सोच में है। ऐसी घटनाएं सिर्फ सड़क पर डर पैदा नहीं करतीं, बल्कि भविष्य में महिला बाइक राइडर्स बनने का सपना देखने वाली बेटियों के आत्मविश्वास और मनोबल को भी चोट पहुंचाती हैं। यह सवाल सिर्फ सिया का नहीं है। यह उन तमाम बेटियों, बहनों और महिलाओं का सवाल भी है, जो रोज घर से निकलती हैं और सुरक्षित लौटने की उम्मीद करती हैं।

महेश कुमार, सिद्धमुख (राजस्थान)

मेलबाक्स

खेल भावना से खिलवाड़

पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों के कारण भारतीय नागरिकों में उसके प्रति नाराजगी और आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन खेल का मैदान राजनीतिक और व्यक्तिगत कटुता से ऊपर होता है। खेल भावना और मर्यादा का सम्मान दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। पिछले वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीतने के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों ट्राफी लेने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद नकवी ट्राफी लेकर चले गए और भारतीय टीम विजेता होने के बावजूद ट्राफी समारोह की औपचारिकता से वंचित रह गई। अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशिया कप जीतने के बाद भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नकवी ट्राफी प्रदान करने की जिद पर अड़े रहे, जबकि भारतीय टीम ने उनके हाथों ट्राफी लेने से इन्कार कर दिया। बीसीसीआइ ने पहले ही आयोजकों को स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय टीम नकवी के हाथों ट्राफी स्वीकार नहीं करेगी

हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

1.3 अरब डालर से बढ़ाकर भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक पांच अरब डालर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।

आजकल

भारतीय कूटनीतिक प्रभाव की गूंज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता, अटूट दृढ़ संकल्प और मानवतावादी दृष्टिकोण का लोहा मनवाया है। हाल में नई दिल्ली में संपन्न 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इसी तरह गत दिनों ताशकंद से लेकर बिश्केक तक की उनकी यात्रा यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के बढ़ते कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव की एक गूंज भी थी

श्री राम शा
shriramshaw@nda.jagran.com

भारतीय कूटनीति के इतिहास में यह दौर एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने वैश्विक पटल पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, कूटनीति, अटूट दृढ़ संकल्प और मानवतावादी दृष्टिकोण का लोहा मनवाया है। हाल में संपन्न 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान देश-दुनिया ने इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसी तरह गत दिनों ताशकंद से लेकर बिश्केक तक की उनकी यात्रा भी मात्र कूटनीतिक बैठकों का सिलसिला नहीं थी, बल्कि यह यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के बढ़ते सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक प्रभाव की एक गूंज थी। मध्य एशिया के इन देशों के साथ भारत के रिश्ते अब केवल राजनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह साझा भविष्य, विश्वास और पारस्परिक विकास की एक मजबूत नींव पर खड़े हैं।

ऊर्जा और खनिजों की सुदृढ़ साझेदारी : प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा ने भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित 11 ऐतिहासिक समझौते इस बात के गवाह हैं कि भारत अब केवल कच्चे माल का खरीदार नहीं, बल्कि मूल्य श्रृंखला में एक बराबर का साझीदार बन रहा है। भू-राजनीतिक रूप से अक्सर रूस, चीन और अफगानिस्तान के बीच एक खाली जगह समझे जाने वाले इस क्षेत्र में भारत ने अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज कराई है। यूरेशियाई धरती पर यूरेनियम, दुर्लभ खनिजों और ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर हुए समझौते भारत की भावी तकनीकी और औद्योगिक क्रांति की रीढ़ साबित होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों, आधुनिक ग्रिडों, उन्नत इलेक्ट्रानिक्स और रक्षा हार्डवेयर के निर्माण के लिए आवश्यक इन खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक अभेद्य कवच प्रदान किया है। उज्बेकिस्तान के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 1.3 अरब डालर से बढ़ाकर पांच अरब डालर से अधिक करने का लक्ष्य अब मात्र एक नारा नहीं, बल्कि समयबद्ध और परखा हुआ विकास माडल बन चुका है। गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने और निवेश तंत्र को मजबूत करने के लिए बनी समन्वय समिति इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

'आतंकवाद पर दोहरे मानदंड' पर प्रहार : बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने आतंकवाद के नासूर पर करारा प्रहार किया। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में चेताया कि जो देश आतंकवाद को अपनी राष्ट्र-नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद कभी भी किसी की सामरिक संपत्ति नहीं हो सकता। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद के खात्मे के लिए 'सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपार्चुनिटी' के तीन स्तंभों पर जोर दिया गया। भारत की पहल पर स्वीकृत 'सुरक्षा मामलों के लिए यूनिवर्सल सेंटर' की स्थापना और आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती तथा कट्टरपंथ के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नेस्तनाबूद करने का आह्वान इस बात का प्रमाण है कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा में एक अग्रदूत की भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही, सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी और सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ 2030 तक चलने वाले कार्यक्रमों ने क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और पुख्ता किया है।

बिश्केक घोषणापत्र के 13 प्रमुख परिणामों में भारत के उन तमाम प्रस्तावों की गूंज स्पष्ट दिखाई दी, जो वसुधैव कुटुंबकम् की भावना पर आधारित हैं। अंग्रेजी को एससीओ की आधिकारिक भाषा के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने से लेकर एससीओ चार्टर में संशोधनों तक, भारत ने संस्थागत ढांचे को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जलवायु परिवर्तन के मोर्चों पर हुआ समझौता, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाले बयान और आपदा प्रबंधन में मानवीय सहायता से जुड़े समझौते भारत के वैश्विक उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं।

ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज : उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यह यात्रा केवल कूटनीति और रणनीतिक समझौतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भारत की प्राचीन सभ्यताओं और सांस्कृतिक जुड़ाव के पुनर्जागरण का भी प्रतीक थी। बिश्केक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना और वहां के प्रवासी भारतीयों तथा स्थानीय नागरिकों से प्रधानमंत्री का भावपूर्ण संवाद इस बात की तस्दीक करता है कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें दुनिया के हर कोने में प्रेम और सद्भाव का संदेश फैला रही हैं। इस वर्ष के अंत में भारत द्वारा आयोजित होने वाला 'एससीओ सिविलाइजेशन डायलाग फोरम' और युवा विज्ञानियों का मंच इस बात का प्रतीक है कि भारत केवल आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि विचारों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। मंगोलिया, तजाकिस्तान, अजरबैजान, लाओस और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों ने यह सिद्ध कर दिया कि आज का नया भारत अपने मित्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह तत्पर है। बिश्केक और ताशकंद की यह ऐतिहासिक यात्रा आने वाले दशकों में यूरेशियाई क्षेत्र की दशा और दिशा तय करने के साथ-साथ भारत को ग्लोबल साउथ की सबसे सशक्त और विश्वनीय आवाज के रूप में स्थापित करती है।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को दी एक नई ऊंचाई। फाइल

भारत एवं मध्य एशिया की अटूट मित्रता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मध्य एशिया की हालिया चार दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा केवल कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आत्मीय संबंधों के जीवंत उत्सव में बदल गई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को भारत की प्राचीन कला, समृद्ध साहित्य, लोक संस्कृति और उत्कृष्ट शिल्प कौशल से जुड़े ऐसे अनमोल उपहार भेंट किए, जिन्होंने दोनों देशों के दिलों को एक सूत्र में पिरो दिया। इन उपहारों में केवल जड़ वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि भारत के महान आत्मा, उसकी मिट्टी की महक और यहां की सांस्कृतिक धरोहर की गंध समाहित थी।

इस यात्रा के सबसे भावुक पलों में एक था किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादीर झापारोव को विवेक देबराय द्वारा अंग्रेजी में अनुदित 'महाभारत' के 10 संस्करण भेंट करना। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित यह महान ग्रंथ भारतीय दर्शन, धर्म, कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का वह शाश्वत स्रोत है, जो पीढ़ियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। किर्गिस्तान के प्रसिद्ध महाकाव्य 'एपिक आफ मनास' के साथ इसकी आत्मीय गूंज साफ महसूस की जाती है, क्योंकि दोनों ही महाकाव्य पीढ़ियों से अपनी साझा स्मृतियों और मूल्यों को सहेजते आए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति झापारोव को लद्दाख का पारंपरिक 'त्सुग-दुल' कंबल भी भेंट किया गया। ऊंचे पहाड़ों और घुमंतू जीवनशैली के बीच बुना गया यह गर्म ऊनी वस्त्र किर्गिस्तान के पर्वतीय जीवन के साथ एक गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक ताना-बाना बुनता है। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री को भेंट की गई 'डोकरा आर्टवर्क' (धातु कला) भारत की प्राचीन लुप्त-मोम ढलाई तकनीक का बेजोड़ नमूना है। पारंपरिक संगीतकारों को दर्शाती यह कलाकृति दोनों समाजों में संगीत के गहरे सांस्कृतिक महत्व को बयां करती है।

उज्बेकिस्तान की धरती पर कदम रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति शवकत मिर्जोयेव को एक चंदन की 'शता तंत्री वीणा' यानी संतूर भेंट की। जम्मू-कश्मीर की संगीत परंपरा से जुड़ा यह वाद्य यंत्र उज्बेकिस्तान के पारंपरिक 'चांग' से अद्भुत समानता रखता है, जो दोनों देशों के संगीत प्रेमियों के बीच के अनकहे संगीत को जीवंत करता है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी की प्रसिद्ध ब्लैक और ग्रीन टी के बक्से भी भेंट किए गए, जिनकी महक हिमालयी क्षेत्रों की प्राकृतिक ताजगी का अहसास कराती है। इस उपहार सूची में एक बेहद खास और दिल को छू लेने वाला तोहफा उज्बेकिस्तान के युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव के लिए था। गोवा में आयोजित 2025 फिडे विश्व कप के फाइनल मुकाबले का वह मूल हस्तलिखित स्कोरशीट, जिसे ऐतिहासिक जीत के बाद सुरक्षित किया गया था, उज्बेकिस्तान की खेल भावना को भारत द्वारा अनूठी श्रद्धांजलि थी।

रिश्तों की इस मिठास को और आगे बढ़ाते हुए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को आगरा के संगमरमर की जड़ाई कला से सजी डिब्बी और वाराणसी की मनमोहक बनारसी सिल्क की शाल भेंट की गई। सफेद संगमरमर पर पत्थरों की बारीक नक्काशी उज्बेकिस्तान की भव्य वास्तुकला की याद दिलाती है। उनकी पुत्री को भारतीय आभूषण कला का परिचय देती एक सुंदर चांदी की ब्रोच दी गई, जबकि उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री को संगमरमर की ही एक खूबसूरत सजावटी प्लेट भेंट की गई। बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल कूटनीतिक दायरे से बाहर निकलकर दो सभ्यताओं के बीच के सच्चे प्रेम, आदर और भाईचारे की मिसाल बन गई। इन उपहारों के जरिये भारत ने यह संदेश दिया कि भौगोलिक दूरियां चाहे जितनी भी हों, कला, साहित्य और संस्कृति के धागे दिलों को हमेशा पास ले आते हैं।

(श्री राम शा)

खरी-खरी

फूफा के खुश होने की सीमा

डा. प्रदीप मिश्र

फूफा को सम्मान बुआ से विवाह के समय से ही मिलना शुरू हो जाता है। पहले बुआ का मान, फिर फूफा का सम्मान। मतलब डबल इंजन वाला सम्मान। इसी अति-सम्मान की वजह से फूफा की न्यूसेंस-वैल्यू काफी ऊंची हो जाती है।

उनके आगे हाथ जोड़ें तो चरण-स्पर्श की चाह में उनका मुंह फूलता है। खाने में रसगुल्ले मिलें तो रबड़ी न मिलने की बात बनाते हैं। विदाई में ग्यारह सौ रुपये मिलें तो हिकारत की नजरों से देखते हैं कि क्यों दे रहे हैं? यही ट्रीटमेंट इक्कीस सौ, इक्यावन सौ, ग्यारह हजार के साथ होता है। अपने खुश होने की सीमा फूफा खुद भी नहीं जानते? नहीं खुश होने के तमाम तरीकों पर फूफाओं को पीएचडी की उपाधि मिल सकती है।

मैंने फूफा को सूचित किया, 'आपका रिजर्वेशन एसी फर्स्ट क्लास में करवाकर कंफर्म टिकट कूरियर से भेज दिया है। जरूर आइएगा।' स्टेशन पर लेने गया तो फूफाजी मालगाड़ी से उतरते दिखे। मैंने पूछा, 'आपको तो एसी फर्स्ट क्लास से उतरना चाहिए था?' फूफा सकपकाए। उन्हें इस तरह पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फूफा तो फूफा, दबंगई से बोले, 'ऐसा रिजर्वेशन कराया था कि एसी फर्स्ट क्लास क्या, किसी भी क्लास में मेरी सीट नहीं थी।' 'रिजर्वेशन तो कंफर्म था, फिर आपको सीट क्यों नहीं मिली?' मुझे आश्चर्य हो रहा था। फूफा नाराज हुए, 'मुझे क्या पता? मैं क्या रेल मंत्री हूं?' मैंने कहा, 'ऐसा कैसे होगा कि कंफर्म रिजर्वेशन में आपको सीट न मिले?'

'मैं पागल हूं न? तुम लोग तो यही समझते हो? रिजर्वेशन होता तो मैं उसमें क्यों नहीं आता? वो तो कहिए मालगाड़ी का ड्राइवर मेरा दोस्त निकल आया तो मटर-टमाटर के डिब्बे में मुझे भी भरकर ले आया, वरना तुम लोगों ने तो नहीं आने देने का पूरा षड्यंत्र रच लिया था। अब भूलकर भी यहां नहीं झांकूंगा।' हर फूफा, हर बार यही कहता है? बाद में रहस्योद्घाटन हुआ कि उन्होंने टिकट कैंसिल करवा कर पैसे वापस ले लिए थे। विज्ञजन, प्रथम स्थान किसे देंगे...शकुनि मामा को या नाराज फूफा को?

पोस्ट

भारतीय सड़कों पर चल रही हर एक बाइक-स्कूटर और कार में डैशकैम लगा ही होना चाहिए। अगर कैमरे की फुटेज नहीं होती तो गुरुग्राम में पीड़ित बाइकर लड़की वाला प्रकरण कभी इस तरह सामने नहीं आ पाता।
संकेत उपाध्याय@sanket

लेन-देन की भले ही जिस सीमा पर यूपीआइ शुल्क लगाया जाए, लेकिन उससे एक गलत संदेश ही जाएगा। इसके पीछे कारण चाहे जो भी गिनाए जाएं, मगर व्यापक स्तर पर यह एक बड़ी राजनीतिक भूल होगी। एनपीसीआइ घाटे में नहीं चल रहा कि 2000 रुपये से ऊपर के लेनदेन पर शुल्क वसूला जाए। यह दलील भी टिकने वाली नहीं है कि यह शुल्क मर्चेंट वहन करेगा, क्योंकि व्यापारी किसी न किसी तरह इसकी लागत का बोझ आम उपभोक्ताओं पर ही डालेंगे।
नवरूप सिंह@TheNavroopSingh

सरकारी सेवा की परिचालन लागत तो देनी ही पड़ेगी। वरना सरकार का घर तो होता नहीं कि वह सर्वर, इंटरनेट, कर्मचारी, आफिस आदि पर खर्चा करेगी, चार पैसे बैंक को न मिलें तो वे भी क्यों भला बेहतर सुविधा देंगे?
निखिल कुमार दुबे@nikhildubei

जागरण जनमत — कल का परिणाम

आतंकी मसूद अजहर पर इनाम घोषित करना पाकिस्तान का एक दिखावा ही है?

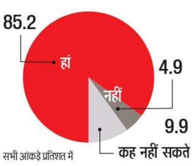

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या एक निश्चित सीमा से ऊपर के यूपीआइ भुगतान पर शुल्क से नकदी पर निर्भरता बढ़ेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

सारे मुद्दे खो गए लगा न कुछ भी हाथ,
राहुल तभी उठा रहे 'नानवेज' की बात।
'नानवेज' की बात विचारों से सिर खाली,
सब करते तारीफ मगर वे देते गाली।
स्वयं न सकें विचार बुद्धि से अपनी हारे,
चौपट उनको आज कर रहे चमचे सारे!

चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ीं मुश्किलें

रविंद्र बड़थ्वाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में अगले विधानसभा चुनाव से तकरीबन पांच माह पहले एक नया मोड़ आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के निजी सचिव के आवास पर ईडी की कार्रवाई के बाद उपजे राजनीतिक हालात में पार्टी सकते में है। जिन मुद्दों को हथियार बनाकर पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश की भाजपा सरकारों पर हमले बोल रही है, उनकी धार को कुंद होने से बचाने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती घोटाले और मनी लांड्रिंग से जुड़ी ईडी की कार्रवाई है। यहां राजनीतिक गलियारों में एक सवाल यह भी तैर रहा है कि इस कार्रवाई के आलोक में चुनाव में समर्थकों को टिकट दिलाने, स्वयं चुनाव लड़ने या पार्टी का चेहरा तय करने समेत दावेदारी के किसी भी मोर्चे पर हरीश रावत की भूमिका अब क्या रहेगी? राजनीतिक दृष्टि से मोल-भाव करने की उनकी क्षमता के लिए भी यह समय अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।

कांग्रेस के लिए प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव करो या मरो सरीखा है। लगातार तीसरा चुनाव हारकर अगले पांच वर्षों तक सत्ता से दूर रहने की नौबत आई तो बचे-खुले जनाधार को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा, पार्टी की असल चिंता भी यही है। इसीलिए मुद्दों के बियाबान में ऐसे मुद्दों पर दांव खेला जा रहा है, जिनके आधार पर केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति में बदलाव का मजबूत आधार तैयार किया जा सके। नीट पेपरलीक प्रकरण के बाद युवाओं में पैठ मजबूत करने की पार्टी की हसरतें जोर मार रही हैं। इस मुद्दे पर पार्टी के आक्रामक रुख को पूर्व मुख्यमंत्री रावत के निजी सचिव चंदन सिंह जीना के आवास पर ईडी की कार्रवाई से झटका लगा है। कार्रवाई के पांच दिन गुजरने के बाद पार्टी के एक भी केंद्रीय नेता ने इस मामले में चुप्पी नहीं तोड़ी। प्रदेश में भी पार्टी क्षत्रपों ने इस घटना को प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन खुलकर कुछ भी बोलने से गुरेज किया है। भ्रष्टाचार और पेपरलीक पर आक्रामक प्रदेश संगठन मनी लांड्रिंग के इस प्रकरण से दूरी बनाता दिखाई देता है।

हरीश रावत, कांग्रेस नेता एवं पूर्व सीएम। फाइल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में छात्रों की गूंज के जिस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, इस हिमालयी राज्य में उसकी धमक धीमी पड़ेगी या युवा मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस नेतृत्व और प्रदेश संगठन अपनी अब तक जारी अलग ही धुन में आगे बढ़ना जारी रखेगा, इस पर टकटकी बंध गई है। प्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की दृष्टि से भी यह मामला अलग रंग लिए हुए है। 79 वर्षीय हरीश रावत का दावा है कि वह कांग्रेस की राजनीति में 60 वर्ष से सक्रिय हैं। यह भी सच है कि उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष की अवधि में कांग्रेस की राजनीति उनके इर्द-गिर्द घूमी।

वर्ष 2022 में भी विधानसभा चुनाव से पहले तमाम उतार-चढ़ाव एवं विरोध के बावजूद पार्टी ने उन्हें ही प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। यद्यपि वर्ष 2016 में हुए उनके स्टिंग आपरेशन के बाद विरोधियों को उन्हें निशाने पर खूब मौका मिला। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया। पार्टी के रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि स्टिंग के बाद अब मनी लांड्रिंग पर उनके पीए पर ईडी की कार्रवाई पार्टी की अंदरूनी और बाहरी राजनीति पर उनकी पकड़ के लिए चुनौती से कम नहीं है। पार्टी हाईकमान ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी भूमिका को अभी तक बेहद सीमित रखा है। अभी तक गठित किसी भी महत्वपूर्ण समिति का वे हिस्सा नहीं हैं। ईडी की कार्रवाई के तुरंत बाद ही उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति एवं प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य के अपने पदों से त्यागपत्र की पेशकश कर दी।

कांग्रेस युवा मतदाताओं से बड़ी उम्मीदें बांधे हुए है। अभी तक प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड, मोहम्मद दीपक और शुद्धीकरण को बड़े मुद्दे उठाकर पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार और सत्तारूढ़ दल पर दबाव बढ़ाने में खूब ताकत झोंकी। यह अलग बात है कि इन मुद्दों पर एंटी इनकंबेंसी को उभारने में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अंकिता भंडारी प्रकरण पर सक्रियता दिखाते हुए आरोपितों को जेल भेजने से लेकर सीबीआइ जांच की संस्तुति के सरकार के कदम को एंटी इनकंबेंसी के काट के तौर पर देखा गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में रैली के तीन दिन बाद सभा स्थल के शुद्धीकरण को विपक्षी पार्टी ने तूल तो दिया, लेकिन शुद्धीकरण में दलित समाज के ही युवाओं के जुड़े होने और रैली को लेकर हल्द्वानी में ओबीसी वर्ग से आने वाले एसएसपी के विरुद्ध कांग्रेस के रवैये को मुद्दा बनाकर भाजपा ने ही पलटवार कर दिया। अब 10 वर्ष पहले भर्ती घोटाले में मनी लांड्रिंग की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के हाथ से एक और बड़ा मुद्दा फिसलता लग रहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें भी इसने बढ़ा दी हैं।

मंथन

कचरे के ढेर में छिपी आर्थिकी

कचरा प्रबंधन में अब यह भी देखना चाहिए कि उसमें से कितना संसाधन के रूप में वापस आया, कितनी सामग्री दोबारा इस्तेमाल हुई, कितने नए कारोबार खड़े हुए

संजिव कुमार
ठोस कचरा प्रबंधन के विशेषज्ञ

आज से ढाई दशक पहले तक भारत में कचरे का मतलब होता था उसे शहर से बाहर ले जाकर फेंक देना। वर्ष 2000 में जब नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम लागू हुआ तो पहली बार देश में कचरा प्रबंधन का व्यवस्थित नियामक ढांचा तैयार हुआ, परंतु उस वक्त भी मुख्य चिंता कचरे के सुरक्षित निपटान की ही थी। आज स्थिति बदल गई है। अब बात कचरे को फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे कमाई करने की जरूरत है। कचरा प्रबंधन में यह परिवर्तन केवल नियमों या तकनीक का नहीं, बल्कि सोच में बदलाव का है। कचरे के ढेर में अब कागज, प्लास्टिक, धातु, जैविक पदार्थ और ऊर्जा के साथ रोजगार और कारोबार की संभावनाएं भी दिखाई देने लगी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने इस बदलाव को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया और अब देश सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

वर्ष 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ने कचरा प्रबंधन को नगर निकायों के सीमित दायरे से निकालकर राष्ट्रीय अभियान में तब्दील कर दिया है। इसका असर कचरा संग्रह और प्रसंस्करण दोनों में दिख रहा है। घर-घर कचरा संग्रह महज एक दशक में ही लगभग 98 प्रतिशत शहरी वार्डों तक पहुंच चुका है। करीब 2.5 लाख संग्रह वाहन इस व्यवस्था में लगे हैं। इसी अवधि में ठोस कचरे का प्रसंस्करण लगभग 16 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में करीब 80 प्रतिशत हो गया। कचरा संग्रह और प्रसंस्करण का इतना बड़ा नेटवर्क अपने साथ आर्थिक गतिविधियों का एक पूरा चक्र लेकर आया है। कचरा उठाने के लिए वाहन, चालक और कर्मचारी चाहिए। उसे अलग-अलग करने के लिए छंटाई केंद्र चाहिए। प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए इंजीनियर, तकनीशियन और आपरेटर चाहिए। इसके अलावा परिवहन, मशीनरी, रखरखाव और लाजिस्टिक्स से जुड़े कारोबार भी पैदा होते हैं। यानी कचरा प्रबंधन अब सिर्फ खर्च का ही विषय नहीं है। सही व्यवस्था के साथ यह रोजगार और आर्थिक गतिविधि का स्रोत भी बन गया है।

वर्ष 2016 में बने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम ने इस सोच को और आगे बढ़ाया। स्रोत से कचरे को अलग करने, रिसाइकल करने, मटेरियल रिकवरी, कंपोस्टिंग, बायोमीथेनेशन, आरडीएफ और ऊर्जा उत्पादन जैसे विकल्पों को बढ़ावा मिला है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि लैंडफिल कचरे की पहली मंजिल नहीं, आखिरी विकल्प होना चाहिए। कचरे के अर्थशास्त्र को ऐसे समझने की जरूरत है कि अगर इसे शुरुआत में ही अलग कर दिया जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। गीले कचरे से खाद, बायोगैस और सीबीजी बन सकती है। इसी तरह सूखे कचरे से कागज, प्लास्टिक और धातु जैसी सामग्री निकाली जा सकती है और ज्वलनशील हिस्से से ईंधन तैयार हो सकता है। निर्माण और तोड़फोड़ से निकले मलबे को भी प्रसंस्करण के बाद फिर से निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जिस कचरे को हम कूड़ेदान में डालकर खत्म मान लेते हैं, वह किसी उद्योग के लिए कच्चा माल भी हो सकता है। यहीं पर कचरा प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ते हैं। सामग्री को इस्तेमाल करने के बाद फेंकने के बजाय उसे फिर उत्पादन चक्र में लाया जाता है।

कचरा प्रबंधन में उद्यमिता के नए रास्ते खुले हैं। कुछ साल पहले तक बहुत कम युवा इसे कारोबार या करियर के क्षेत्र के रूप में देखते थे। अब स्टार्टअप और नई कंपनियां इस क्षेत्र में भी तकनीकी समाधान लेकर आ रही हैं। कचरा संग्रह क्षेत्र में आटोमेटेड सार्टिंग, प्लास्टिक रिकवरी, डिजिटल ट्रेसबिलिटी, डंपसाइट की बायोमाइनिंग, विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण और इंटरनेट आफ थिंग्स आधारित काम हो रहा है। मतलब युवा पीढ़ी नई तरह का उद्यम लेकर आ रही है, जिसे 'वेस्टप्रेन्योर' कहा जा सकता है। वह कचरे के ढेर में केवल गंदगी नहीं देखता है, बल्कि उसमें मौजूद आर्थिक मूल्य को पहचानता है। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के पहले समूह के 30 स्टार्टअप ने करीब 63 हजार टन से भी अधिक कचरे का प्रबंधन किया और दो हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए। यह इस बात का संकेत है कि कचरा प्रबंधन में तकनीक और निजी उद्यम की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था के वर्ष 2050 तक लगभग दो ट्रिलियन डालर तक पहुंचने और लगभग एक करोड़ रोजगार पैदा करने की क्षमता का अनुमान है। ठोस कचरा इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं तय होता है कि कोई सामग्री अर्थव्यवस्था से बाहर चली जाएगी या दोबारा उत्पादन चक्र में लौटेगी। कचरे को फेंकने की चीज मानने के बजाय अगर संसाधन मान लिया जाए तो स्वच्छ भारत की अगली मंजिल सर्कुलर भारत हो सकती है।

रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का स्रोत बनता कचरा प्रबंधन। फाइल

फ्लिपकार्ट ने 2.5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित कीं

नई दिल्ली: ई-कामर्स प्लेटफार्म फ्लिपकार्ट ने आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर 2.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं। इसमें लगभग 75 हजार या 30 प्रतिशत पद ऐसे हैं, जो पहली बार कार्यबल में शामिल हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत बद्री ने कहा कि नए पदों में करीब 60 प्रतिशत अंतिम पायदान तक डिलीवरी श्रेणी से जुड़े होंगे। कंपनी ने त्योहारी सीजन के लिए 900 नए वितरण हब जोड़े हैं। (प्रेट्र)

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश करके भारतीय अर्थव्यवस्था 'मध्यम-आय वाले जाल' से बाहर निकल सकती है।
– थामस पिकेटी, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलो ग्राम	डालर	क्रूड प्रति बैरल
74,003.82 ▼ 777.94	23,118.60 ▼ 279.50	₹ 1,54,400 ▼ ₹ 1,000	₹ 2,34,600 बदलाव नहीं	₹ 95.88 ▲ ₹ 0.34	$ 107.7

टाटा संस के सूचीबद्ध होने की संभावना से समूह के कई शेयर चढ़े

मुंबई, रायटर: टाटा संस के सूचीबद्ध होने की संभावना बढ़ने के चलते मंगलवार को टाटा समूह की कई कंपनियों के शेयर चढ़ गए। बता दें कि केंद्रीय बैंक ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफएसी) के तौर पर पंजीकरण को रद करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। समूह की 31 कंपनियों की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की संभावित लिस्टिंग से सूचीबद्ध टाटा कंपनियों खासकर उन कंपनियों का मूल्यांकन बढ़ सकता है, जिनके पास पैरेंट कंपनी में हिस्सेदारी है। टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और टाटा इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में से हैं जिनके पास टाटा संस में हिस्सेदारी है।

मंगलवार को टाटा केमिकल्स के शेयर 20 प्रतिशत तक बढ़ गए, जबकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर 11.5 प्रतिशत बढ़े। आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज के अनुसार, टाटा केमिकल्स दो से ढाई महीने के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। टाटा केमिकल्स की टाटा संस में लगभग 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि यह हिस्सेदारी 100 अरब रुपये से 150 अरब रुपये (1.04 अरब से 1.56 अरब डालर) के बीच है, जो टाटा केमिकल्स के मौजूदा बाजार पूंजीकरण के करीब है। हालांकि, आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज का मानना है कि टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चल सकती है। 100 साल से ज्यादा पुरानी होल्डिंग कंपनी ने निजी क्षेत्र में ही बने रहने की इच्छा जताई है।

- उन कंपनियों के शेयर ज्यादा चढ़े, जिनकी टाटा संस में है हिस्सेदारी
- टाटा केमिकल्स के शेयर 20% तक बढ़े, टाटा मोटर्स में चार प्रतिशत की तेजी

आरबीआइ ने टाटा संस को माना है एक निवेश कंपनी

आरबीआइ ने टाटा संस को एक शुद्ध निवेश कंपनी के तौर पर वर्गीकृत किया है और यह गैर-बैंक ऋणदाता के लिए उसके बनाए गए नियमों के तहत है। आरबीआइ के नियमों के तहत एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति वाली कंपनियों का सूचीबद्ध होना जरूरी है। टाटा संस पर अपने शेयरधारकों की तरफ से भी सूचीबद्ध होने का दबाव है। शापूरजी पलोनजी समूह टाटा संस में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा के दो ट्रस्टियों ने हाल ही में अपने मीडिया इंटरव्यू में टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर में विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत होगी, जिसे आंतरिक रूप से जुटाना संभव नहीं होगा।

आरबीआइ ने बांबे हाई कोर्ट में दाखिल की कैविएट

मुंबई, रायटर: आरबीआइ ने टाटा संस की लिस्टिंग से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई से पहले बांबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसे कानूनी भाषा में कैविएट कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा मामला टाटा संस की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के तौर पर उसके पंजीकरण को रद करने के आवेदन को खारिज करने के बाद उठाया गया है। अब अगर समूह आरबीआइ के फैसले को कोर्ट में चुनौती देता है या स्टे मांगता है तो न्यायालय कोई भी फैसला देने से पहले आरबीआइ का पक्ष जरूर सुनेगा। सूत्रों के मुताबिक टाटा समूह के अंदर की कुछ कंपनियां लिस्टिंग का विरोध कर रही हैं।

अब कल होने वाली बोर्ड बैठक पर सबकी नजरें

मुंबई, प्रेट्र: अब सबकी नजरें 17 सितंबर को मुंबई में होने वाली टाटा संस की बोर्ड मीटिंग पर है। इस दौरान तीन जरूरी मुद्दों चर्चा हो सकती है। इसमें आरबीआइ के फैसले के बाद टाटा संस की लिस्टिंग, एन चंद्रशेखरन के चेयरमैन बने रहने पर अनिश्चतता और दो मुख्य टाटा ट्रस्ट में से एक में गवर्नेंस संबंधी चिंताएं। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा होल्डिंग कंपनी टाटा संस की किसी भी संभावित लिस्टिंग का साफ विरोध कर रहे हैं। खबर है कि उन्होंने इस साल फरवरी में टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल का नवीनीकरण करने के लिए इसे अपनी पूर्व शर्त के तौर पर रखा था। चंद्रशेखरन ने अगला कार्यकाल लेने से मना कर दिया है।

सेंसेक्स 778 अंक लुढ़का, निफ्टी पांच माह नीचे

मुंबई, प्रेट्र: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 777.94 अंक या 1.04 प्रतिशत टूटकर तीन महीने के निचले स्तर 74,003.82 पर आ गया जबकि निफ्टी 279.50 अंक या 1.19 प्रतिशत गिरकर पांच महीने के निचले स्तर 23,118.60 पर बंद हुआ। निफ्टी का यह स्तर छह अप्रैल के बाद का सबसे निचला बंद स्तर है।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में भारत इलेक्ट्रानिक्स के शेयर में करीब छह प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), टाइटन, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, एचसीएल टेक्नोलाजीज 3.98 प्रतिशत, इन्फोसिस 3.64 प्रतिशत, टेक महिंद्रा 2.31 प्रतिशत, टीसीएस 2.18 प्रतिशत और एचडीएफसी बैंक 1.27 प्रतिशत चढ़े। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 107.7 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बढ़ते वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल से निवेशक धारणा प्रभावित होने के कारण घरेलू बाजार में गिरावट जारी रही। हालांकि, एआइ के विकास की रफ्तार धीमी होने संबंधी टिप्पणियों से पारंपरिक आइटी सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका कुछ कम हुई, जिससे आइटी शेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए

रुपया 34 पैसे लुढ़ककर 95.88 प्रति डालर पर

मुंबई, प्रेट्र: विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया मंगलवार को डालर के मुकाबले 34 पैसे लुढ़ककर 95.88 पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और ब्रेंट क्रूड की ऊंची कीमतों से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि तेल आयातकों की ओर से डालर की बढ़ती मांग ने भारत के बाहरी संतुलन और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा घरेलू बाजारों में कमजोरी, अमेरिकी डालर में मजबूती और वैश्विक बांड पर प्रतिफल बढ़ने की वजह से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। रुपया शुक्रवार को डालर के मुकाबले 95.54 पर बंद हुआ था। मिरे एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि निवेशक बुधवार को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के फैसले से पहले सतर्क रह सकते हैं।

एक नजर में

पांच सप्ताह के निचले स्तर पर सोना, चांदी स्थिर रही

नई दिल्ली: कमजोर वैश्विक संकेतों और अमेरिकी डालर में मजबूती के चलते मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में एक हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई। अब इसका मूल्य करीब सप्ताह के निचले स्तर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। सात अगस्त को भी इसका मूल्य इसी के आसपास था। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, दिल्ली में चांदी की कीमत लगातार 2,34,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही है। (प्रेट्र)

जुलाई में सात अरब डालर रहा चालू खाता घाटा

मुंबई: इस वर्ष जुलाई में देश का चालू खाता घाटा करीब दोगुना बढ़कर सात अरब डालर रहा है। इसमें ज्यादा वस्तु व्यापार घाटे का प्रमुख योगदान रहा है। आरबीआइ के अनुसार, जुलाई 2026 में वस्तु व्यापार घाटा 31.7 अरब डालर था, जो पिछले वर्ष समान महीने में 28.2 अरब डालर था। जुलाई 2026 में कुल वस्तु आयात 76.8 अरब डालर और निर्यात 45.1 अरब डालर था। डाटा के अनुसार, जुलाई 2026 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 7.3 अरब डालर रहा है जो पिछले वर्ष समान महीने में 4.5 अरब डालर था। (प्रेट्र)

अगस्त में वनस्पति तेल आयात में 4.7% की गिरावट

नई दिल्ली: इस वर्ष अगस्त में वनस्पति तेल आयात में 4.71 प्रतिशत की गिरावट रही है और कुल 16.09 लाख टन तेल का आयात किया गया है। उद्योग संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के अनुसार, यह गिरावट पाम तेल के आयात में कमी के कारण हुई है। अगस्त 2025 में 16.94 लाख टन वनस्पति तेल का आयात किया गया था। यह गिरावट पाम तेल की शिपमेंट में कमी के कारण हुई है। विपणन वर्ष 2025-26 में नवंबर से अगस्त तक कुल वनस्पति तेल आयात चार प्रतिशत बढ़कर 138.8 लाख टन रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 133.37 लाख टन था। (प्रेट्र)

पांच महीने के निचले स्तर पर आया व्यापार घाटा

पिछले महीने 26.86 अरब डालर रहा व्यापार घाटा, निर्यात 26.12% बढ़कर 43.81 अरब डालर रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में तेज वृद्धि से अगस्त में देश का वस्तु निर्यात 26.12 प्रतिशत बढ़कर 43.81 अरब डालर हो गया। वहीं, सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर पांच महीने के निचले स्तर 26.86 अरब डालर पर आ गया। अगस्त में आयात साल-दर-साल 14.1 प्रतिशत बढ़कर 70.76 अरब डालर रहा। अगस्त में निर्यात में वृद्धि जून 2022 के बाद सबसे ज्यादा रही। उस समय निर्यात में 30.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पिछले महीने ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें 90 से 94 डालर के बीच रही।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान निर्यात साल-दर-साल 17.85 प्रतिशत बढ़कर 215.91 अरब डालर हो गया और आयात 18.21 प्रतिशत बढ़कर 363 अरब डालर हो गया। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 147.09 अरब डालर हो गया, जबकि अप्रैल-अगस्त 2025-26 के दौरान यह 123.88 अरब डालर था। अगस्त 2025 में व्यापार घाटा 27.22 अरब डालर था। जुलाई में यह 31.98 अरब डालर था। पिछला सबसे कम व्यापार घाटा इसी साल मार्च में 20.67 अरब डालर था। पिछले साल अगस्त में सोने का आयात 5.4 अरब डालर था जो अबकी बार घटकर 2.3 अरब डालर रह गया और इस तरह इसमें 57.7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

पांच महीनों में 95.57 अरब डालर के कच्चा तेल आयात : अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान कच्चे तेल का आयात पिछले साल की समान अवधि के 78.07 अरब डालर से बढ़कर 95.57 अरब डालर हो गया। इलेक्ट्रानिक सामान का आयात भी अप्रैल-अगस्त 2025-26 के दौरान 46.31 अरब डालर से बढ़कर 66.48 अरब डालर हो गया है। निर्यात की बात करें तो पेट्रोलिमय उत्पादों का निर्यात अप्रैल-अगस्त 2026-27 के दौरान पिछले साल की समान अवधि के 25.32 अरब डालर से बढ़कर 35.31 अरब डालर हो गया है।

ब्रिक्स देशों को निर्यात 13.30 प्रतिशत बढ़ा : वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि 2026-27 के पहले पांच महीनों में ब्रिक्स देशों को भारत का निर्यात 13.3 प्रतिशत बढ़कर 34.5 अरब डालर हो गया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से भी अच्छी मांग आई है। निर्यात वृद्धि की अच्छी रफ्तार जारी है और यह बढ़ भी रही है। उन्होंने कहा कि पांच महीनों में ज्यादा आयात की वजह मजबूत घरेलू आर्थिक वृद्धि, बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की तेज वृद्धि है। इससे व्यापार घाटा भी बढ़ा है। व्यापार घाटे के मुख्य कारण पेट्रोलिमय, क्रूड और कोयला, कोक व ब्रिकेट और इलेक्ट्रानिक्स सामान जैसे ऊर्जा उत्पाद रहे हैं।

- अगस्त में निर्यात में वृद्धि जून 2022 के बाद सबसे ज्यादा, पिछले महीने ब्रेंट क्रूड 90-94 डालर रहा
- अप्रैल से अगस्त के दौरान निर्यात साल-दर-साल 17.85 प्रतिशत बढ़कर 215.91 अरब डालर हो गया

व्यापार चिंताओं को लेकर भारत-चीन में चर्चा शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत और चीन ने द्विपक्षीय व्यापार चिंताओं को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि दोनों पक्ष आगे की बातचीत के लिए और बैठकें आयोजित करने की उम्मीद कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके चीनी समकक्ष वांग वेंटाओ के बीच हाल की बैठक एक प्रारंभिक चर्चा थी।

अगले माह लागू हो सकता है भारत-न्यूजीलैंड एफटीए

नई दिल्ली, प्रेट्र: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अगले महीने के आखिर में लागू हो सकता है और इस संबंध में आधिकारिक तारीखों का एलान जल्द किया जाएगा। दोनों देशों ने 27 अप्रैल को एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

एंकर निवेशकों के लिए आज खुलेगा एनएसई का आइपीओ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: नशेनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का 22,569 करोड़ रुपये का आइपीओ एंकर निवेशकों के लिए आज खुलेगा। एनएई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि लिस्टिंग से पहले ही बड़े संस्थानों की मांग उम्मीद से ज्यादा है। इससे साफ है कि संस्थागत निवेशक एनएसई पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा, 'एंकर बुक काफी बड़ी है, जितनी हमने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा।'

एंकर बुक करीब 6,250 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जो पहले अनुमानित 9,000 करोड़ रुपये से कम है। निवेशकों की अंतिम सूची अभी तय हो रही है। एंकर बुक दरअसल आईपीओ खुलने से पहले चुनिंदा बड़े संस्थानों को आवंटित की जाने वाली हिस्सेदारी होती है। इसी से अंदाजा लग जाता है कि बाजार इश्यू को कितनी गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि लागू आरक्षण ढांचे के तहत घरेलू म्यूचुअल फंड, अन्य संस्थाओं और विदेशी निवेशकों के बीच शेयर बांटने होते हैं, इसलिए इस आकार के आइपीओ में उपलब्ध शेयर सीमित रह जाते हैं। सूत्रों के अनुसार गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पलटन और फिडेलिटी इंटरनेशनल जैसी बड़ी निवेश संस्थाओं ने शुरुआती दिलचस्पी दिखाई है। 2024 में हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के आईपीओ के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा इश्यू होगा। आम निवेशकों के लिए निर्गम 17-21 सितंबर तक खुलेगा। शेयर का मूल्य 1,700 से 1,785 रुपये प्रति इकाई है। ऊपरी स्तर पर एनएसई का मूल्यांकन करीब 4.42 लाख करोड़ रुपये बैठता है।

अपने प्लेटफार्म पर ट्रेड नहीं कर सकेगा एनएसई का शेयर : सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसई को अपने ही शेयरों को अपने प्लेटफार्म पर ट्रेडिंग के लिए सेबी से अनुमति लेनी होगी। हालांकि, इससे पहले सेबी ने बीएसई को भी इसकी अनुमति नहीं दी थी। न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग पर उन्होंने बताया कि दो लाख के बड़े शेयरधारक आधार के चलते लिस्टिंग के बाद 100 प्रतिशत फ्री फ्लोट रहेगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में शामिल होने पर मांग और बढ़ सकती है। चौहान ने माना कि भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट वाले दिन ज्यादा देखने को मिले हैं लेकिन दीर्घकालिक तौर पर भारत की इकोनमी को लेकर कोई संशय नहीं है।

- 22,569 करोड़ रुपये का निर्गम आम निवेशकों के लिए 17-21 सितंबर तक खुलेगा
- 1,700-1,785 रुपये प्रति शेयर होगा प्राइस बैंड, पूंजीकरण 4.42 लाख करोड़ होगा

एफपीआइ ने सरकारी बांड से 5,109 करोड़ निकाले

मुंबई, प्रेट्र: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने वैश्विक अनिश्चितता के कारण कमजोर भावनाओं के चलते पिछले तीन दिनों में सरकारी प्रतिभूतियों से लगभग 5,109.21 करोड़ रुपये निकाले हैं। पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत योग्य विदेशी निवेशकों को कुछ सरकारी प्रतिभूतियों को बिना किसी सीमा के खरीदने और बेचने की अनुमति है। क्लियरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के अनुसार, 15 सितंबर तक एफएआर के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआइ निवेश 3,66,806.286 करोड़ रुपये था, जबकि नौ सितंबर को यह 371,915.496 करोड़ रुपये था।

पिछले महीने बेरोजगारी दर मामूली कम होकर पांच प्रतिशत पर आई

नई दिल्ली, प्रेट्र: मंगलवार को जारी आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) के मुताबिक, अगस्त में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की कुल बेरोजगारी दर थोड़ी कम होकर पांच प्रतिशत हो गई।

15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की कुल बेरोजगारी दर जुलाई में 5.1 प्रतिशत थी। पिछले साल अगस्त में भी यह 5.1 प्रतिशत ही थी। इसी दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर महीने-दर-महीने 4.5 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई जबकि शहरी बेरोजगारी दर जुलाई के 6.7 प्रतिशत के मुकाबले अगस्त में 6.8 प्रतिशत पर लगभग स्थिर रही। अगस्त 2025 की तुलना में अगस्त 2026 में कुल बेरोजगारी दर और शहरी बेरोजगारी दर मोटे तौर पर स्थिर रही जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर अगस्त में 0.2 प्रतिशत घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई।

अगस्त में यात्री वाहनों की बिक्री 36% बढ़ी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पिछले साल सितंबर में की गई जीएसटी कटौती के फैसले की फसल अभी तक आटो कंपनियां काट रही हैं। इस वजह से त्योहारी सीजन की शुरुआत के पहले महीने यानी अगस्त, 2026 में आटोमोबाइल की बिक्री में 36.5 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई है। उद्योग संगठन सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) के अनुसार, घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की कंपनियों से डीलरों तक आपूर्ति पिछले साल के मुकाबले 36.5 प्रतिशत बढ़कर 4,39,309 यूनिट हो गई। अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 3,21,901 यूनिट था।

सियाम ने मंगलवार को कहा कि दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 10.5 प्रतिशत बढ़कर 20,34,698 यूनिट रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 18,41,954 यूनिट था। तिपहिया वाहनों की थोक बिक्री 22.8 प्रतिशत बढ़कर 93,764 यूनिट हो गई। पिछले साल इसी महीने यह 76,324 यूनिट थी।

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि यात्री वाहन, तिपहिया और दोपहिया, तीनों श्रेणियों में अगस्त 2026 अब तक का सबसे अच्छा अगस्त रहा है। भारतीय आटो उद्योग मजबूत वृद्धि के दौर से गुजर रहा है। अगस्त की तेज रफ्तार में पिछले साल का निम्न आधार भी सहायक रहा। अगस्त, 2025 में कई ग्राहकों ने जीएसटी कटौती की संभावना को देखते हुए खरीद स्थगित कर दी थी। उन्होंने कहा कि व्यापक मांग का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण बाजारों से भी जबरदस्त मांग आ रही है और वित्त की सुविधा भी बेहतर हुई है। इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन की मांग ने ग्राहकों का एक नया वर्ग तैयार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारी मांग से और तेजी आने की उम्मीद है, जिससे दूसरी तिमाही के आंकड़े भी अच्छे रहने चाहिए।

- जीएसटी कटौती और त्योहारों से वाहन कंपनियों की बिक्री में उछाल
- वैकल्पिक ईंधन की मांग ने ग्राहकों का एक नया वर्ग तैयार किया

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

आरबीआइ ने बैंकिंग प्रणाली से 3.93 लाख करोड़ रुपये निकाले

नई दिल्ली, प्रेट्र: आरबीआइ ने मंगलवार को परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के जरिये बैंकिंग प्रणाली से 3,93,352 करोड़ रुपये नकदी वापस ली। केंद्रीय बैंक को अधिसूचित पांच लाख करोड़ रुपये की राशि के लिए 3,93,352 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं। इन बोलियों को 5.24 प्रतिशत की 'कट-आफ' दर और भारित औसत दर पर स्वीकार किया गया।

11 सितंबर तक बैंकिंग प्रणाली में सरप्लस नकदी लगभग 10.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास थी। वीआरआरआर नीलामी के अलावा, केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए एक लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के तीन चरणों में खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) का एलान किया है। इसकी पहली नीलामी 17 सितंबर को होगी।

राष्ट्रीय फलक

गुमराह करने वाले विज्ञापनों व गलत तरीकों के लिए रैपिडो पर जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथारिटी (सीसीपीए) ने गलत व्यापार तौर-तरीकों और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने कहा कि रैपिडो के खिलाफ यह कार्रवाई भारत में काम करने वाले कैब और बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफार्म की पूरे सेक्टर में की गई जांच पर आधारित है। यह जांच प्री-राइड टिपिंग और डायनामिक प्राइसिंग से जुड़े तौर-तरीकों की जांच के लिए की जा रही है।

अथारिटी पहले ही उबर, ओला, रैपिडो और नम्मा यात्री जैसे प्लेटफार्म को नोटिस जारी कर चुकी है और उन्हें डार्क पैटर्न की रोकथाम और नियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023 का पालन करने का निर्देश दिया है। डार्क पैटर्न यूजर इंटरफेस के ऐसे डिजाइन होते हैं जो ग्राहकों को गुमराह करते हैं या उन्हें ऐसे फैसले लेने के लिए उकसाते हैं, जो वे असल में नहीं लेना चाहते थे। चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा की अगुवाई वाली सीसीपीए ने कहा कि इस मामले में उबर और ओला की जांच अभी चल रही है। अलग-अलग प्लेटफार्म की जांच के दौरान, अथारिटी ने पाया कि रैपिडो एप पर ऐसे मैसेज दिख रहे थे जैसे 'कीमत जितनी ज्यादा होगी, राइड मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी' और 'कैप्टन 60 में राइड स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्लस 10, प्लस 20, प्लस 30 जोड़कर देखें', जबकि राइडर की बुकिंग

- सीसीपीए ने कहा कि मामले में उबर और ओला की जांच अभी चल रही है

दिवालिया कानून के तहत कर्ज में बड़ी कटौती ईडी के निशाने पर

नीलू रंजन • जागरण

नई दिल्ली : दिवालिया कानून (इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड-आइबीसी) के तहत कर्ज देनदारी में बड़ी कटौती (हेयरकट्स) के मामले ईडी के निशाने पर हैं। ऐसे मामलों में आपराधिक साजिश के तहत प्रमोटरों को लाभ पहुंचाने और दिवालिया कंपनी को फिर से अपने स्वामित्व में लेने के मामलों में मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बेंगलुरू में हो रहे ईडी के क्षेत्रीय अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईडी निदेशक राहुल नवीन ने बड़े हेयरकट में आपराधिक साजिश का पता लगाकर पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने को कोर आपरेशन थ्रस्ट एरिया बताया।

एसेल ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा के ... को 6.50 करोड़ रुपये में निपटाने के बाद पहली बार ईडी के क्षेत्रीय अधिकारियों के सम्मेलन में एक पूरे सत्र में आइबीसी के (एनसीएलटी) में कर्ज की देनदारी निपटाने के मामलों में हो रही आपराधिक साजिश और उससे निपटने के लिए ... गया कि कैसे आइबीसी में संबंधित पार्टी के क्लेम को बढ़ाने, क्रेडिटर्स की समिति में गड़बड़ी, संपत्तियों की कीमत को कम दिखाने और कृत्रिम तरीके से बड़े हेयरकट के माध्यम से प्रमोटर्स को लाभ पहुंचाया जाता है। इसके चलते प्रमोटर्स बहुत कम देनदारी के बाद संपत्तियों को दोबारा हासिल कर लेता है।

सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों को आइबीसी के तहत बड़े हेयरकट के मामलों को चिह्नित करने व ऐसे मामलों में दस्तावेजों की जांच करने की जरूरत बताई गई। ऐसे मामलो में दिवालिया कानून के तहत हुई कार्रवाई में शामिल सभी आयामों की विस्तृत पड़ताल के बाद आइबीसी ट्रिब्युनल में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करने पर एक राय बनी। इसके अलावा बताया गया कि ऐसे मामलों में मास्टरमाइंड के खिलाफ पीएमएलए के तहत ईडी को स्वतंत्र

- बेंगलुरु में ईडी के क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक में आइबीसी की आड़ में हुई धोखाधड़ी पर विस्तृत चर्चा
- बड़ी कटौती की आपराधिक साजिश में शामिल मास्टरमाइंड के खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्रवाई पर जोर

ईडी यूनिटों की संख्या अब 131 से बढ़कर 241 हो जाएगी

सम्मेलन के दौरान ईडी निदेशक ने सरकार द्वारा एजेंसी के स्वीकृत पदों में दोगुना बढ़ोतरी का हवाला देते हुए कहा कि देशभर में अब काम करने वाले ईडी की यूनिट की संख्या 131 से बढ़कर 241 हो जाएगी। ये सभी यूनिट अगले साल एक जनवरी से काम करने लग जाएंगी। सरकार ने ईडी के मौजूदा 2029 पदों को बढ़ाकर 3256 कर दिया है। इसके साथ ही ईडी ने 31 मार्च 2029 तक सभी 39 बड़े शहरों में अपना कार्यालय भवन बनाने का भी लक्ष्य रखा है।

आइओएस 18 से जुड़ी आइफोन शिकायतों की सीसीपीए ने शुरू की जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने आइओएस 18 के जारी होने के बाद आइफोन यूजर द्वारा बताई गई तकनीकी समस्याओं की जांच शुरू कर दी है। नियामक ने पिछले साल एपल इंक को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा था, जिसमें सामने आई तकनीकी समस्याओं, उनके उभरने की समयसीमा और उनके समाधान के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

सूत्रों ने बताया कि नोटिस जारी होने के एक साल बाद भी समस्याएं बरकरार रहने के कारण सीसीपीए ने इस मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस बीच, लोकलसर्किल्स के सर्वे से पता चलता है कि जनवरी, 2025 में किए गए पिछले अध्ययन के बाद से आइफोन

फडणवीसांचा 'राव'क्षण!

'एमपीएससी' संदर्भात विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्यासाठी व्ही. राधा यांचा कृतीगट राज्यभर जाणार आहेच, पण आयोगाची अंतर्बाह्य साफसफाई करण्याचे सर्वाधिकार या गटाला द्यावेत...

महाराष्ट्राचा प्रशासकीय लौकिक गोपट्ट्यातील राज्यांशी स्पर्धा करू लागण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण राज्य लोकसेवा आयोगात सुरू झालेली दुकानदारी हे आहे. एकेकाळी राज्यातील सर्व सेवाभरती या लोकसेवा आयोगामार्फत होत असे आणि त्यात गुणवत्तेत तडजोड केली जात नसे. त्याचे महत्त्वाचे श्रेय तेव्हाच्या नेक अधिकाऱ्यांस जाते. आपल्या पदाचे इमान राखणारे एकापेक्षा एक उत्तम अधिकारी प्रशासनात होते आणि राजकीय नेतृत्वही अशांची कदर करत असे. त्यावेळी राज्य प्रशासनाच्या लौकिकाची तुलना उदाहरणच द्यावयाचे तर मुंबईच्या आणि देशाच्या क्रिकेट संघाशी करता येईल. एकेकाळी ज्या प्रमाणे राष्ट्रीय क्रिकेट संघापेक्षा मुंबईच्या क्रिकेट संघात स्थान मिळवणे अवघड मानले जात असे त्या प्रमाणे महाराष्ट्राचे प्रशासन हे राष्ट्रीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोरही आब राखून होते. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शरद पवार इत्यादींनी ही प्रशासकीय घडी कधी विस्कटू दिली नाही. तथापि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू शशिकांत कर्णिक यांच्यासारख्या विधिनिषेधशून्य व्यक्तीच्या हाती लोकसेवा आयोगाची धुरा दिली गेली आणि या महत्त्वाच्या संस्थेचा ऱ्हास सुरू झाला. तो अखंड सुरू असून आज तर या संस्थेची इभ्रत पार रसातळास गेल्याचे दिसते. चोराच्या हाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या दिल्यावर आणखी काय होणार; हे खरेच. त्याचमुळे राज्यभरातील विद्यार्थी वर्गात कमालीचा रोष आहे. तो कसा व्यक्त करावा याचा धडा 'जंतर-मंतर'ने घालून दिला असून राज्यातील विद्यार्थीही त्याच मार्गाने गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. ही दिल्लीतील इतिहासाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होऊ नये अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर लोकसेवा आयोगाच्या साफसफाईसाठी नेमलेल्या व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखालील कृतीगटास त्यांनी यासाठी सर्वाधिकार द्यावेत आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या शिफारशींची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे धाडस दाखवावे.

येथे 'धाडस' हा शब्दप्रयोग करण्याचे कारण म्हणजे लोकसेवा आयोगाच्या बदअमलात खुद्द फडणवीस यांच्या आसपासच्या अनेकांचे गुंतलेले हितसंबंध. ज्या प्रमाणे चांगले रस्ते हे कंत्राटदार आणि त्यांच्या आडून आपले अर्थकारण साधणारे राजकारणी यांच्या मुळावर येतात तद्वत सरकारातील पारदर्शी भरती प्रक्रिया अनेकांच्या उत्पन्नावर गदा आणते. हे कसे होते याचे निलाजरे उदाहरण कर्णिक यांच्या काळात जे घडले त्यात आहे. लोकसेवा आयोगात १९९९ साली पोलीस उपनिरीक्षक आणि अन्य पदांच्या भरती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला. ते प्रकरण इतके गंभीर होते की कर्णिक यांच्या समवेत तत्कालीन मंत्र्याच्या सचिवासह अन्य पाच जणांस तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यावेळच्या भरती प्रक्रियेत ३९८ उमेदवारांच्या उत्तर पत्रिकेत फेरबदल केल्याचा आरोप या सर्वांवर होता. त्यातून पुढे अनेकांस शासनही झाले. तेथून सुरू झालेली आयोगाची अधोगती इतकी तीव्र की आता संबंधितांस उत्तरपत्रिकांत छेडछाड करावी लागत नाही. आता प्रश्नपत्रिकाच फोडल्या जातात. म्हणजे पूर्वी एकटा-दुकटा अधिकारी शेण खात असे. आता ते सामुदायिकरीत्या खाऊन 'श्रावणी' साजरी केली जाते. परिणामी एक वर्ष असे जात नाही की ज्यात परीक्षा घोटाळा झालेला नाही वा होत नाही. शिवाय पेपरफुटी कमी म्हणून की काय चुकीचे प्रश्न, तपशिलातील गोंधळ इत्यादी अनागोंदी सोबतीला आहेच. त्यामुळे परीक्षार्थींत कमालीची खदखद असून तो रोष कधी आणि कसा व्यक्त होणार इतकाच काय तो प्रश्न आता उरलेला आहे. या विषयावर प्रक्षोभ टाळण्याचा शेवटचा मार्ग म्हणजे व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखालील हा कृतीगट.

पेपरफुटीचे कारण मुळापाशीच उखडून टाकणे, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करणे, कोणत्या पदाच्या किती जागा रिक्त आहेत, किती पदांवर नियुक्ती केली जाणे अपेक्षित आहे इत्यादी तपशील वेळच्या वेळी जाहीर करणे इत्यादी काही प्राथमिक शिफारशी या कृतीगटाने केलेल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. सध्या व्ही. राधा आणि समिती सदस्य राज्यभर दौरा करणार असून विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. पुण्यातील अशा चर्चेत १२ सप्टेंबरास सुमारे ६०० विद्यार्थ्यांनी या समितीसमोर आपले मन मोकळे केले. नंतर नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण, नाशिक अशा सर्व ठिकाणी हा कृतीगट विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल. त्याची गरज होती. कारण सत्ताधीशांस आज विद्यार्थ्यांसाठी वेळ नाही. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे सत्ताधीश कंत्राटे देण्याचे नवनवीन मार्ग शोधण्यात मग्न असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्याकडे वेळ असणार तरी कसा, हेही खरेच. आता तर सणासुदीचा काळ. आपल्या चेल्याचपाट्यांस खूश करण्यासाठी गल्लोगल्लीतील मंडळांस वा मंडपांत भेटी देण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य या सत्ताधीशांस पार पाडावयाचे असल्याने विद्यार्थी हिताकडे दुर्लक्ष होणे साहजिक. अशा परिस्थितीत या संदर्भात दुसरा उत्तम पर्याय म्हणजे व्ही. राधा यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी सुपूर्द करणे. तशी ती सुपूर्द करून फडणवीस यांनी एक पाऊल पुढे टाकले.

> महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात वरवरच्या मलमपट्टीने सुधारणा होतील ही अपेक्षा बाळगण्याचा काळ कधीच सरला. आयोगातील भ्रष्टाचाराच्या कर्करोगावर आता शस्त्रक्रियाच हवी...

पण त्याने भागणारे नाही. या कृतीगटास लोकसेवा आयोगाची अंतर्बाह्य साफसफाई करण्याचे सर्वाधिकार देण्याची गरज असून त्यापाठोपाठ त्यांच्या शिफारशींची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे अगत्याचे आहे. वरवरच्या मलमपट्टीने लोकसेवा आयोगात सुधारणा होतील ही अपेक्षा बाळगण्याचा काळ कधीच सरला. या आयोगात शिरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कर्करोगास आता शस्त्रक्रियाच हवी. मूळ देह वाचवावयाचा असेल तर कधी कधी किडका अवयव काढून टाकावा लागतो. लोकसेवा आयोगाबाबत ही वेळ आली आहे. परीक्षा पद्धती, तीमधील पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव, खासगी कंपन्यांहाती दिलेला मतलबी व्यवहार इत्यादी अनेक कारणे या अनागोंदीमागे आहेत आणि ती अनेकदा नमूदही केली गेली आहेत. म्हणजे आता निदानाची गरज नाही. निदान खूप झाले. आता कडक उपचार हवेत. त्यातील एक भाग म्हणजे राज्य शासनाशी संबंधित सर्व नेमणुका या लोकसेवा आयोगामार्फतच व्हाव्यात हे बंधनकारक करणे. हे केवळ सरकारी-निमसरकारी आस्थापनांबाबतच होता नये. तर शासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील नेमणुका/नियुक्त्याही लोकसेवा आयोगामार्फतच केल्या जाव्यात. याचे कारण असे की अनेक राजकारणी हे शिक्षण-माफिया बनले असून एका बाजूने सरकारी अनुदाने लाटायची आणि दुसरीकडून नियुक्त्याही देवाण-घेवाणीवर करायच्या असा हा दोन्ही बाजूंनी मलिदा खाण्याचा त्यांचा उद्योग वर्षानुवर्षे बिनबोभाट सुरू आहे. तथापि आता मात्र पाणी डोक्यावरून गेले असून योग्य पावले उचलली नाहीत तर राज्य तरण्याची सुतराम शक्यता नाही.

योग्य पावलांचा प्रारंभ हा योग्य व्यक्तींची योग्य स्थानी निवड करण्यापासून होतो. राज्य लोकसेवा आयोगावरील गेल्या काही वर्षांच्या नेमणुका म्हणजे याला झाकावा आणि त्याला काढावा या धर्तीच्या आहेत. अलीकडे सत्ताधीश वा प्रभावशाली व्यक्ती यांच्यासमोर न झुकणारे तसे विरळच झाले आहेत. जे कोणी तसे असतील त्यांस अभय देऊन त्यांच्याकडून अधिकाधिक निष्पक्ष कर्तव्य करवून घेण्याचे चातुर्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवावे. अडचणीचा क्षण हा सुधारणा रेटण्याचा उत्तम मुहूर्त असतो. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी १९९१ साली घेतलेले निर्णय हा याचा उत्कृष्ट नमुना. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यापासून प्रेरणा घेत लोकसेवा आयोगाची बहुप्रतीक्षित साफसफाई करून घ्यावी. त्यासाठी हीच वेळ आहे. आपल्या कारकीर्दीतील हा 'राव'क्षण फडणवीस यांनी वाया दवडू नये. कारण अशी संधी पुन्हा मिळणार नाही.

शासनाने जावे विद्यार्थ्यांच्या दारी...

लेख

मिलिंद मुरुगकर
आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक
milind.murugkar@gmail.com

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पाहणी करण्यासाठी जातील तेव्हा माध्यमे त्यांची दखल घेणार हे आता अपरिहार्य आहे. आणि ही गोष्ट स्वागतार्हदेखील आहे. कारण आपण कितीही चौपदरी, आठपदरी रस्ते बांधले तरी देशातील शिक्षणाची आणि विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली नाही तर आपण विकसित देश प्रत्यक्षात होणे दूरच, पण विकसित होण्याचे स्वप्नही पाहू शकत नाही. या निष्कर्षाला भरभक्कम अर्थशास्त्रीय आधार आहे.

शिक्षणाचा मुद्दा देशाच्या विकासाच्या धोरणविषयक चर्चा विश्वात केंद्रस्थानी आणणे हे कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) मोठे योगदान आहे. ही गोष्ट दुसरा कोणताही विरोधी पक्ष करू शकला नसता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच अलीकडे त्याचे कारण सांगितले. ते म्हणाले की, समजा काँग्रेसने जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला असता तर आपण त्यांना विचारू शकलो असतो की तुम्ही सत्तेवर असताना काय केले... अर्थात ते पुढे म्हणाले की सीजेपी ही काँग्रेसचीच खेळी आहे. अगदी सुरुवातीला काँग्रेसने नाही पण काही काँग्रेस समर्थकांनी सीजेपीला संघ भाजपची खेळीदेखील ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण या 'कॉन्स्पिरसी' थियरीपलीकडील मुद्दा असा की सीजेपीने हाती घेतलेला शिक्षणाचा मुद्दा प्रभावी ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला राजकीय प्रतिसाद देणे हे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य आहे. पण मुख्यमंत्री त्यापलीकडे जाऊन अधिक खोलवरचा प्रतिसाद देऊ शकतील का ? असा प्रतिसाद जो राज्यातील प्राथमिक शिक्षणावर अल्पावधीत मोठा विधायक परिणाम करू शकेल? आणि तोदेखील राज्याच्या शिक्षणावरील तरतुदीमध्ये अगदी अत्यल्प वाढ करून?

'असर' हा देशातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल माहिती देणारा जगप्रसिद्ध अहवाल. २०२४ सालच्या या अहवालात ग्रामीण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाबद्दल खालील गोष्टी नमूद केल्या आहेत.

राज्यातील शासकीय शाळेत शिकणारी तिसरीतील फक्त ३७ टक्के मुलेच दुसरीतील धडा वाचू शकतात. फक्त ३१ टक्के मुले वजाबाकी करू शकतात. पाचवीत शिकणारी फक्त ५९ टक्के मुलेच दुसरीतील धडा वाचू शकतात. पाचवीत शिकणारी फक्त २८ टक्के मुलेच भागाकार करू शकतात. आठवीतील फक्त ३६ टक्के मुले भागाकार करू शकतात.

प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता इतकी खालावलेली असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षकांसमोर एका वर्गात समोर बसलेली मुले ही केवळ औपचारिकदृष्ट्याच त्या वर्गातील असतात. म्हणजे त्यांची शैक्षणिक पातळी ही वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ आठवीच्या वर्गामध्ये दुसरीची शैक्षणिक पातळी न ओलांडलेली मुले असतात. चौथीची शैक्षणिक पातळी न ओलांडलेली मुलेही असतात आणि पाचवीतील शैक्षणिक पातळी न ओलांडलेलीही मुले असतात. ती शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या पातळीवर असतात. परंतु शिक्षक मात्र त्यांना आठवीचा अभ्यासक्रम शिकवत असतात. त्यामुळे बहुतेक विद्यार्थ्यांना आपल्यासमोर काय सुरू आहे याचे आकलनच होत नसते. यावर उपाय म्हणजे मुले ज्या पातळीवर आहेत त्या पातळीवर जाऊन शिकवणे. पण प्रत्यक्षामध्ये असे घडत नाही. कारण मुले नापास होत नाहीत, ती वरच्या वर्गात जात राहतात आणि ती वरच्या वर्गात जात असली तरी त्यांची शैक्षणिक पातळी मात्र खालावलेलीच राहते. यावर प्रभावी उपाय म्हणजे विद्यार्थ्यांना ते ज्या पातळीवर आहेत त्या पातळीवर जाऊन शिकवणे. आणि असे केले तर त्यांच्या शैक्षणिक पातळीमध्ये अत्यंत कमी अवधीमध्ये मोठी लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते असा अनेक अभ्यास सांगतात.

> कॉक्रोच जनता पार्टीने 'स्कूल ठीक करो' ही मोहीम सुरू केल्यानंतर कधी नव्हे ते शिक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला हवा हा या हेतूने तमिळनाडूत, महाराष्ट्रात आधीपासूनच काहीएक काम सुरू आहे. शासनाने त्याला हातभार लावून ते व्यापक करणे गरजेचे आहे.

या संदर्भात तमिळनाडूने हाती घेतलेला उपक्रम महाराष्ट्रासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. कोविडमुळे शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी तमिळनाडूमध्ये एका उपक्रमाची आखणी करण्यात आली. त्याचे नाव होते 'इल्लम थेडी कल्वी'. म्हणजे 'शिक्षण तुमच्या दारी'. तमिळनाडू शासनाने दोन लाख स्वयंसेवकांना या कार्यक्रमाशी जोडले. त्यांनी दररोज तास ते दीड तास शाळा सुटल्यानंतर शिक्षण सुधार वर्ग घेतले. यासाठी त्यांना महिन्याला अवघे एक हजार रुपये इतके कमी मानधन दिले गेले. हे वर्ग शाळांच्याच आवारात भरायचे आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ते पूर्णपणे मोफत होते. २०२१ च्या अखेरीस सुरू झालेला हा उपक्रम २०२२ च्या सुरुवातीपर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विस्तारला की ३० लाखांहून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले.

'इल्लम थेडी कल्वी' हा तमिळनाडूतील उपक्रम कोविड काळातील शैक्षणिक तूट भरून काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.

अर्थतज्ज्ञ कार्तिक मुरलीधरन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार कोविड काळातील शैक्षणिक तूट भरून काढण्यात हा उपक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला. त्याने केवळ शिक्षणच दिले नाही, तर समता या मूल्याचे महत्त्वही वाढवले, कारण यात सहभागी होणारे बहुतांश विद्यार्थी सरकारी शाळांमधील होते. खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडे आधीच खासगी शिकवणीसारखी साधने असतात. कार्तिक मुरलीधरन म्हणतात की या कार्यक्रमाचा आर्थिक किफायतीपणा थक्क करणारा आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणाच्या बजेटचा फक्त दोन टक्के निधी यासाठी लागला. पण विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पातळीत ३० टक्क्यांहून अधिक सुधारणा झाली. राज्यातील नेहमीच्या शालेय शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत हा उपक्रम दहा पटींनी अधिक किफायतशीर होता.

या उपक्रमामुळे महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागात आणि सक्षमीकरणात मोठी भर पडली. कारण या स्वयंसेवकांमध्ये महिलांचा समावेश मोठा होता. या उपक्रमाने महिलांना त्यांच्या सोयीच्या वेळेत काम दिले आणि समाजात सन्मानही मिळवून दिला. या उपक्रमाची स्वयंसेवकांमधील लोकप्रियता मोजायची असेल, तर एकच संदर्भ पुरेसा आहे. तो म्हणजे दरमहा केवळ एक हजार रुपये मानधन असूनही एकेका जागेसाठी चार-चार अर्ज आले होते.

परिणामकारकता, किफायतशीरपणा, शिक्षणातील विषमता कमी करणे आणि महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर होणारा सकारात्मक परिणाम या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार करता 'शिक्षण तुमच्या दारी' हा केवळ कोविडचे नुकसान भरून काढणारा तात्पुरता उपाय राहू नये असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे, अभ्यासकांचे मत आहे. शाळा सुटल्यानंतरचा कायमस्वरूपी उपक्रम म्हणून याचे अनुकरण व्हायला हवे. हा उपक्रम सध्याच्या शिक्षकांना पर्याय नाही, तर त्यांना पूरक आहे आणि तो समाजाला शिक्षणाच्या प्रक्रियेत थेट सामावून घेतो.

तमिळनाडूच्या प्रकल्पापासून प्रेरणा घेऊन एमकेसीएल (MKCL)ने आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचा निधी वापरून असाच प्रकल्प सुरू केला आहे. तमिळनाडूच्या प्रकल्पापेक्षा 'विकास घर' हा त्यांचा प्रकल्प काही बाबतीत वेगळा असला तरी मूळ संकल्पना तशीच आहे. ती म्हणजे मुख्य शालेय शिक्षणाला हा प्रकल्प पूरक आहे. या प्रकल्पाचे निष्कर्ष अतिशय उत्साहवर्धक आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील १०० शाळांमध्ये हा प्रकल्प गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे होणारी मुलांची प्रगती, महिला स्वयंसेवकांमध्ये आलेला आत्मविश्वास या ठळकपणे जाणवणाऱ्या गोष्टी आहेत. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प आपल्या प्रयत्नांना पूरक आहे याची जाणीव शिक्षकांमध्ये वाढत चालली आहे आणि इतर शाळांमधून या प्रकल्पाला मागणी वाढते आहे. सुरुवातीला ५० शाळांमधे सुरू झालेला हा प्रकल्प शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या मागणीमुळे आता १०० शाळांमधे सुरू आहे.

पण या इतक्या मूलभूत पातळीवरच्या कामासाठी निधीची उपलब्धता शासनाकडूनच झाली पाहिजे. तरच तमिळनाडूप्रमाणे याचा परिणाम राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षणावर होईल. महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत. शासन या उपक्रमात सहभागी होऊ शकेल. त्यासाठी शासनाला फार खर्चही करावा लागणार नाही. आणि त्याचे परिणाम अल्पावधीत दिसू शकतील.

शिक्षण हा विषय राजकीय पटलावर केंद्रस्थानी आलेला असताना महाराष्ट्र शासनाचा त्याला हा एक स्वागतार्ह, विधायक प्रतिसाद ठरेल.

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

त्रिभाषा सूत्र फक्त महाराष्ट्रातच?

महाराष्ट्राच्या भूमीत येऊन 'महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे बहुभाषिक राज्य आहे' आणि 'हिंदी हा सर्व भारतीय भाषांना जोडणारा 'मध्यमणी' आहे,' असे शोध लावणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आणि व्यासपीठावर गप्प बसून मान डोलावणाऱ्या महाराष्ट्राच्या नेत्यांना ठणकावून विचारावेसे वाटते की हा महाराष्ट्राचा सन्मान आहे की मराठीच्या अस्मितेवर मारलेला दरोडा? गेल्या वर्षी पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा घाट घातला गेला. यंदा मावशीच्या नावाने आईचा गळा घोटण्याचा प्रकार उघडपणे सुरू केला आहे. मावशीचा आदर आम्ही नक्कीच करू, पण मावशीला घरात आणून आईलाच स्वयंपाकघराबाहेर काढायचा हा डाव महाराष्ट्रातील जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहते आहे. सर्व भारतीय भाषा समान आहेत, तर मग हिंदीच 'मध्यमणी' का? त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली बँका, रेल्वे, पोस्ट आणि केंद्र सरकारच्या सर्वच संस्थांमधून मराठीला हद्दपार केले गेले आहे. हे त्रिभाषा सूत्र फक्त महाराष्ट्रातच का? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यात तिसरी भाषा कोणती शिकवली जाते?

■ **आबासाहेब पाटील,** पुणे

हिंदीचा दुस्वास नको

'**महाराष्ट्र मोठे** बहुभाषिक राज्य : राजभाषा संमेलनात अमित शहा यांचे प्रतिपादन' हे वृत्त वाचले. केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांचे म्हणणे संयुक्तिक आहे. बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला मातृभाषा, राजभाषा (हिंदी) व ज्ञानभाषा (इंग्रजी) अशा किमान तीन भाषा चांगल्या प्रकारे लिहिता,वाचता, बोलता याव्यात अशी अपेक्षा राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने २००५ मध्ये व्यक्त केली होती, तीही योग्यच. राष्ट्रीय ऐक्यात हिंदी मोठी भूमिका बजावू शकते, त्यामुळे हिंदीला विरोधासाठी विरोध करणे योग्य नाही. दक्षिणेकडील हिंदीविरोध हा प्रामुख्याने मतपेढीच्या राजकारणामुळे आहे. मराठीचा आग्रह जरूर धरावा मात्र त्यासाठी हिंदीचा दुस्वास नको!

■ **डॉ. विकास इनामदार,** पुणे

दक्षिणेत हेच बोलाल?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नवी मुंबईत हिंदी भाषिक संमेलनाला आले, तेथे त्यांनी महाराष्ट्र हे बहुभाषिक राज्य आहे असे वादग्रस्त विधान केले! असेच विधान ते दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जाऊन करू शकतील का? मराठी माणूस सोशिक, संयमी व सर्वांना सामावून घेणारा आहे याचा अर्थ त्याला आपल्या भाषिक व प्रांतीय अस्मितेची काहीच चाड नाही असे कोणी समजून घेऊ नये. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा बघून तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही माघार घेतली होती.

■ **प्रवीण नारकर,** ठाणे

...तोवर आत्मघातकी ठरेल!

'**मिळतिल भूपाल** अमित...' हा अग्रलेख (१४ सप्टेंबर) वाचला. चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापार- तफावत जवळपास १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. चीनने आपल्यावर गलवानचा संघर्ष लादल्यानंतरही आपल्या बाजारातील चिनी वस्तूंची आवक वाढत राहिली. तरीसुद्धा 'ब्रिक्स' परिषदेत आपण म्हणतो की एकमेकांच्या सीमा एकमेकांच्या व्यापारासाठी सताड उघडा? खरे तर जोपर्यंत चीनच्या बाजारपेठेत स्थान मिळवण्याइतपत आपली कारखानदारी तगडी होत नाही तोपर्यंत व्यापारावरील नियंत्रणे उठवणे हे आपल्यासाठी आत्मघातकी ठरेल.

■ **प्रभाकर दगाजी वारुळे,** मालेगाव (जि. नाशिक)

काँग्रेस भाजपच्या गळास लागते!

'**जम्मू-काश्मिरात काँग्रेसच्या** भूमिकेचा भाजपलाच फायदा!' हा अन्वयार्थ (१४ सप्टेंबर) वाचला. 'वंदे मातरम' सारख्या भावनिक मुद्द्यांवर वाद घालून त्यावर आपली भाकरी भाजून घेणे नेहमीच भाजपसाठी फायद्याचे व काँग्रेससाठी अपायकारक ठरले आहे. अशा मुद्द्यांवर भाजप बाजी मारून जाते व काँग्रेस त्यांच्या गळाला लागते. या वादांमुळे मूळ मुद्दे बाजूला राहतात व राजकीय खेळींमुळे लोकांचे लक्ष विचलित होते. यातून राजकीय ध्रुवीकरण घडवून आणण्याची भाजपला सुवर्णसंधी मिळते. जम्मू-काश्मीरसारख्या आधीच वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या राज्यात हा वाद अधिकच फोफावतो आणि भाजपचा डाव पुन्हा यशस्वी होतो.

■ **सरिता पोटे,** अहिल्यानगर

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कोणाला?

विश्लेषण

सुहास सरदेशमुख
suhas.sardeshmukh@expressindia.com

> मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे तयार झालेल्या मतपेढीचा भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला होता. त्यावर मात करण्यासाठी मग 'लाडकी बहीण' योजना आली. आता पुन्हा सुरू झालेल्या जरांगे यांच्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कोणाला होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे पुन्हा मतपेढी निर्माण होईल?

२०१४ पासून मराठा आरक्षण हा विषय चर्चेत आहे. गेल्या तीन वर्षांत मराठा आरक्षण आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे यांनी ११ वेळा आणि आजपर्यंत ९६ दिवस उपोषण केले. जरांगे यांच्या आंदोलनाकडे सरकारने नेहमीच मराठा मतपेढीचा प्रभावक म्हणून पाहिले. परिणामी, मागण्यांच्या पातळीवर जरांगे म्हणतील तसे, अशीच सरकारची भूमिका राहिली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जरांगे यांच्या आंदोलनातून मराठा - मुस्लीम आणि दलित अशी मतपेढी तयार झाली होती. त्याचा गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला लाभ झाला.

विधानसभा निवडणुकीत काय परिणाम झाला?

विधानसभा निवडणुकीमध्ये ज्यांना मतदान करायचे त्यांना करा, अशी जाहीर भूमिका जरांगे यांनी घेतली होती. प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांना मराठा मतपेढीचा लाभ झाला. याचा ओझरता उल्लेख जरांगे यांनी त्यांच्या ११ व्या उपोषणादरम्यान केला. यातून मतपेढीची राजकीय ताकद घेऊन आरक्षण मागणीतील त्रुटी दूर करण्याच्या मागण्या ते करत आहेत. हे सारे करताना सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य करायचे आणि सत्तेतील शिवसेनेला जवळ करायचे, अशी रणनीती होती. लोकसभेत जरांगे आंदोलनाने निर्माण केलेल्या मराठा - मुस्लीम - दलित मतपेढीवर महिला मतपेढीने मात केली होती. आता पुन्हा नव्या मतपेढीची शक्यता आहेच.

जरांगे आंदोलनातून मराठा समाजाला काय मिळाले?

मराठा जातीचे वर्चस्व असणाऱ्या राज्यातील ८२ मतदारसंघांमध्ये आणि आरक्षित ५४ पैकी ३६ मतदारसंघांत गणित जुळवून आणून 'मराठा शक्ती'चा प्रयोग करण्याच्या हालचाली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ठरविण्याच्या सुरू होत्या. मात्र, हे करताना जरांगे आंदोलनातून मराठा समाजाला बरेच काही मिळाले. पहिल्या काही आंदोलन हाताळणीमध्ये स्वतः तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. परिणामी न्या. शिंदे समिती स्थापन झाली. पुढे या समितीने कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या ऐतिहासिक नोंदी शोधण्याचे मोठे काम केले. नोंदी सापडलेल्या आणि अर्ज करणाऱ्या तीन लाखांहून अधिक जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली. परिणामी, यातील काही जणांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच नगरपालिका निवडणुकीमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवता आली. याशिवाय हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याचा शासननिर्णय काढण्यात आला. यामुळे प्रत्येक आंदोलनातून एकेक पाऊल पुढे सरकत आंदोलनास यश मिळत गेले. परिणामी, ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्यातून आरक्षणाचा लाभ मिळाला ते सारे जरांगे समर्थक 'मतपेढी' म्हणून वावरत असतात.

आंदोलनाकडे मराठा नेते कसे पाहतात?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जरांगे आंदोलनाचा मोठा फटका भाजपला बसला होता. त्यामुळे या आंदोलनापासून भाजप नेते चार हात दूरच होते. पण मराठवाड्यातील भाजपचे १९ आमदार आहेत. यापैकी जवळपास १२ आमदार मराठा आहेत. पण आंदोलनाकडे हे आमदार फिरकले नाहीत. मात्र, विरोधी पक्षातील आमदारांनी मात्र आवर्जून हजेरी लावली. संख्येने मोठ्या असणाऱ्या या समाजाची घोषणाही 'एक मराठा लाख मराठा' अशी आहे. ती संख्यादर्शक शक्ती दाखवते. यामुळे मतपेढी म्हणून मागण्या मान्य होतात, असेच चित्र आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळेच गावोगावी जातीची प्रमाणपत्रे वितरित करण्याची शिबिरे सरकार घेत आहे.

आता आंदोलनाचे वळण बदलेल का?

जरांगे यांना आंदोलनापासून रोखता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आणि जरांगे यांनी आंदोलनाची दिशा मुंबईकडे वळवली. पण आंदोलन करण्याची परवानगी पोलिसांनी नाकारली. आता मोजक्या लोकांसह जरांगे यांनी मुंबईला जाण्याचे नियोजन जाहीर केले आहे. तत्पूर्वी सरकारही जरांगे यांच्याशी पुन्हा बोलणीची तयारी करत आहे. पुन्हा प्रश्न आहे तो मराठा मतपेढीचा. त्यामुळेच दबाव आणि पोलीस वापरून पुढे जाता येणार नाही, हे सरकार आणि जरांगे या दोघांनाही पूर्ण माहीत आहे. ब्राह्मण मुख्यमंत्री आणि सततची मराठा आंदोलने यात बहुतांश गणित राजकीय होतेच आणि आजही ते आहेच. मात्र, जाट, पटेल आंदोलने हाताळणाऱ्या भाजपला जरांगे प्रकरण नाजूक हातानेच हाताळावे लागेल. आरक्षण मागणीला शेतीप्रश्नाची गुंतागुंतही जोडलेली आहे. शेती उत्पादकांमध्ये असणारी खदखद वाढतच जाते आहे. वर्गाचे प्रश्न जातीचा मुखवटा घेऊन येतात आणि त्याचे उत्तर आरक्षण आहे, हे आता रुजले आहे. त्यामुळे आंदोलन हाताळणीचे वळण फारसे बदलणार नाही, असेच दिसते. यात तुम्ही जिंकलात असे म्हणायचे आणि मराठा नेतृत्वाने गुलाल उधळायचा, ही कार्यपद्धती पुन्हा एकदा अनुसरली जात जाईल.

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

📍EnglishEditorialsPDF with International Newspapers Editorials [35-40pages]

📍 Hindi Editorials PDF

📍 Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International [Genaral & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world. Asian, Europian & American

Hindi Newspapers

1) दैनिक जागरण
2) जनसत्ता
3) हरिभूमि
4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

Click Here